हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 11 मार्च, 1980

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(7)28
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)31
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग– रूल 116 के अधीन या अन्यथा कार्यवाही से हिस्से या हिस्सो को निकालने के अध्यक्ष के विवेकाधिकार संबंधी।	(7)32
ध्यानाकर्शण सूचना– रोडी तथा सिरसा डिवीजनो के लिये टोहाना हैड से पानी की कम सप्लाई संबंधी	(7)34
वक्तव्य– सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना	(7)35

संबंधी	
बिल्ज (इन्ट्रोडयूरेड सदन की अनुमति से)	(7)38
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980	(7)38
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैं ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)39
दि पंजाब लैन्ड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)39
दी हरियाणा वेलीडे ान आफ आक्ट्राय एण्ड, सरचार्ज बिल, 1980	(7)40
दी हरियाणा म्यूनिस्पिल (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)40
दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)41
दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)42
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) सैकिण्ड अमैंडमैंट बिल, 1980	(7)42
दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)43
दि पंजाब प्रोहिब ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट)	(7)43

बिल, 1980	
दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किक्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980	(7)47
वर्श 1979–80 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पर चर्चा (i) राज्य के राजस्वो पर प्रभारित अनुमानो पर चर्चा (ii) अनूपूरक अनुमानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(7)47
वैयक्तिक सपश्टीकरण– चौधरी गंगाराम द्वारा	(7)84
वर्श 1974–75 के एक्सैस डिमाडंज ओवर ग्रांटस एण्ड एप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान।	(7)84

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ मे प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, सवाल होंगे।

Cooperative Sugar Mill at Kaithal

***1457 Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Cooperation be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill at Kaithal; if so, the time by which it is likely to be set up?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): जी नही।

चौधरी राम लाल वधवाः मैं मंत्री महोदय से जाना चाहता हूं कि जब चीनी की भाोर्टेज जनता सरकार के वक्त मे

नही थी तो कांग्रेस (आई) की सरकार आते ही चीनी की भौर्टेज क्यो हो गई ?

इाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, इस सप्लीमंटरी का सवाल से कोइ संबध नही है। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवरः मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरियाणा सरकार ने सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखकर भेजा है. .....

श्री अध्यक्षः यह सवाल भूगर मिल कैथल से ताल्लुक रखता है।

चौधरी संत कंवरः मैं भी भूगर मिल के बारे मे ही सवाल पूछ रहा हूं । स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि हरियाणा मे और भूग मिल लगाने की जरूरत है ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, वैसे जो चौधरी संत कंवर के सप्लीमैंटरी सवाल से कोई संबंध नही है क्योंकि यह सवाल कैथल के बारे मे है। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं हाउस की तसल्ली के लिये इसका जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, चौधरी संत कवर ने पूछ है कि क्या हरियाणा सरकार के केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि प्रांत मे और भूगर मिले बढ़ाई जाये। मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पहले हमने दो भूगर मिल्ज, एक पलवल और दूसरी भााहबाद के लिये

सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखा था। वह केस अभी पैंडिग है, उसकी मंजूरी नही आई है। फिर हमने पांच भूगर मिल और लगाने के लिये केंद्र को लिखा। केन्द्र ने एक एक सर्वे कमेटी हरियाणा मे भूगर मिल लगाने के प्रौसपैक्टस देखने के लिये भेजी। उस कमेटी ने यहां का दौरा किया और देखा कि क्या यहां पर पांच और भूगर मिल लगाई जा सकती है लेकिन उन कमेटी ने कोई फेवरेबल प्रौसपैक्टस नही पाये । पांच भूगर मिल लगाने की प्रोपोजल श्री बरनाला ने रिजैक्ट कर दी और कहा कि पिछले साल हमारी स्टेट मे और सारे मूल्क मे भूगर बहुत ज्यादा पैदा हुई है इसलिये इस चीज को देखते हुए कोई भूगर मिल नही लगाई जा सकती। इस तरह से स्पीकर साहब, श्री बरनाला ने हरियाणा मे पांच भूगर मिल लगाने की हमारी प्रोपोजल रिजैक्ट कर दी है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपने कैथल मे यह आ वासन नही दिया था कि यहां पर भूगर मिल बनाई जायेगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैने ऐसा कोई आ वासन नही दिया था कि कैथल मे भूगर मिल लगायेंगे। मैंने एक पब्लिक मीटिंग मे यह कहा था कि हमने भारत सरकार को पांच भूगर मिल लगाने के लिये लिखा था। उसमे कैथल का नाम भी भारत सरकार ने पांच मिलों की प्रोपोजल नही मानी है। इस मामले को हम फिर टेक अप करेंगे अगर भारत सरकार मान गई तो हम जरूर भूगर मिल लगायेंगे।

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, क्योंकि यह सवाल कैथल के बारे मे है मैं इसे और क्लीयर कर देता हूं । कैथल मे इस ाूगर मिल को बनाने के लिये एक सोसायटी 3–6–1970 को रजिस्टर हुई थी। इस सोसायटी ने सैंट्रल गवर्नमैंट के डायरैक्टर आफ फूड एंड सप्लाइज को एक ऐपलीके ान दी कि हमे कैथल मे भाूगर मिल लगाने की इजाजत दी जाये। उस सोसायटी ने ऐप्लीके ान डायरैक्ट ही वहां भेज दी थी लेकिन उन्होंने इस प्रोपोजल को रिजैक्ट कर दिया अऔर यह कहा कि इस एरिया मे इतना गन्ना नही कि यहां पर एक भाूगर मिल लगाई जाये। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि मैंने कोई आ वासन नही दिया कि कैथल मे भाूगर मिल लगाई जायेगी। सैंट्रल गवर्नमैंट ने इस ऐरयिा का सर्वे एक कमेटी द्वारा करवाया था ओर सारे प्रोसपैक्टस देखकर भाूगर मिल लगाने की प्रोपोजल रिजैक्ट कर दी है।

श्री रघूनाथ गोयलः स्पीकर साहब, कैथल मे भाूगरमिल लगाने के लिये अढाई लाख रूपये के भोयर बेचे गये और मुख्य मंत्री महोदय ने हवां पर यह आ वासन दिया था कि कैथल मे भाूगर मिल लगाई जायेगी लेकिन आज ये कहते है कि मैंने कोई आ वासन नही दिया था।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने कोई आ वासन नही दिया थां

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, अढ़ाई लाख रूपये के भोयर नही बिके थे। सिर्फ 57 हजार के भोयर्ज 30–6–1979 तक सोसायटी ने बेचे थे।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल ने जींद मे एक पब्लिक मीटिंग मे यह कहा कि जींद मे एक भूगर मिल लगायी जायेगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब भी हरियाणा मे कोई भूगर मिल लगाई जायेगी क्या वह सबसे पहले जींद मे लगाई जायेगी जिससे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी अ योरेंस को पूरा किया जा सके ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल भूगर मिल कैथल के बारे मे है, जींद के साथ इस सवाल का कोई संबंध नही है।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, अभी बताया गया है कि हरियाणा मे पांच भूगर मिल के लिये भोयर बेचे गये थे। अध्यक्ष महोदय इसी तरह से पलवल मे भी मैंने पांच लाख रूपये के भोयर बिकवाए थे लेकिन अभी तक वहां पर कोई भूगर मिल नही लगाई गई हैं क्या मंत्री महोदय उन भोयर्ज को वापिस करवाने की कृपा करेंगे ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि पलवल और भााहबाद मे भूगर मिल लगाने की प्रोपोजल

गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास भेजी गई थी और वह अंडर कंसिड्रे ान है। अभी तक वह प्रोपोजल रिजैक्ट नही हुई है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, कैथल की भूगर मिल चौधरी बंसी लाल की सरकार के समय मे मंजूर की गई थी और लाखो रूपये के भोयर भी खरीदे गये थे लेकिन बदकिस्मती से एक साहब, जिसका मैं नाम लेना चाहता, मिल मिलाकर और हेराफरी करके उसको करनाल ले गये। स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि वहां पर इतना गन्ना नही होता कि भूगर मिल लगाई जा सके। यह बात ठीक नही है। वहां पर गन्ने की हालत यह है कि दो साल तक तो हम लाखो क्विंटल गन्ना जलाते रहे है। वहां पर गन्ने की कोई कमी नही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कैथन के लिये सेंट्रल गवर्नमैंअ भूगर मिल लगाने की इजाजत नही देती है तो हरियाणा सरकार अपने लैवल पर कोई भूगर मिल लगाने की वजबीज पर गौर करेगी ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि इन्होने बताया कि लाखो रूपये के भोयर खरीदे गये। यह ठीक बात नही है। सिर्फ 57 हजार रूपये के भोयर 30—6—1979 तक बेचे गये थे ये भोयर एक सोसायटी के थ्रू बिके थे और वह सोसायटी एक रजिस्टर्ड सोसायटी थी। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि दो साल लाखों क्विंटल गन्ना हम जलाते रहे है। स्पीकर साहब, ऐसा मालूम होता है कि जब गवर्नमैंट आफ इंडिया की सर्वे कमेटी आई

थी, उसके आने से पहले ही वह गन्ना इन्होने वहां जला दिया होगा इसलिये वह कमेटी उस गन्ने को देख नही पाई। मैं फिर सदन को बताना चहाता हूं कि उस कमेटी ने गन्ने की कमी की वजह से ही कैथल मे मिल लगाने की प्रोपोजल रिजैक्ट कर दी थी।

Rise in Price of Sugar

***1542. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether it is in the notice of the Government that there has been steep rise in the price of sugar in the open market during the last three months; and

(b) if so, the steps, if any taken or proposed to be taken to bring down the price of sugar in the open market?

Food and Supplies Minister: (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):

(a) Yes.

(b) The Government of India have taken the following measures to tide over the situation:-

(i) Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 issued on 17-12-79 introducing partial control on sugar for distribution of levy sugar to consumers at the fixed retail rat of Rs. 2.85 per kilogram.

(ii) Levy (Restriction on Movement) Order, 1979 issued on 17-12-79 banning transport of sugar from one State to another.

(iii) Reduction in the stocking limits of sugar by licensed dealers from 500 quintals to 250 quintals in towns with population from one lac to 5 lacs and from 250 quintals to 100 quintals in towns with population of less than one lac from 26-2-80.

(iv) Validity period of uplifted quota of sugar form December, 1979, January, 1980 and February, 1980 has been extended till 31-3-1980.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जो स्टैप्स राज्य सरकार ने उठाये है, उन से सरकार का मसला हल हो जायेगा ? दूसरी बा यह है कि भारत सरकारने जिस तरह से पए उठाये है, क्या राज्य सरकार भी उसी तरह के पग उठाने का विचार रखती है ताकि राज्य मे स्थिति समान्य हो जाये ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जो स्टैप्स भारत सरकार ने इस मसले को हल करने के लिये उठाये है, उन पर हम फौरी तौर पर अमल करते है और उनको फौरी तौर पर ही लागू भी करत`है। उसके साथ साथ मै यह भी बता देना चाता हूं कि सरकार ने जो स्टैप्स उठाये है, उनसे काफी मात्रा मे छिपाई गई चीनी बाहर आयी है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने 'बी' पार्ट के पहले भाग मे यह कहा है कि ''उपभोक्ताओ को 2.25 पैसे प्रति किलोग्राम की नि चत दर पर लैवी चीनी बेचने के लिये 17–12–79 से चीनी पर आं ाक कन्ट्रोल किया गया तथा लैवी भूगर सप्लाई कंट्रोल आर्डर, 1979 जारी किया गया''। स्पीकर साहब, यह तो आर्डर 17–12–79 को हुआ, यह इतना इल्लीगल और डिफैक्टिव था, जिसके कारण से दो महीने से ही चीनी मे इतनी तेजी आ गई और लोगो को काफी परे ाानी हुई। क्या इल्लीगल6 और डिफैक्टिव कानूनो को लागू करना ही एस तेजी का कारण है ? (ाोर एंव व्यवधान)

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, यह कानून बिल्कूल इल्लीगल और डिफैक्टिव नही है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं आपरेबल मैंबर साहेबान से कहूंगा कि वे इस बारे मे अपने एम.पी. से मिले (ाोर एवं व्यवधान) The hon. Member says that the law is illegal and defective. I would request the Hon'ble Minister to please clarify it.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, इसी कानून के लागू होने के कारण ही हरियाणा मे व्यापारियों ने इस का बड़ा फायदा उठाया ओर लोगो को परे ाानी हुई (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, इस बारे मे मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा। मैंने पहले भी बताया है कि कोई ऐसा डिफैक्टिव कानून नही है जो सरकारा ने लागू किया हो

और जिसका फायदा व्यापारियों ने उठाया हो। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः क्या इसकी इम्पलीमैंटे ान स्टेट मे ठीक तरह से हो रही है ? (ाोर)

Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar: Yes, Sir. The Govt. of India are within their right to0 put these restrictions. It is for the Govt. of India to decide and not for the State Government.

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब हयह है कि जो रिस्ट्रिक ान आन मूवमैंट आर्डर, 1979 लागू हुआ है, वह गलत है। लोगो को इससे दिक्कत हुई और वे हाई कोर्ट से चले गये। हाई कोर्ट से उन्हे स्टे आर्डर मिल गया। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि इस बारे मे दोबारा भारत सरकार को लिखा जायेगा कि इस कानून को बदला जाये ? अभी यह इम्पलीमैंट भी नही हो पा रहा है । (ाोर)

श्री अध्यक्षः क्या यह कानून अभी इम्पलीमैंट नही हुआ है

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, हो ही नही सकता और नही हुआ है। यह कानून बिल्कुल गलत है। (ाोर एंव व्यवधान) स्पीकर साहब, उनकी काम चलाऊ सरकार थी, कानून बनाते समय सोचा नही, इसी लिये भाूगर के भाव मे तेजी आयी

है। अगर सही तरीके से कानून बना दिया जाता तो इतनी तेजी न आती।

Mr. Speaker: The hon. Members appear to be quite agitated on the subject. Therefore, I would request the Government to examine this question in detail.

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी एक आनरेबल मैंबर श्री मांगे राम गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा जो कानून लागू किये गये है, वे सभी इल्लीगल और डिफैक्टिव है और लोगो को हाई कोर्ट मे इसके विरूद्ध स्टे भी मिल चुकी है दूसरी तरफ मिनिसटर महोरदय फरमा रहे है कि यह कानून इल्लीगल और डिफैक्टिव नही है। इसलिये आपके द्वारा मैं मिनिस्टर साहब से यह कहूंगाा कि इस बारे मे वे जरा पोजी ान क्लियर कर दे।

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है हाई कोर्ट का कोई इंटरवें ान नही है। There is no intervention from the High Court side. दूसरी बात यह है कि 65 परसैंट लैवी की चीनी ली जाती है और तमाम स्टेटस को सैंटर की तरफ से कोटे के मुताबिक डिस्ट्रिब्यू ान होती है और जितनी जितनी हमे चीनी केन्द्र सरकार की तरफ से मिलती है, उसके हिसाब से हमे डिस्ट्रिब्यू ान करते रहते है।

श्री अध्यक्षः मोटी बात तो यह है कि लैवी की भाूगर 2.85 पैसे पर किलो मिल रही है कि नही ? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गजराज बहादूर नागरः जी हां, मिल रही है, जो कोटा आता है, उसकी 2.85 यपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से डिस्ट्रिब्यू न की जा रही है। मेरी इत्तलाह के मुताबिक या किसी एक भाुग मिल ने या किसी ने डंडीविजुअल लैवल पर पैटी ान जरूर दायर कर रखी है लेकिन हाई कोर्ट की उसमे कोई इंटरवें ान नही है और न ही कोई स्टे है। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Since the hon. Members appear to be quite agitated, I would once again request the Government to examine this question in detail.

श्री जयनारायण वर्माः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने जो कानून बनाये है, उन से छिपी हुई चीनी बाजार मे आ रही है। क्या वे बताने का कश्ट करेंगे कि जितनी चीनी बाजार मे आई है उसकी मात्रा कितनी है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, इसके लिये अलग से नोटिस चाहिए।

श्री मूलचंद जैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि सिचुऐ ान को ईज करने के लिये स्टैप्स उठाये गये है। मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि जो स्टैप्स, सिचुऐ ान ईज हो जायेगी ? अगर नहीं तो क्या सरकार इस बोरे मे केन्द्र सरकार से कोई इफैक्टिव स्टैप्स उठाने के लिये कहेगी ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, जो स्टैप्स सरकार ने उठाये है, वे बड़े इफैक्टिव है। उनसे डिपो होल्डर्ज किसी प्रकार से स्टाक नही कर सकेंगे और आगे के लिये इससे भी ज्यादा इफैक्टिव स्टैप्स सरकार उठाने का विचार रखती है।

Mr. Speaker: As a layman, I can also see that this is an anti hoarding measure.

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि किसी किस्म का कोई स्टे नही मिला है, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज हुआ था चाहे डीलर के खिलाफ, चाहे कंज्यूमर के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ क्या वे इस बात को क्लियर करेंगे कि ऐसा कोइ मामला उनके विचर मे आया है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, सवाल Sta of enforcement of the order regarding levy sugar. के बारे मे है। मैंने यह कहा कि लैवी भूगर के बारे मे कोई स्टे नही मिला हुआ। अगर कोई ऐसी बात है या कोई पैटी ान होगी तो किसी इंडीविजुअल की होगी या किसी डीलर की होगी and not concerning the functioning of this order.

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister for Cooperation & Planning wants to say something.

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, मैं क्लियर कर देता हूं क्योकि भूगर मिल्ज का मामला मेरे

से संबंधित है। 4917.9 टन का लेवी भूगर का कोटा मन्थली जो हमारी स्टेट को मिलता है, उसी कहसाब से हम उसकी डिस्ट्रीब्यू ान कर रहे है।

श्री अध्यक्षः मतलब यह है कि इस की डिस्ट्रीब्यू ान कोआप्रटिव डिपार्डमैंट के थ्रू हो रही है।

श्री फतेह चंद विजः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मिनिस्टर सहाब से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो स्टैप्स उठाये गये है, वक कब लागू हुए और इसके लागू होने से रेटस मे कोई उतार चढ़ाव आया है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, रेटस मे कोई फर्क नही है। 2.85 रूपये के हिसाब से हम लैवी की भूगर लोगा को दे रहे है।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हम रोजाना अखबारों मे पढ़ते है कि सारे राज्य मे जमाखोरी करने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है और कई स्थानो पर छापे भी मारे जा रहे है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि सारी स्टेट मे ब्लैक मार्किट करने वालों और जमाखोरी करने वालो की तादाद कितनी है जिनके खिलाफ सरकार ने रेडज वगैरह किये हो और कोई और कदम उठाया हो ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बाजह किया था कि पहले भी यह वाजह

किया था कि टोटल कितने केसिज रजिस्टर हुए । उन्होनें इस हाउस मे बताया था कि 300 केसिज मे से 206 केसिज रजिस्टर किये गये और भूगर के मामले मे ही रेडज नही किये गये बल्कि डीजल, कैरोसिन आयल और दूसरी एसैि ायल कामोडिटीज की जो बस्तुएं है, उनकी सप्लाई कराने के लिये भी बड़े कड़े पग उठाये गये है और इस बारे मे पुलिस मे भी काफी केसिज रजिस्टर हुए है।

श्री अध्यक्षः उनका सवाल यह है कि भूगर होडिंग के बारे मे कोई रेड्ज हुए है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, रेड्ज तो जरूर हुए है लेकिन इस समय मैं एग्जैक्ट फिग्गर नही दे सकता। उसके लिये सैपरेट नोटिस देंगे तो बता दिया जायेगा।

चौधरी संत कंवरः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि पांच हजार की आबादी वाले इलाको मे भूगर का कोटा 50 क्विंटल से घटा कर 250 क्विंटल कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे यह बात है कि इस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे मिल चुकी है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः स्पीकर साहब, हमारे नोटिस मे ऐसी कोई बात नही आई है ?

चौधरी रिजक रामः अभी मंत्री महोदय फरमा रहे थे कि छिपी हुई चीनी बाहर आ गई है लेकिन वे यह नही बता सके कि

कितनी चीनी बाहर आई। जब इनको रेड्ज के बारे मे पता नही कि कितने रेड्ज हुए तो यह किस आधार पर कह रहे है कि चीनी बाहर आई है ?

चौधरी गजराज बहादूर नागरः पहली चीनी के भाव ऊंचे होते जा रहे थे, उसकी निस्बत अब कुद नीचे आए है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय इसके बारे मे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अभी चौधरी रिजक राम और कुछ दूसरे माननीय सदस्यो ने पूछा कि छिपी हुई चीनी कितनी बाहर आई। जैसे ही चीनी की हद मुकर्रर हुई, हम हद से ज्यादा जितनी चीनी किसी के पास थी, वह बाहर ले आयें उस चीनी अवेलेबल हो सके और रेट भी कुद कम हो सके। पिछले 15 दिनों से फ्री सेल चीनी के रेट 50 पैसे किलो के हिसार से कम भी हुए है। पहले चीनी साल रूपये किलो तक पहूंच गई थी लेकिन अब चीनी का भाव 6 रूपये किलो है यानी 50 पैसे से लेकर एक रूपये तक स्टाक पर पाबंदी लगाने से चीनी के भाव कम हुए है (ाोर)।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी बोल रहे है आप भाांति से सुने। रोला मचाने का फायदा नही ।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, चीनी के बारे मे जो सब से बड़ी दिक्कत आई वह यह थी कि केन्द्र मे लोक दल की

सरकार ने चीनी के बारे मे जो नीति निर्धारित की उसकी वजह से चीनी के भाव बढ़े। (ाोर)

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर सहब से पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी के भाव लैवी सिस्टम लागू होने के बाद बढ़े है ? मिल वालो की बहुत बड़ी लाबी है, वे नही चाहते कि लैवी सिस्टम लागू हो। क्या मंत्री जी भारत सरकार को लिखेंगे कि लैंवी सिस्टम खत्म किया जाये ?

चौधरी भजन लालः हम यह मामला भारत सरकार के साथ टेक अप करेंगे हमारी पूरी कोि ा ा होगी कि गरीब आदमी को ठीक भाव पर चीनी मिले।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, 17—12—79 का जो आर्डर है वह सरकार ने इम्पलीमेंट किया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 17—12—79 को व्यापारियों के पास जो चीनी का स्टाक था वह आपने ओपनिंग स्टाक के हिसाब से लिया या कलोजिंग स्टाक के हिसाब से लिया ?

श्री अध्यक्षः मेरा ख्याल है कि इसके लिये तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चीनी का स्टाक कम करने का जो आर्डर पास हुआ उससे सरकार ने स्टाकिस्टस से कितनी चीनी अपने कब्जे मे ली ?

श्री अध्यक्षः उस चीनी को कब्जे मे लेने का सवाल नही है वह तो मार्किट मे आ गई।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री और मंत्री जी के ब्यानो मे फर्क है। मंत्री जी तो कहते है कि हमने छापे मार कर चीनी पकड़ी और ये कहते है कि बिल्कुल नही पकड़ी । तो कौन सी स्टेटमैंट ठीक है । (ाोर)

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी हुकम सिंहः अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जो दूकानदार पहले 1000 क्विंटल चीनी रख सकता था वह अब 500 क्विंटल चीनी रख सकेगा। तो क्या मंत्री जी ने नोटिस मे यह बात है कि वह चीनी बाजार मे नही आई है बल्कि उसको देहातो मे ले जाकर छिपा दिया गया है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने नही है। लेकिन यह जरूर है जैसे मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जिनके पास 1000 हजार क्विंटल का स्टाक था वह 500 क्विंटल रह गया और बाकी जो 500 क्विंटल था वह ओपन मार्किट मे भेज दिया गया।

श्री अध्यक्षः इससे मैं यही अंदाजा लगाता हूं कि मैंबर साहिबान इस मामले पर बड़े एजीटेटिड है इसलिये मैं सरकार को सिफारि ा करूंगा कि वह अपनी विजीलैंस और दूसरी एजैंसीज से

भूगर होर्डर्ज पर और ज्यादा रेड करवाएं और चीनी को मार्किट मे लाएं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इस बारे मे हमने बाकायदा हिदायते कर रखी है। पिछले हफ्ते सभी जिलो मे रेड हुए है और कई जगह कार्यवाही करवा रहे है और कोई जिला ऐसा नही है जहां रेड न हुआ हो। इसी तरह से डीजल और सीमैंट के मामले मे भी रेड करवाए गये है और कई लोगों के खिलाफ एक ान भी लिया गया है।

श्री अध्यक्षः पिछले एक महीने मे जितनी रेड हुये है और सरकारने कितना स्टाक पकड़ा है क्या उसक `बारे मे आप सची दे सकते है ताकि मैंबरो को जानकारी मिल सके।

चौधरी भजन लालः ठीक है जी, वह हम सरकुलेट करवा देंगे।

Complaints regarding malpractices in the distribution of sugar/kerosene

***1443. Shri Mook Chand Jain:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to stat—

(a) the month and year from which sugar and kerosene iol are being supplied on ration cards through Government approved depots in the State;

(b) the quantity of sugar and kerosene oil alloted to all the deposts is the State in the months of December, 1979 and January, 1980;

(c) whether complaints of malpractices against the deport holder/officials in the distribution of sugar and kerisene have been recieved; if so, the district wise and monthwise number thereof since December, 1979, to date together with the action taken against the delinquent depot holders/officials; and

(d) whether complaints regarding the distribution of inferior quality sugar and kerosene adulterated with cheap diesel have also been recieved; if so, number thereof and action taken thereon?

Food and Supplies Minister (Ch. Gajraj Dahadur Nagar):

(a)	Sugar	December, 1979.
	Kerosene oil	November, 1979.
(b)	Sugar	6728 tonnes.
	Kerosene oil	13253 K.L.

(c) Yes, The required information is placed on the Table of the House.

(d) No.

Statement

Statement showing the details of complaints of malpractices againt the depot holder/officals in the distribution of sugar.

Name of District	December, 1979		January, 1980		February, 1980		Action taken agains depot holder/officials
	Depot holder	Officials	Depot holder	Officials	Depot holder	Officials	
Ambala							
Bhiwani			1		1	1	(i) In one Show Cause Notice issued to depot holder & in other case 50 % of the security forfeited. (i) Enquiry against official

							being held.
Faridabad							
Gurgaon							
Hisar							
Jind							
Karnal					5		Complaints being equired into by D.F.S.C.
Kurukshetra							
Kaithal							
Narnaul							
Rohtak			2		1		Show Cause Notice issued to 2 depots. One case under enquity by D.F.S.C.
Sirsa						1	Under enquiry by D.F.S.C.

Sonepat					1		F.I.R. lodged with police.

Statement showing the details of complaints of malpractices againt the depot holder/officals in the distribution kerosene oil.

Name of District	December, 1979		January, 1980		February, 1980		Action taken agains depot holder/officials
	Depot holder	Officials	Depot holder	Officials	Depot holder	Officials	
Ambala			4		2		Fine imposed in 4 cases. One case is still unde action. Once case filed.
Bhiwani			1				Sequrity of depot holder forefeited.

Faridabad			4				Supplies of the two depot holders suspended and two depots cancelled.
Gurgaon			1				Show Cause Notice issued to depot holder.
Hisar							
Jind							
Karnal			4				Cases registered with the Police.
Kaithal			2				-Do-
Kurukshetra			1		4		Show Cause Notice issued to all the 5 depot holders.
Narnaul					1		Case registered with the Police.
Rohtak							
Sirsa							

Sonepat					1		Case registered with the Police.

श्री मूल चंद जैनः अध्यक्ष महोदय, पार्ट 'सी' के जवाब से साफ जाहिर होता है कि जनवरी, 1980 मे इन्होने सिर्फ 3 डिपो होल्डर्ज को भूगर के मामले मे पकड़ा है और फरवरी, 1980 मे 8 को। इसी तरीके से मिट्टी के तोल के बारे मे दिसम्बर के महीने मे इनके पास कोई शिकायत नही आई और जनवरी मे 17 शिकायतें इनके पास आई है और फरवरी मे 8 आई है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये जो शिकायते आई है, ये लोगो की अपनी शिकायतें है या उनमे सरकार की तरफ से लगाए गए किसी इंसपैक्टर की तरफ से डिपो होल्डर्ज को पकड़े जाने के संबंध मे भी शिकायते शामिल है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष महोदय, इन शिकायतों मे दोनो तरह के केस शामिल है।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके कर्मचारियो ने कितने केस पकड़े है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष महोदय, यह सैपरेट क्वैचन है। इसका अलग से नोटिस चाहिए।

Mr. Speaker: Babu Ji, actually I have not understood your supplementary. क्या आप यह जानना चाहते है कि पूलिस ने कितने केस पकड़े है और डिपार्टमैंट ने कितने पकड़े है ?

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, मै सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमैंट ने कितने केस पकड़े है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमैंट मे तमाम डिटेल्ज लिखी हुई है Where action has been taken against the depot holders as well as the officials who have been found involved in it.

श्री अध्यक्षः बाबू जी, आपने अपने सवाल के पार्ट 'सी' मे यह स्पैसीफाई नही किया whether you wanted this information separately. आपने तो सिर्फ यह कहा कि "whether complaints of malpractices against the depot holders/officials in the distribution of sugar and kerosene have been received; if so, the district wise and month wise number thereof since December, 1979 to date....." लेकिन आपने सैपरेट यह नही पूछा कि पुलिस ने कितने पकड़े है और डिपार्टमैंट ने कितने पकड़े है ?

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, यह सवाल पिछले सवाल से कनैक्टिड है और हाउस के माननीय सदस्यों को इस बारे मे गिला है कि फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट के कर्मचारी डिपो होल्डर्ज से मिले हुए होते है इसलिये केस पकड़े नही जाते और न कोई मामला काबू मे आता है ?

श्री अध्यक्षः जैन साहब, मेरे ख्याल मे कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसके लिये एक सैपरेट सैल क्रिएट किया जा रहा है।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट मे हजारो की संख्या मे डिपो होल्डर्ज होंगे उनमे से ये आंकड़े इन्होने दिये है इसलिये मैंने मंत्री जी से पूछा था कि आया किसी सिविल सप्लाई इन्सपैक्टर ने भी किसी डिपो होल्डर्ज को पकड़ा है तो इन्होने कहा कि 'हां पकड़ा है' और जब मैंने पूछा कि कितने पकड़े है तो इसका मंत्री जी जवाब नही दे रहे है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि उन्होंने एक भी केस नही पकड़ा।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि इसकी डिटेल हमने स्टेटमैंट मे दी हुई है।

Mr. Speaker: I think, this is a very categorical statement that the Leader of the Opposition has made. (Interruptions)

Ch. Gajraj Bahadur Nagar: In the statement, it is stated that:-

"(i) in one case show cause notice issued to depot holder & in the other case 50% of the security forfeited; and

(ii) Enquiry against official being held."

Mr. Speaker: I think, you should have brought this to the notice of the Hon. Minister earlier so that the information could be collected. Babuji, you kindly give a separate notice for this.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चीनी की रा ानिंग का सिस्टम जनवरी, 1980 से लागू हुआ है और भाव बढ़े है इसमे कोई दो राय नही है लेकिन जैसा मैंने माननीय सदस्यो को बताया है कि पिछली सरकार द्वारा कुछ ऐसी नीति निर्धारित की गई, जिसकी वजह से चीनी के भाव बढ़ गये है। उसने बाद जब भी हमारे पास ि ाकायते आई कि डिपो होल्डर्ज ब्लैक करते है तो हमने रेड करवाए। सभी जगह डिप्टी कमि ानर्ज द्वारा रेड करवाए गए है और बहुत से केस पकड़े भी गये है। वैसे ही यह कह देना कि फूड एंड सप्लाईज डिपो होल्डर्ज के साथ मिला हुआ है यह गलत बात है। अगर माननीय सदस्यो के नोटिस मे ऐसी कोई बात आए कि फलां डिपो होल्डर्ज के साथ मिल कर कोई इन्सपैक्टर या डी.एफ.ओ. गड़बड़ करता है, वह हमारे नोटिस मे लाये, हम उसके खिलाफ एक ान लेंगे।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सवाल के पार्ट 'डी' मे यह पूछा था कि क्या गवर्नमैंट के पास यह ि ाकायत आई है कि डिपो हाल्डर्ज बढ़िया भूगर मे इंफीरियर क्वालिटी की भूगर मिला देते है। और इसी तरह से कैरोसीन मे भी सस्ता डिजल मिला देते है तो इन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई ि ाकायत नही है। स्पीकर साहब सभी माननीय सदस्यों को यह पता है कि डिपो होल्उर्ज कैरोसीन मे एडल्ट्रे ान करते है और चीनी मे भी घटिया दर्जे की चीनी मिला कर बेचते है। (ोम भोम)

Mr. Speaker: Babu Ji, do you mean that diesel is cheaper than kerosene oil?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं जैन साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा डीजल है जोकि मिट्टी के तेल से सस्ता है। जैने साहब जरा उस डीजल का नाम बता दें।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, डीज मे मिट्टी का तेल मिल कर उसको डीजल कह करके बेचा जाता है (ाोर)।

Disparity in the pay scales of English and Vernacular Languages Teachers

***1466. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is any disparity in the pay scales of Hindi, Sanskrit, English and Punjabi teachers; and

(b) if reply to part (a) be in the affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the disparity referred to above?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाांति देवी):

(क) जी हां। संस्कृत अध्यापकों के पास भाास्त्री डिग्री होती है जिसको बी.ए. के बराबर माना गया है और इसलिये उन्हें मास्टर का ग्रेड दिया जाता है।

(ख) जी नही।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने मेरे सवाल के भाग (ख) के उत्तर मे कहा है कि वर्नैकुलर भाशा के अध्यापकों तथा संस्कृत अध्यपकों के पे सकेल मे अंतर है और सरकार इस अंतर को दूर नही करना चाहती। मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदया से पूछना चाहता हूं कि जब हिन्दी हमारी राश्ट्र भाशा है तो इसके अध्यपकों को कम वेतनमान क्यो दिया जा रहा है, इसके साथ भेदभाव क्यों बर्ता जा रहा है ?

श्रीमती भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, यद्धपि वे ि ाखा मंत्री रह चुके है, तो भी बता देती हूं कि संस्कृति अध्यापक प्राज्ञ, वि ाारद परिक्षाएं पास करने के बाद दो खण्ड भाास्त्री के पास करते है और उसके बाद ओ.टी. की ट्रैनिंग लेते है जबकि मुकाबले मे हमारे हिन्दी के अध्यापक केवल मैट्रिक के बाद ज्ञानी या प्रभाकर पास करके ओ. टी. की ट्रेनिंग लेते है। इनकी योग्यता समकक्ष नही है, इसीलिये यह अंतर रखा गया है।

सरदार सुखदेव सिंहः क्या मुख्य संसदीय सचिव महोदया, बतायेंगी कि किन पंजाबी अध्यापकों की क्वालिफिके ान्ज पूरी है, क्या उनको मास्टर का ग्रेड दिया जायेगा ?

श्रीमती भाांति देवीः क्वालिफिके ान पूरी होने से आपका क्या क्या उद्दे य है, सबसे पहले आप मुझे यह बता दे। (व्यवधान)

सरदार सुखदेव सिंहः क्वालिफिके ान से मेरा उद्दे य यह है कि जो पंजाबी अध्यापक ज्ञानी टीचर्ज लगे हुए है और उन्होंने बी.ए. पास कर ली है, क्याउनको सरकार मास्टर का ग्रेड देने की कोि ाश करेगी ? अक्सर उनको ज्ञानी कह कर टाल दिया जाता है, ऐसा नही होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती भाांति देवीः अगर कोई पंजाबी अध्यापक ज्ञानी करने के बाद बी.ए. पास कर लेता है तो हम उसको मास्टर का ग्रेड दे देंगे।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, बहुत से भाास्त्री पास अंडर मैट्रिक भी होते है, बहुत कम भाास्त्रियों ने मैट्रिक पास की हुई होती है लेकिन वे पूरा ग्रेड ले रहे है। जिस तरह से भाास्त्री को प्राज्ञ, वि ाारद और भाास्त्री के दो खण्ड पास करने पड़ते है उसी प्रकार हिन्दी अध्यापको को रत्न, भूशण पास करने के बाद प्रभाकर पास करने पड़ते है उसी हिन्दी की हाईएस्ट डिग्री है। इस चीज को ध्यान मे रखते हुए क्या सरकार हिन्दी अध्यापको को संस्कृत अध्यापको के बराबर ग्रेड देने के लिशय पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती भाांति देवीः संस्कृत अध्यापक प्राज्ञ, वि ाारद पास करने के बाद भाास्त्री के दो खण्ड पास करते है और इसके बाद ओ.टी. की ट्रेनिंग करते है, इसीलिये उनको मास्टर का ग्रेड दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने यहां पर बड़ा जोर लगार बताया कि भाास्त्री पास करने के लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है । मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदया से जानना चाहती हूं कि स्कूलों मे जहां एस.एस. मास्टर संस्कृत पढ़ा रहे है उनको जगह भाास्त्री लगाने की कृपा करेंगे और जो संस्कृत अध्यापकों की कमी है उसको पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती भाांति देवीः इस कमी को पूरा करने के लिये हमारा प्रयास जारी है और निकट भविश्य मे इस पर हम कोई खास डिसीजन लेने जा रहे है ।

Cases of dacoities, murders, arsons, rapes etc. in the State

***1484. Ch. Ram Lal Wadhwa, Ch. Satvir Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district wise number of cases of thefts, arsons, dacoities, murders and rapes in the State during the years 1975-76 to 1979-80 (to date), separately; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above challaned in the courts during the period referred to in part (a) above, separately?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT-1

(a):

District wise statement of registered cases during the year 1975-76.

District	1975-76				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	317	-	3	24	10
Kurukshetra	231	5	-	25	5
Karnal	305	4	3	7	8
Sonepat	161	-	1	14	2
Gurgaon	352	13	2	11	3
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	263	5	1	15	6
Rohtak	287	3	2	20	6

Narnaul	178	7	2	8	-
Jind	145	-	1	15	4
Bhiwani	237	10	-	18	3
Sirsa	90	2	-	7	5
Total	2568	49	15	164	52

District wise statement of registered cases during the year 1976-77 & 1977-78

District	1976-77				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	307	-	1	20	1
Kurukshetra	178	4	-	12	5
Karnal	257	6	2	20	4
Sonepat	214	4	-	15	4
Gurgaon	378	7	7	15	2
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	226	3	1	23	7
Rohtak	238	3	-	23	7
Narnaul	130	5	-	9	-

Jind	131	4	-	12	1
Bhiwani	160	2	-	11	7
Sirsa	87	3	-	9	2
Total	2307	41	11	169	40

District	1977-78				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	524	-	-	19	10
Kurukshetra	400	6	1	22	6
Karnal	721	14	4	44	4
Sonepat	316	4	-	18	3
Gurgaon	706	11	10	36	14
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	537	12	3	21	12
Rohtak	491	6	2	31	4
Narnaul	218	3	2	5	3
Jind	161	-	-	26	3
Bhiwani	249	9	1	16	6
Sirsa	95	7	1	11	4

Total	4418	72	24	249	69

STATEMENT-1

District wise statement of registered cases during the year 1978-79 and 1979-80 (to date)

District	1978-79				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	557	-	5	25	2
Kurukshetra	365	5	3	27	7
Karnal	562	13	-	25	7
Sonepat	297	7	2	27	5
Gurgaon	637	14	10	31	11
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	650	15	1	43	9
Rohtak	328	8	2	37	10
Narnaul	254	12	2	12	-
Jind	172	3	2	22	6
Bhiwani	205	13	1	26	7
Sirsa	147	2	-	16	2

Total	4174	92	28	291	66

District	1979-80 (to date)				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	487	-	-	21	8
Kurukshetra	356	6	-	19	4
Karnal	601	9	2	39	8
Sonepat	385	11	2	39	8
Gurgaon	299	15	1	13	5
Faridabad	374	8	-	18	1
Hisar	417	17	3	45	6
Rohtak	395	8	1	26	6
Narnaul	231	12	1	22	2
Jind	200	6	2	22	3
Bhiwani	161	5	1	15	2
Sirsa	182	16	1	24	5
Total	4088	111	14	303	58

STATEMENT-II

District wise statement of Challaned in Courts cases during the year 1975-76 and 1976-77

District	1975-76				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	177	-	2	15	9
Kurukshetra	128	3	-	23	5
Karnal	145	1	3	5	7
Sonepat	97	-	1	13	2
Gurgaon	197	4	2	7	2
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	102	5	1	15	5
Rohtak	147	3	2	17	6
Narnaul	116	1	2	8	-
Jind	67	-	1	13	2
Bhiwani	228	8	-	18	3
Sirsa	61	2	1	6	4
Total	1462	27	14	140	45

District	1976-77

	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	178	-	1	16	1
Kurukshetra	114	1	-	12	3
Karnal	158	4	2	19	3
Sonepat	154	3	-	15	3
Gurgaon	231	3	3	12	2
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	101	1	1	23	6
Rohtak	129	2	-	18	7
Narnaul	92	4	-	9	-
Jind	98	4	-	12	1
Bhiwani	167	2	-	11	7
Sirsa	62	1	-	7	2
Total	1484	25	7	154	35

STATEMENT-II

District wise statement of cases Challaned in Courts during the year 1977-78 and 1979-80 (to date)

District	1977-78

	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	224	-	-	17	9
Kurukshetra	119	2	1	18	5
Karnal	312	9	1	34	1
Sonepat	121	3	-	13	3
Gurgaon	388	6	7	32	12
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	203	6	1	18	5
Rohtak	214	3	2	29	3
Narnaul	135	3	2	4	3
Jind	88	-	-	21	2
Bhiwani	241	8	1	16	6
Sirsa	63	1	1	9	4
Total	2108	41	16	241	53

District	1978-79				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	248	-	3	24	1
Kurukshetra	196	4	3	22	5

Karnal	284	6	-	22	5
Sonepat	152	4	2	25	4
Gurgaon	364	5	10	27	9
Faridabad	-	-	-	-	-
Hisar	298	5	1	36	8
Rohtak	211	8	2	33	10
Narnaul	166	5	1	12	-
Jind	80	2	2	20	6
Bhiwani	194	10	1	26	7
Sirsa	89	4	-	13	2
Total	2282	53	25	260	57

District	1979-80				
	Theft	Arson	Dacoity	Murder	Raps
Ambala	158	-	-	14	5
Kurukshetra	167	4	-	14	3
Karnal	198	2	-	24	5
Sonepat	169	2	1	30	-
Gurgaon	107	11	1	8	5

Faridabad	129	-	-	11	11
Hisar	131	4	2	23	1
Rohtak	121	4	-	17	5
Narnaul	117	3	-	8	2
Jind	60	2	2	16	1
Bhiwani	100	2	-	10	2
Sirsa	88	1	-	16	4
Total	1416	35	6	191	44

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट दी है, इसमे हर एक साल के क्राईमज को अलग अलग करके अगर मैं आपको बताने लगे तो बहुत टाईम लगेगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इतने क्राइम्ज बढ़ने के क्या कारण है और क्राइम्ज की संख्या घटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, क्राईम्ज कम भी हुए है। आप स्टेटमैंट को देखे, 1978–79 मे चोनी के केसिज 4174 हुए है और इसके मुकाबले मे 1979–80 मे 4088 केसिज हुए है। पहले से कम ही है, ज्यादा नही।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट के मुताबिक क्राईम्ज पहले साल की निस्बत दूसरे साल मे बढ़े है। इसलिये मैंने कहा था कि पढ़ने मे टाईम ज्यादा लगेगा। अगर मुख्य मंत्री साहब यही चाहते है तो मै पढ़ देता हूं। आप देखे कितने केसिज रजिस्टर हुए है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: केसिज रहजस्टर होने का मतलब यह नही है कि क्राईम्ज बढ़ गये है। इन्क्वारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है कि क्राईम है या नही । लेकिन हमारी पूरी कोि ा ा है कि स्टेट मे क्राईम्ज कम हो और ला एंड आर्डर कंट्रोल मे रहे। इसके लिये जो कार्यवाही मुनासिब है वह हम कर रहे है।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, जितना माल चोरी होता है उसकी लिस्ट कम्पलेंट से साथ दी जाती है कि फंला फलां माल चोरी हुआ है। इन्क्वायरी आफिसर इन्क्वायरी करके चोरी तो बरामद कर लेता है लेकिन चोरी का पूरा माल गायब हो जाता है। क्या मंत्री महोदय ऐसा इंतजाम करेंगे कि जिससे चोरी की बरामदगी के साथ साथ चोरी के माल की भी पूरी तरह बरामदगी हो जाये ?

श्री अध्यक्ष: कोई इंडिविजुअल केस तो हो सकता है, जनरली ऐसा नही।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जनरली तो ऐसी बात होती नही। किसी एक आध केस मे ऐसी बात हो सकती है, जैसे फर्ज करो किसी केस मे सौ तोले जेवर चोरी हुआ हो और उसमे 5 चोर भाामिल हो। पांच चोरो मे से 3 पकड़े गये हो और दो चोर अभी तक पकड़े न गये हो। जो दो चोर पकड़े नही गये है, उन से माल की बरामदगी न हो सकी तो, ऐसा केस हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल केस होगा तो उसके लिये माननीय सदस्य मुझे जानकारी दे। मैं सरकार की तरफ से पूरी कोि ा ा करूंगा कि जितना माल चोरी हुआ है, वह बरामद होना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, परले रोज श्री हीरा नंद आर्य के सवाल के जवाब मे गवर्नमैंट की तरफ से जवाब आया था कि इस सवाल का डैटा कलैक्ट करने मे जो टाईम लगेगा उससे कोई फायदा नही होगा लेकिन आज गवर्नमैंट उसी किस्म के सवाल की डिटेल दे रही है।

श्री अध्यक्षः इतनी देर मे भाायद जवाब आ गया होगा। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि सवाल के जवाब देना या न देना गवर्नमैंट के विम पर है। इनकी मर्जी होती है तो जवाब दे देते है, मर्जी नही होती तो नही देते है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: it is not a supplementary question. It is worthwhile for the Government to say that the time and labour involved in preparing the answer to the question will not be commensurate with benefits to be achieved. उसके बाद गवर्नमैंअ ने कोि ा ा करके इंफर्मे ान मंगवा ली है, इसके लिये आपको गवर्नमैंट को भााबा ाी देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंहः ये अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देते है। आप कृपाय मिनिस्टर साहब से कह दे कि वे मेहनत करके आया करे।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब का जवाब आ चुका है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, सुनने मे आया है कि जो चोरियां होती है उनके बारे मे कुछ पोलिटिकल आदमी केस दर्ज नही होने देते। तो मै। आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की पोलिटिकल इंटरफियरैंस के ऊपर कोई चैक लगेगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये खुद सियासी आदमी है ओर सियासी आदमियो के ऊपर ही ये बात डिपैंड करती है। खास तोर पर एम.एल.ए. साहेबान अगर दखल कम देंगे जो यह चीज अपने आप कम हो जायेगी।

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, जी.टी. रोजड़ के किनारे अम्बाला तहसील मे मौड़ा गांव के पास जो पैट्रोल पम्प है,

वहां यूथ कांग्रेस वालो ने पैट्रोल पम्प के मालिक और उसके आदमियों की पिटाई की। पुलिस ने दोने पार्टीज के विरूद्ध केस दर्ज किया लेकिन बाद मे सरकार के कहने पर वह केस वापिस हो गया। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सवाल से इसका कोई संबंध नही है। (ाोर)

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, सरकारने और सी. एम. साहब ने तीन तारीख को केस वापिस लेने के लिये कहा। (ाोर) इस तरह से ला एंड आर्डर की प्रोब्लम कैसे हल होगी ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः सवाल से इसका कोई संबंध नही है। (ाोर)

श्री भले रामः क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलात्कार और कत्ल के कितने केसिज हरिजनो से संबंधित है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जवाब बड़ा डिटेल मे दिया गया है ओर उसमे लिखा है कि कितने केसिज रजिस्टर हुए और कितने चालान हुए । ये कृपया स्टेटमैंटस मे देख लें।

श्री अध्यक्षः ये हरिजनों के बारे मे जानना चाहते है।

चौधरी भजन लालः इसके बारे मे तो अगर माननीय सदस्य अलग से नोटिस देंगे तो यह भी बता देंगे। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज।

डॉ. बृज मोहन गुप्ताः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन केसिज मे सालाना मर्डर के कितने केसिज रजिस्टर हुए और उनमे अब तक कितने अनट्रेस्ड है ? (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सारे आंकड़े इसमे दिए हुए है।

डॉ. बृज मोहन गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै। मर्डर के केसिज के बारे मे जानना चाहता हूं ?

Mr. Speaker: I think, no useful purpose will be served by this.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 1975–76 मे मर्डर के 164 केसिज है, 1976–77 मे 169 केसिज है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसमे सारे आंकड़े दिए हुए है। अगर आप कहं तो सारा पढ़ कर बता देता हूं।

श्री अध्यक्षः कोई आव यकता नही ।

चौधरी भाकरूल्लाः अध्यक्ष महोदय, जब सन् 1978 मे जनता सरकार थी और मैं उस पार्टी का एम.एल.ए. नही था तो 10–2–78 को मेरे घर पर चोरी हुई थी लेकिन वह सरकार भी

बदल गई और मै भी इधन आ गया (विघ्न) लेकिन अब तक वह चोरी बरामद नही हुई ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 1978 की जिस चोरी का जिक्र किया, उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, जो अब हंस रहे है, गृह मंत्री थे। इनका फर्ज बनता था कि उसको बरामद कराते लेकिन इन्होंने कुछ नही किया। (विघ्न) माननीय सदस्य मेरे नोटिस मे कुछ दिन हुए यह बात लाए है। हमने बाकायदा एस.पी. की ड्यूटी लगा रखी है, पूछ ताछ जारी है और वह चोरी जल्दी ही बरामद हो सकती है।

I.T.I. for Boys at Jhajjar

***1495. Captain Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any poposal under consideration of the Government to open I.T.I. for boys at Jhajjar Town; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the said proposal is likely to materialize?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) No such proposal is under consideration of Govt. at present.

(b) The question does not arise.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, रोहतक जिले मे झज्जर तहसील है।

श्री अध्यक्षः वह तो सभी जानते ह। आप सवाल पूछिए। (विघ्न)

चौधरी संत कंवरः यह सवाल चूंकि झज्जर से संबंधित है जो कि रोहतक जिले मे है इसलिये मै। मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रोहतक जिले मे जो हसनगढ़ आई.टी.आई. है.....(ाोर)

श्री अध्यक्षः फिर तो आप यह भी कह सकते है कि झज्जर रोहतक मे है और रोहतक हरियाणा मे है, इसलिये कोई भी सवाल पूछ लिया जाये। (विघ्न) खैर, आप सवाल पूछिए। (विघ्न)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बहुत सारे रिप्रैजैंटे ांज देने के बावजूद भी हसनगढ़ आई.टी.आई. मे प्रिंसिपल और म ाीने आदि क्यों नही है ?

श्री अध्यक्षः मेन क्वै चन से इस प्र न का कोई संबंध नही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अर्ज यह है कि हसनगढ़ आई.टी.आई. मे प्रिंसिपल इसलिये नही था क्योंकि वह तो एक सब ब्रांच थी अब आई.टी.आई. हो गई है। इसके अलावा मेहम और रोहतक मो भर आई.टी.आई. है यानी रोहतक जिले मे तीन है।

चौधरी संत कंवरः मैं इस बात को चैलैंज करता हूं (ाोर)

चौधरी भजन लालः पहले वह एक सब ब्रांच थी अब पूरी आई.टी.आई. है।

श्री अध्यक्षः मैं आनरेबल मैंम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि अगर कोई मानीय सदस्य इंटैलिजैंट सप्लीमैंटरी पूछना चाहे तो मैं उसे पूरा मौका दूंगा लेकिन अगर कोई भाोर मचा कर अपनी बात कहना चाहेगा उसे मैं अलाऊ नही करूंगा। (विघ्न)

It this way, no useful prupose will be served and i thing, this wil only be wasting of time. You are only giving an exhibition of your intelligence and way of behaviour. अगर कोई इंटैलिजैंट सप्लीमैंटरी क्वे चन पूछना चापहेगा, चाहे वह मन क्वै चन से कनैक्टिड न भी हो, उसे मैं मौका दूंगा जैसा कि मैंने चौधरी संत कंवर जी को दिया है। बीच मे भाोर मचाने से कोई फायदा नही होगा।

श्री हीरानंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कुछ स्थानों पर आई.टी.आई. खोलने की घोशणा की थी। क्या मुख्य मंत्री जी उन द्वारा की गइ कमिटमैंटस को भी ध्यान मे रखेंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी ने अगर कोई घोशणा की है जो उनको ऐग्जामिन करवा लेंगे और अगर कहीं आई.टी.आई. खोलने की आव यकता हुई तो वहां भी खोलने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, झज्जर के अंदर एक सरकारी पौलिटैक्निक है। उसमे बहुत सी ऐसी म ाीनरी भी है जो वहां आई.टी.आई. के कुछ ट्रेडज के काम आ सकती है। क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसम ाीनरी को प्रयोग मे लोने के लिये कोई नई ट्रेटज वहां चालू की जायेगी?

चौधरी भजन लालः इसको ऐग्जामिन करवा लेंगे और अगर कोई ट्रेड चालू हो सकी तो भाुय करवा देंगे।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, झज्जर फौजी इलाका है। वह फ्लड अफैक्टिड एरिया भी है और चार पांच हल्कों से कनैक्टिड भी है। अगर मुख्य मंत्री जी आई.टी.आई. की ब्रांच ही वहां खुवला दे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछ रहे है या सजै ा दे रहे है।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं तो रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

कैप्टन मांगे रामः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब के पार्ट 'ए' में कहा है कि–

"No such proposal is under consideration of Govenrment at present."

स्पीकर साहब, झज्जर, जैसाकि दलाल साहब ने कहा, एक फौजी इलाका है। वह फ्लड अफैक्टिड ऐरिया भी है। ट्रेनीज का झज्जर से रोहतक जाने मे बड़ा खर्च होता है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये समय झज्जर मे भी आई.टी.आई. खोने की बात को कंसिडर करेंगे जब दूसरी जगह आई.टी.आई. खोलने की बात पर ये विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस पर जरूर विचार किया जायेगां हम कोि ा ा करेंगे कि अगर पूरा आई.टी. आई. नही तो ब्रांच ही वहां खोल दें।

Mr. Speaker: Question Hours is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Technical educaiton facilities in Mewat area

***1478. Swami Aditya Vesh:** Will the Minsiter for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to provide technical education facilities in Mewat area; and

(b) if so, the details thereof together with the time by which the said scheme as referred to in part (a) above is likely to be implemented?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) जी नही।

(ख) प्र न उत्पन्न नही होता।

Milk Plant at Sirsa

***1538. Sh. Mani Ram, Sh. Bhagi Ram:** Will the Minsiter for Cooperation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that foundation stone for the setting up of a Milk Plant in district Sirsa was laid; and

(b) if so, the time by which the afore said Milk plant is likely to be set up?

Cooperation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) Yes.

(b) The Sirsa Milk Plant is expected to be completed by the middle of 1982.

District Reorganisation Committee's Report

***1510. Ch. Satvi Singh Malik:** Will the Minsiter for Revenue be pleased to state—

(a) whether the District Reorganisation Committee has submitted its report to the Government during the year 1979-80; if so, whether it has been implemented; if not, the reasons therefor; and

(b) wheter the Government has shifted some revenue estates from one district to another district, from one sub division to another sub division, if so, the reasons and criteria adopted therefor?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) हां। जिला पुर्नगठन कमैटी की कुछ सिफारि ो को कार्यान्वित किया जा चुका है जबकि अन्य अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) हां राजस्व एस्टेटो को एक जिले से दूसरे जिले ता एक उप मण्डल से दूसरे उप मण्डल मे तबदील करने बारे अन्य कारणा के अतिरिक्त आपसी मेज जोल, यातायार सुविधाओं,

व्यापारिक संबंधों तथा प्र ाासकीय सुविधाओं को ध्यान मे रखा गया है।

Repair of roads in District Sirsa

***1517. Ch. Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minsiter for P.E.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads in District Sirsa—

(i) Kagdana to Kumahria (ii) Chopta to Bhattu (iii) Chpta to Jamal (iv) Sirsa to Modia, and (v) Ding to Sarovarpur?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): हां ।

इन सभी सड़कों की मुरम्मत लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क भााखा) द्वारा की जा रही है।

(c)

Constuction of bridge on Western Yamuna Canal

***1573. Smt. Sr. Kala Verma:** Will the Minsiter for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) The reasons for not starting the work so far on the bridge on Western Yamuna Canal even after its foundation stone had been laid by the Chief Minister on 19th October, 1979; and

(b) the time by which the constuction will be started thereon?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) The work could bot be started earlier as the location of the bridge has been cleared by the Army authorities only on 5-3-1980.

(b) Now work will be started after the call of tenders at an early date.

Damage to Rabi Crops due to Hailstorms

***1577. Sh. Gulzar Singh:** Will the Minsiter for Revenue be pleased to state—

(a) the district wise number of villages where Rabi crops of 1979 were damaged due to hailstorms in the State;

(b) whether compernsation to all the hailstorms affected farmers in all the villages referred to in part (a) above has been paid; if so, the amount of compensation so paid in each such village; and

(c) if reply to part (b) be in the negative the district wise names of vilalges where compensation to the hailstorms affected farmers has not so far been paid together with the reasons therefor?

***Interim Reply**

“Sher Singh Revenue Minister, Haryana.

D.O. No. 776-ER(II)_80/8964

Chandigarh, dated 7-3-80

Subject:- Starred Assembly Question No. 1577.

My Dear Col. Sahib Ji,

The Starred Assembly Question No. 1977, asked by Shri Gulzr Singh, M.L.A., has been fixed for answer on 11-33-1980. Notice for this question was received on 27-2-1980. The reply to the Assembly question is not ready as the equired information is awaited from the Deputy Commissioners.

2. I shall be grateful if you kindly extedn the time for answring the quesiton under Rule 46(ii) of the Rules of Procedue and Conduct of Business in the Haryana Legislative Asembly. This quesitonmay be included in the list of questions for any date after one month.

With regards.

Yours sincerly,

Sd/-

(Sher Singh)

Col. Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Endst. No. 776-ER(II)-80/ dated

A copy is forwarded to the PS/CM for information of Chief Minister, Haryan.

Sd/-

Revenue Minister,

Haryana"

तारांकित प्र न एंव उत्तर

J.B.T. Teachers in District Jind

335. Sh. Mange Ram Gupta: Will the Chief Minsiter be pleased to state—

(a) whether it is fact that the selection grade of Rs. 250-300 was given to JBT teachers on the basis of total number of posts of these teachers in a district during the year 1967; and

(b) if so, whether it is also a fact that the yearwise lists of number of posts of JBT teachers in district Jind bas not so far been announced; if so, the reasons therefor?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) JBT teachers have district wise Cadre and selection grade is awarded on 15% of permanent posts. Numbers of permanent posts changes from time to time.

(b) No year wse list of numbers of permanent posts is announced. However, if may be stated that at present thee are 1151 permanent JBT (men) posts and 159 permanent JBT (women) posts and on the basis thereof 172 JBT (men) Teachers and 24 (women) Teachers have been awarded selectiongrade.

Annual increments to selection grade JBT Teachers

336. Sh. Mange Ram Gupta: Will the Chief Minsiter be pleased to state—

(a) whether it ios a fact that the JBT teachers drawing the selection grade of Rs. 250-300 have been given annual increments after the completion of their selection grade: and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give annual increment to the teachers as referred to in part (a) above; if so, the time by which it is likely to be given?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि जै.बी.टी. अध्यापकों के बाई एनुअल वृद्धि ग्रेड के पूर्ण होने पर दे दी जाये।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

रूल 116 के अधीन या अन्यथा कार्यवाही से हिस्से या हिस्सों को नकालने के अध्यक्ष के विवेकाधिकार संबंधी

Mr. Speaker: Hob'ble Members, a couple of points of order wre raised two or three days back जिनपर मैंने अपनी रूलिंग रिजर्व की थी। उन पर रूल्ज स्टडी करने के प चात अब मैं रूलिंग देता हूं–

The first point is "Does the Speaker's discretion extend beyond the term and words 'defamatory, or indecent, or un parliamentary or undignified' under Rule 116 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Vidhan Sabha, in the power of the Speaker to expunge part or parts of the proceedings?"

रूल 116 बड़ा स्पश्ट है। इसके अलावा on page 860 of the book 'Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher' it has been stated that the scope of the rurl governing the expunction of words hav ebbeen enlarge and the Speaker has ordered, in his discdretion, form time to time, the expunction of ward, which he considered su judice, prejudicial to the national interest, or to the maintenance of friendly relations with a foreign Statre, deropatory to high dignitaries a

comminity, likely to discredit the Indian Army, and not in good test or otherwise objectionable. Further, the Chair canorder expunction of words/remarks/speach and even order their not being recorded in any of the following cases:-

(i) when a member, on being asked to withdraw objectionable remarsk held to be not relevant ot the debated, refuses to do so;

(ii) on bieng aksed by the Chair not to quote from ad document of which advance notice has not be given and which is not relevant to the dabate, if the memebr continues to quote therefrom;

(iii) where a member without being called upon to speak, continoues speaking despite the Chair asking asking him to desist from it;

(iv) if a memebr continues to interrupt the speech of another memebr or a Minister; and

(v) if a memebr speaks on an extraneous matter without rising on a point of order.

The second point is “Can the Speaer order expunction of his own ruling or observation given ont he floor of the House?” As regards this point, when a Speaker gives a ruling on any point of order or otherwise arising furing the course of debates, it becomes the order of the House. The ruling of the Speaker is final. Although the ruling of the Speaker is neve rexpunged, however, there is nothing to prevent the Speaker from revising any ruling at any subsequent stage if the changed cicumstances so warrant.

Hon. Members, it will be observed that one of the important criteria fro expunction is that of a Member continuing to interrup the speech of another Memebr or a Minister or even in the case of the Chief Minister. The same will apply to irrelevant points of order. I ahve been noticing in this House that form post few days, the members have been raising irrelevant points of order merely to interrupt the continuity of the speech of some of the senior legislators and even some of the Ministers. No. doubt, thee can be no hard whether a point of order is relevant or irrelevant but as you might be aware of old story ofg 'wolft, wolf' is repeated, the people are bound to ignore and stop believing it. Similarly, in view of my past experience, I was constrained to observe that thee was n point of order as numerous irrelevant points of order were being raised primarily with a view to interrupt the speeches of the Memebrs, Ministers and even the Chief Minister. It will also be appreciated that a point of order can be raised only in respect of the subject before the House. So when there was occasion or the subject did not attract any pont of order, it was not very difficult for me even to prejudge that the sole objective of the point of order was to interupt the continuity of the speech of the Memeber and it was not actually a point or order.

Ho. Members, we all are here to serve our masters, which is the electorate. I own it to the House that the discussions are not interupted on trivial and irrelevant grounds. This I wish to ensure to the best of my ability. I am open tosuggestion from senior legislators and even from some other friends to ensure tha achievement of this object. I would conclude my ruling with an appreal to atleast the Leades of all

the parties and various groups in this House that they should ensure that our deliberations are not disturbed or interrupted on trivial and irrelevant grounds. Towards this object they should ensure that the membes of their parties or groups remain within the ambit of some someblance of decorum and discipline, which has been sadly lacking in this House in the post one week.

श्री मूलचंद जैनः स्पीकर साहब, मैंने भी आपको दो प्वायंट लिख कर दिये थे परन्तु उनके बारे मे आपकी रूलिंग नही आयी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अज आपके प्वायंटस मेरे सामने आयेंगे तो उन पर भी जरूर रूलिंग दूंगा। (विघ्न)

श्री मूलचंद जैनः मैंने आपके सामने ही दिये थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेरे को नही दिये। (विघ्न)

श्री मूलचंद जैनः आपके सामने आप के सैक्रेटरी को ही हाउस मे दिये थे। (विघ्न)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मेरी एक काल अटैं ान मो ान थी उसका अभी तक जवाब नही आया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपकी काल अटैं ान मो ान अंडर कंसिड्रै ान है। (विघ्न)

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, अब जीरो आवर है, इसलिये मैं ला एण्ड आर्डर के बारे मे अर्ज करना चाहता हहूं। वैसे तो मैं क्वै चन आवर मे भी सप्लीमैंटरी उठाना चाहता था परुतु आपने समय नही दिया। मेरे उकलाना हल्के मे थ्री स्टार इंसपैक्टर की पिटाई की गई। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आपके इसके लिये नोटिस नही दिया । (ाोर) इस लिये इस समय आपको इजाजत नही दूंगा। अब आप बैठिये। बिना नोटिस के इजाजत नही दूंगा।

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, इन्सपैक्टर की पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद वे आदमी कार मे भाग गये। कार के नीचे 11 साल का लड़का मारा गया। आज यह ला एंड आर्डर की हालत हरियाणा मे है। (ाोर)

ध्यानाकर्शण सूंचना

रोड़ी तथा सिरसा डिविजनो के लिये टोहाना हैड से पानी की कम सप्लाई संबंधी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मनी राम ने टोहाना हैड से रोड़ी और सिरसा डिवीजन को पानी मे कमी करने के बारे मे एक काल अटैन ान मो ान का नोटिस दिया है। मैं इसे मंजूर करता हूं। इसलिये मैंबर साहब अपना नोटिस पढ़ सकते है।

Shri Mani Ram: Sir, I draw the attention of this august House to the matter of an urgent public importance about short supply of water from Tohana Head for Rori and Sirs Divisions. The points to be urged are as under:-

1. That for the above said Divisions; the sanctioned quantity of water is 1200 Cs (Twelve hundred) whereas supply is being made 500 Cs.

2. That because of this short supply of water a great discrimination is being made to the farmers of these divisions.

3. That becouse of this short supply of wather the farmers of thise divisions have suffered a great loss, their crops have been damaged to an underable extent and they have duffered a great economic loss.

4. That because of this short supply against sanctioned quota is a great discrimination and people are greatly demoralised.

It is therefore, requested to the Govt. to take notice of it and give the reply in the present session.

Mr. Speaker: Would the Hon. Minister like to give the reply today or subsequently?

सिंचाई तथा बिजली मंत्रीः (चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, मैं अभी जवाब दे देता हूं।

वक्तव्य–

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्शण सूचना संबंधी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, ध्यानाकर्शण सूचना मे उसकाल का विवरण नही है जिसमे सिरसा भाखड़ा नहरें परिमण्डल के सिरसा तथा रोड़ी मण्डलों मे कम पानी दिया गया है। सिरसा और रोड़ी मण्डल सिरसा भाखड़ा नहर परिमण्डल के अधिकार क्षेत्र मे आते है जिसको कि भाखड़ा के पानी से 100 बुर्जी पर पानी दिया जाता है। 1–2–80 से 5–3–80 तक दिये गये पानी की स्थिति इस प्रकार है:–

1–2–80 से 5–3–80 तक टोहाना हैड पर प्राप्त किये हुए पानी की मात्रा 129999 क्यूसिक्स दिन थी (जिसकी दैनिक औस्तन 3923 क्यूसिक्स बनती है) जिसमे से सिरसा और रोड़ी मण्डलों का हिस्सा 100 बुर्जी भाखड़ा मुख्य भााखा पर 52857 क्यूसिक्स दिन था (औस्तन 1554 क्यूसिक्स दैनिक) इसकी तुलना मे 100 बुर्जी भाखड़ा मुख्य भााखाा पर इन मण्डलों मे उपयोग के लिये दिया गया पानी 48620 क्यूसिक्स दिन था। (औस्तन 1423 क्यूसिक्स दैनिक) औस्तन कमी लगभग 8 प्रति ात बनती है जोकि नाम मात्र है। ऐसी नाम मात्र कमी आने वाले काम मे परी कर दी जाती है जो कि पानी के दैनिक उतार चढ़ाव को देखते हुए केवल नाम मात्र है। इसके बाद तमाम मण्डलों के पानी का हिसाब रोटे ानल कार्यक्रम के अंत मे संतुलित कर दिया जाता है।

इस तरह की कोई कमी नही है, और इस प्रकार इन मण्डलों के किसानो के साथ कोई विभेद पूर्ण नीति नही अपनाई जा रही है। प्राप्त होने वाले पानी का देय हिस्सा दिया जा रहा है।

पानी की कोई कमी नही है।

पानी का देय हिस्सा दिया जा रहा है।

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, अभी कुछ समय पहले मंत्री महोदय एम.एल.ए. होस्टल मे गए थे और वह अलग एम.एल.एज. से मिले थे और उन्होंने एम.एल.एज. से कहा कि ऐसे काल अटैं ान मो ान न दिया करो।

चौधरी मेहर सिंह राठीः मैं इस बात से डिनाई करता हूं, यह बिल्कुल गलत बात है मैंने किसी को नही कहा। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाये, बाहर की बाते यहां हाउस मे न करे।

श्री मनी रामः हमारा 1200 क्यूसिक्स पानी बनता है जिसके बदले मे हमे 500 क्यूसिक्स पानी दिया जा रहा है। अभी मैंने यह जो काल अटैं ान मो ान दी थी वह इसी सिलसिले मे दी थी कि यह जो डिस्क्रिमिने ान हो रहा है उसको दूर किया जाये। मैं मुख्य मंत्री जी से यह आ वासन चाहूंगा कि क्या भविश्य मे सारे इलाके मे जो पानी कम जा रहा है उस को पूरा देंगे ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः मैं इस बात से डिनाई करता हूं । यहां इन्होने जो कहा है कि हमारा 1200 क्यूसिक्स पानी बनता है मैं इनको बतानाचाहता हूं कि 1200 क्यूसिक्स नही बल्कि 1430 क्युसिक्स पानी बनता है। इनको अपने पानी का ही पूरा पता नही है। (ाोर)

श्री मनी रामः स्पीकर साहब, इस डिस्ट्रिब्युटरी मे एक महीने से पानी नही आ रहा है। मंत्री महोदय बे ाक वहां का दौरा करके देख ले।

चौधरी मेहर सिंह राठीः मैं दौरे पर जाने के लिये तैयार हूं और पर्सनली भी जा कर देखने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः आप मंत्री महोदय को अपने हल्के के लिये दौरे का निमंत्रण दे ताकि इस डिस्क्रिमिने ान का पता लगाया जा सके। (ाोर)

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिने ान नही है। उनको 1200 क्यूसिक्स की बजाये 1430 क्यूसिक्स पानी दिया जा रहा है। इनको पता ही नही कि अपने हल्के मे कितना पानी मिल रहा है। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब बड़ा डटेल मे दिया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इस साल भयंकर सूखा सारे दे ा मे पड़ा हुआ है। इस किस्म का सूखा आज तक कभी नही पड़ा था कि पहाड़ों मे

भी वर्शा न हो। पहाड़ों मे वर्शा न होने के कारण गोबिंद सागर का पानी 60 फुट की सतह तक नीचे चला गया। इसलिये गोबिंद सागर से पानी कम रिलीज हो रहा है। यह दिक्कत सभी जगह पर आ रही है। मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि किसी इलाके के साथ कोई भेदभाव की नीति नही बरती जायेगी। जितना पानी कम है उसके हिसाब से सभी इलाकों मे ठीक से डिस्ट्रिब्यू ान की जायेगी। किसी इलाके के साथ कोई भेद भाव नही बरता जायेगा।

श्री अध्यक्षः जो पिछले साल पानी था और जो अब पानी दिया जा रहा है, क्या उस मे कोई कटौती की है ?

चौधरी भजन लालः जैसे बिजली की पोजी ान चल रही है, उसी तरह पानी की भी चल रही है। गोबिंद सागर मे पानी कम होने के कारण पानी कम रिलीज हो रहा है। जो नहर पहले एक महीने मे एक बार बंद हुआ करती थी अब महीने मे दो बार बंद जो रखनी पड़ रही है। यह सारे इलाके मे ऐसा हो रहा है किसी एक इलाके के साथ ऐसा नही हो रहा है।

श्री अध्यक्षः क्या प्रत्येक इलाके मे यूनिफार्म तरीका चल रहा है?

चौधरी भजन लालः जी हां।

चौधरी रिजक रामः अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि गोबिंद सागर मे पानी कम होने के कारण यह कमी हुई है जबकि

राठी साहब ने फरमाया है कि रोड़ी ब्रांच को हमने पानी बढ़ा कर दिया। इसमे से कौन सी बात ठीक है ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह मुमकिन हो सकता है कि कटौती करके भी जो उनका पानी का कोटा बनता है, उससे 8 परसेंट फालतू पानी मिला होगा। (व्यवधान व भाोर)

बिल्ज (इंट्रोडयूस्ड सदन की अनुमति से)

(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउन्सिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1980

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउन्सिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउन्सिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउन्सिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्ज पैं ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्ज पैं ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्ज पैं ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली स्पीकर्ज पैं ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(iii) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(iv) दि हरियाणा वेलीडे ान आफ आक्ट्राय एण्ड सरचार्ज बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा वेलीडे ान आफ आक्ट्राय एण्ड सरचार्ज बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा वेलीडे ान आफ आक्ट्राय एण्ड सरचार्ज बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा वेलीडे ान आफ आक्ट्राय एण्ड सरचार्ज बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(v) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(vi) दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा सैलरीज एण्ड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(vii) दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, आज जो ग्राम पंचायत एक्ट मे अमैंडमैंअ करने के लिये बिल पे ा करने की अनुमति मांगी जा रही है, इस बारे मे अभी नान आफि ायल डे पर एक रैजोल्यू ान लीडर आफ दी अपोजी ान ने रखा था, उस पर बहस भी पूरी हूई थी। वह अ ाोक मेहता कमेटी की मेहता कमेटी की रिपोर्ट मे जो रिकमैंडे ान्ज है, उनको इम्पलीमैंट करना चाहते है और ब्लाक समितिज को, जिला परिशदज को और ग्राम पंचायतस को उसी तरीके से कांस्टीच्यूट करने के लिये हम एक एग्जाहस्टिव बिल लायेंगे जो एक्ट की भाक्ल अख्तियार करेगा। अगर इस अमैंडमैंट बिल को जो सरकार ने पे ा किया है, इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत दे दी जाती है तो उससे हाउस के टाईम की वेस्टेज ही होगी क्योंकि फिर वह सारे का सारा एक्अ ही

बदलना पड़गा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह गुजारि ा करूंगा कि फिलहाल या तो इस बिल के डैफर कर दिया जाये या फिर उसको फार दी टाईम बीइंग विदड्रा कर लिया जाये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा है, हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे। अभी यह कहना मुनासिब नही होगा कि इस बिल को इन्ट्रोडयूस न किया जाये और विदड्रा कर लिया जाये। इस बिल को पास करने से पहले जो भी डिसीजन होगा, वह हम तय कर लेंगे।

चौधरी खुर ाीद अहमद: स्पीकर साहब, हम इस बारे मे एक कम्प्रीहैसिंव बिल जरूर लायेंगे लेकिन यह जरूरी नही है कि हम उसे इसी सै ान मे पे ा कर सके। इसलिये मैं हाउस मे यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल को प्रस्तुत कने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(viii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैंबली (अलाउंसिज एण्ड पैं ान आफ मैंबर्ज) सैकिंड अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(ix) दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(x) दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, अब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं।

(xi) दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1980।

स्थानिय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री मूल चंद जैन (संभालका): स्पीकर साहब, यह जा बिल लाया गय है इसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, यह एक बड़ा गल्त बिल है। स्पीकर साहब, एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटिंग कमेटीज चुनाव द्वारा बनाई जाती है। जनता पाट्री की सरकार आने से पहले इस सूबू मे जो कांग्रेस सरकार थी, उस सरकारने नामजदगी का तरीका अख्तियार किया लेकिन उसके बाद जब जनता सरकार आई तो इस हाउस ने नामजदगी के तरीके को खत्म किया और चुनाव का तरीका इंड्राडयूस किया। जिस समय यह चुनाव का तरीका इंट्रोडयूस किया उस सतय ये सदस्य जो आत रूलिंग पार्टी मे बैठे है, इन्होंने एक एक करके इस चुनाव की प्रणाली का समर्थन किया था और सभी ने इस बत की ताईद की थी कि नामजदगी का तरीका खत्म होना चाहिए और चुनाव का तरीका अपनाना चाहिए। स्पीकर साहब, यह कोई पुरानी बात नही है। मेरे ख्याल मे 1977 मे यह बिल पास किया गया थ। (व्यवधान) । स्पीकर साहब, पहले भी चुनाव का ही तरीका था लेकिन दो तीन साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी उस समय यह तरीका

खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जनता सरकार के समय मे, जैसा मैंने पहले कहा है कि जहां तक मुझे याद है 1977 के सै ान मे चुनाव की प्रणाली अपनाई गई थी। अगरचुनाव से वंचित किया जा रहा है। स्पीकर साहब, यह गल्त किस्म का बिल ला रहे है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर कंसर्न्ड से प्रार्थना करना चाहता हूं कि नामजदगी के तरीके की बात न करे। अभी तक चुनाव नही कराए गये तो यह अफसोस करना चाहता हूं कि नामजदगी के तरीके की बात न करें। अभी तक चुनाव नही कराए गए तो यह अफसोस की बात है। मेरा कहना यह है कि आप चुनाव का तरीका अपनाए, सब कुछ तैयार है। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहते सिर्फ यह गुजारि ा करना चाहता हूं कि इस बिल को वापिस ले लिया जाये और चुनाव का तरीका अपनाया जाये।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, चौधरी खुर ाीद अहमद ने जो बिल हाउस के सामने पे ा किया है, मैं उनसे सहमति प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, आज की जो मार्किट कमेटीज है उने अख्तियारात बहुत मामूली है। मार्किट कमेटीज के जो अख्तियारात थे वे सब मार्किटिंग बोर्ड को दे दिये गये है। कमेटिज के कोई अख्तियारात नही रह गये है। स्पीकर साहब, मार्किट कमेटीज के जो इलैक ान है वे ऐसे इलैक ान है जो असैम्बलीज से भी ज्यादा बदतर हैं। एक मैंबर चुनने के लिये सारी तहसील का हल्का है। एक एक मैंबर बीस

बीस हजार रूपया खर्च करता है औरइनके अधिकार कुछ भी नही है। स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि देहात की फिजा को ठीक रखने के लिये जितनी कम से कम चुनाव कराए जायें उतना ही अच्छा है (व्यवधान) । जितने चुनाव कम होंगे उतनी ही देहात की फिजा अच्छी होगी। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि पंचायतों मे नगरपालिकाओं मे और यहां तक कि असैम्बलीज मे भी चुनाव सिस्टम को खत्म किया जाये और नौमिने ान का सिस्टम भाुरू किया जाये (व्यवधान) जिससे कि देहात की फिजा अच्छी हो सके।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जो बिल इंट्रोडयूस किया है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल हमारे दे ा के लोकतान्त्रिक ढांचे पर एक भारी प्रहार है। अध्यक्ष महोदय, उस दिन पंचायती राज संस्थओं के बारे मे बाबू मूल चंद जैन का जो प्रस्ताव हुआ था, उस पर बोलते हुए भी मैंने कहा था कि पंचायतें हमारे दे ा मे लोकतान्त्रिक ढांचे की बुनियाद है और इनको नश्ट कर दिया गया तो हमारे दे ा मे लोकतात्रित ढांचा समाप्त हो जायेगा। इसलिये पंचायतों के लिये चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और नामजदगी खत्म होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बिल के उद्दे यों तथा कारणो के विवरण मे दिए हुए केवल मात्र एक सैंटेंस की ओर दिलाना चाहती हूं। इसमे लिखा है—''मण्डी समितियों के निर्वाच मे सामन्यतः बहुत समय लगता है''।

स्पीकर साहब, डिले का कारण यह बना रहे है क्योंकि इलैक्टोरल कालिज के चुनाव नही हो सके। जब आप लोगो की नियत ही नही है कि इलैक्टोरल कालिज के चुनाव हो तो वे कैसे हो सकते है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बिल लाकर ये हमारे दे ा मे चुनाव ढांचे को समाप्त करना चाहते है। ये लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त करने की साजि ा कर रहे है। कल को ये असैंबलीज के चुनाव समाप्त कर देंगे, फिर पार्लियामैंट के चुनाव समाप्त होंगे। अध्याक्ष महोदय, मैं इस अलोकतान्त्रिक बिल का विरोध करती हूं (व्यवधान)।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर साहब, जो यह बिल लाया गया है, मैं इसके बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। कि मार्किट कमेटी का जो महकमा है यह किसानो के मुफाद के लिये है। यह महकमा किसानो की पैदावाद की हिफाजत करता है। यह महकमा भाहरों मे और देहातो मे यह देखता है कि किसानो का अनाज ठीक से तोला जाये, उनके अनाज का ठीक भाव किसानो का माल ठीक तरह से बिके, बोली ठीक लगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मार्किट कमेटी के प्वायंट पर आएं और इसी प्वायंट पर बोले।

कामरेड भांकर लाल: मैं मार्किट कमेटीज पर ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पे ा किया गया है, यह अलोकतान्त्रिक बिल है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, चौधरी खुर ाीद अहमद ने जो बिल इंट्राड्यूस किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खडा़ हुआ हूं। (व्यवधान) स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम ने आज भी इस बिल का समर्थन किया है और परसों भी नान आफि ायल डे पर बाबू मूल चंद जैन के रैजोल्यू ान पर इन्होंने पंचायतो के बारे मे कहा था कि इन पंचायतो के चुनावों ने गांवो की फिजा खराब कर दी है, चुनाव नही होने चाहिए। अभी वे कह रहे थे मार्किट कमेटियों के चुनाव अनडैमोक्रेटिक है और ये नही होने चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि असैम्बलीज मे भी नोमिने ान कर देनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं सदन का ध्यान स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज की ओर दिलाना चाहता हूं। कितनी गल्त बयानी की गई है। पता हनी कोई पढ़ता भी है या नही। इसमे लिखा है–

"Section 12 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 provides for the constitution of the Market Committees consisting of elected members, election to Market Committees generally takes long time as the elections of producer members has top be made by the Panches and Sarpanches of the Gram Panchayats, the election of which could not be held so far....." I want to know who was responsible.

Voices: You are responsible.

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस इलैक ान को करवाने के लिये कभी इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया, या कोई इस

बारे मे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आया हो या कोई और बाधा आ पड़ी हो जिसकी वजह से ये इलैक ान नही हुए ? (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। भाायद मेरे दोस्त को इस बारे मे गलत फहमी हो गई है। 1978 मे पंचायतो के इलैक ान तो हो चुके है। स्पीकर साहब, इन्होनें इस बिल को लाने को वजह यह बताई है कि प्रोडयूसर्ज के नुमाइंदे इलैक्ट नही हो सके है क्योंकि पंचों और सरपंचों के चुनाव नही हुए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जैन साहब, आप दोनो ही वकील है, आप आपस मे ही इस बात का फैसला कर ले।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, फैसल तो आपने कहना है, मैं तो यह बता रहा था कि इस बिल के आब्जैक्टस एण्ड रीजंज मे जो यह लिखा गया है कि पंचों और सरपंचों के इलैक ान नही हुए है, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अध्यक्षः बिल की लैंगवेज से यही जाहिर होता हे कि अभी तक पंचायतों के इलैक ान नही हुए है, इसलिये प्रोड्यूसर मैंबर्ज के इलैक ान नही हो सके।

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि इस का मतलब उलट पड़ गया है।

Mr. Speaker: Would the Hon. Minister also like to reply?

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, इस बिल के बारे मे मैंने मैंबर साहेबान के विचार सुने और विचार सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंबर साहेबान गल्तफहमी के ि ाकार हो गये है। इसमे कोई खास बात नही है जिस पर मैंबर साहेबान नेइतनी नुक्ताचीनी की। इसमे तो एक मासूम सी बात है, जिसको चौधरी रिजक राम जी ने आसानी से कह दिया है। चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि मार्किट कमेटियो के जो अखितयारात थे, वे अब मार्किटिंग बोर्ड को दे दिये गये है। कमेटिज को कोई अख्तियारात नही दिये गये है। क्योंकि मार्किट कमेटियो के इलैक ान अभी तक नही हो पाये, इसलिये हमने यह फैसला किया है कि इन कमेटियो मे नामजदगी करके इनको कांस्टीच्यूट किया जाये ताकि ये कमेटियां अपना काम ठीक ढंग से खुद चला सकें।

स्पीकर साहब, जनता सरकार पिछले अढ़ाई सालों मे इस संबंध मे कुछ नही कर सकी, इसलिये हम कमेटियों का काम उनको ही सौंपने के लिये यह बिल लाए है। इसमे और कोई ऐसी बात नही है, इसलिये मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced that "The Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was carried.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Bill.

वर्श 1970–80 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वो पर प्रभारित अनुमानों पर चर्चा

Mr. Speaker: Now the House will discuss the supplementary Estimates for the year 1979-80. Those hon. Members who wish to discuss the charged items may please do so.

(No Member rose to speak.)

(ii) अनुपूरक अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः साहेबान, पहली प्रैक्टिस के मुताबिक हाउस का समय बचाने के लिये, सभी डिमांडज जो आर्डर पेपर पर है, वे एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गयी समझी जायेगी। माननीय

सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है लेकिन बोलने से पहले, उन को डिमांड नंबर बताना होगा, जिस पर वे बोलना चाहते है। गिलोटीन एक बजे बाद दोपहर अप्लाई किया जायेगा।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 263000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs.802770 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.2-Genral Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs.14258875 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs.54630680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.4-Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs.16289405 for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.4518060 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.7-Other Administrative Service.

That a supplementary sum not exceeding Rs.893790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs.1444390 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs.7127220 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.110972835 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs.20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18929000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs.7255360 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs.365700 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.125658545 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10003000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.22-Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.445440 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

श्री मूल चंद जैन (सम्भालका): अध्यक्ष महोदय, ये सप्लीमेंटरी डिमांडज कुल मिला कर 39 करोड़ 33 लाख रूपये की है। (इस ससमय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। डिप्टी स्पीकर साहब, इन सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस मे सरकार जो कुछ चाहती है ।और कल बजट स्पीकच मे फाइनैस मिनिस्टर साहब ने जो कुछ पढ़ा, इन दोनो डाकुमैंटस को देखते हुए मै यह समझता हूं कि हमारी सरकार ने बजट पे ा करने का और सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पे ा करने का यह नया ही तरीका निकाला है। कल फाइनैंस मिनिस्टर ने खास तौर पर जो यह कहा था कि वे वेस्टफुल एक्सपैंडिचर को कम करने की कोि ा ा करेंगे और इसी तरीके से जो 45–46 करोड़ रूपये का घाटे का बजट पे ा किया है, उस घाटे को कम करने की कोि ा ा करेंगे। अगर आप इसी सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस को पढ़ कर देंखे तो कल जो उन्होंने बात कही थी वह उससे

बिल्कुल उलट है। सबसे पहले मैं डिमांड नंबर दो जिसमे गवर्नर साहब के लिये 3 लाख 84 हजार रूपये और मिनिस्टरों के लिये 8 लाख रूपये के करीब मांगे गये है, के बारे मे कुछ कहना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप देखेंगे कि जहां तक गवर्नर साहब के खर्चे का ताल्लुक है, 1977–78 मे गवर्नर साहब और उनके अमले के लिये 11 लाख 77 हजार रूपये खर्च हुए थे। 1978–79 मे बजट मे इसके लिये 10 लाख 42 हजार रूपये रखे गये लेकिन खर्चा जो किया था वह 14 लाख 13 हजार रूपये हो गये यानी चार लाख के करीब खर्चा बढ़ गया। इसी तरह से 1979–80 के बजट मे 11 लाख 13 हजार रूपये रखा गया लेकिन आज 15 लाख के करीब खर्चा दिखा रहे है। यानी 3 लाख 84 हजार रूपये अधिक खर्चा हो गया। मैं हाउस के माननीय सदस्यो के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि यह छोटी सी स्टेट गवर्नर और उसके अमले पर 15 लाख रूपये सालाना खर्च कर रही है। तो इससे ज्यादा वेस्टफुल एक्सपैंडिचर क्या हो सकता है ? गवर्नर साहब का खर्चा कैसे बढ़ सकता है और कैसे नही बढ़ सकता इसके लिये भारत सरकार ने नियम बनाये है। लेकिन जहां तक मुझे पता है राश्ट्रपति की इजाजत के बगैर गवर्नर साहब का कोई खर्चा नही बढ़ाया जा सकता। लेकिन इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स मे कार के बारे मे तो लिखा है कि हमने राश्ट्रपति की इजाजत ले ली और दूसरी आइटम्ज के बारे मे लिखा है कि हमने राश्ट्रपति की इजाजत ले ली और दूसरी आइटम्ज के बारे मे लिखा है–

"Due to the increase in the prices of commodities, it has not been possible to limit these expenses within the ceiling of Rs. 10.000. Approval of the Government of India to the enhancement of this ceiling is being obtained."

तो अभी भारत सरकार की इजाजत तो आई नही लेकिन खर्चा ये हम से मंजूद करवा रहे है। यह बात बिल्कुल कायदे के खिलाफ है। एक एक आईटम पर अगर गौर किया जाये जो मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि यह खर्चा कैसे हो गयां एक आइटम के आगे लिखा है 'एक्सपैंडिंचर फ्रास कंट्रैक्ट अलाउंस आफ गवर्नर'। कन्ट्रैक्ट अलांउस मे कार का खर्चा हो यगा और तीन चार लाख इस साल बढ़ा दिया। इसी तरीके से मिनिस्टरो के लिये खर्चा बढ़ाने की बात है। सरकार को भूलना नही चाहिए कि राजा अगर पब्लिक के बाग मे से एक आम तोड़ लेगा तो उसकी फौज सारा बाग नश्ट कर देगी। गवर्नर हाउस और मिनिस्टरी अपने लिये खर्चा बढ़ाये तो आई.ए.एस. और नीचे वालो से किफायत की आ ाा कैसे कर सकते है ? हास्पिटैलिटी एक्सपैंडिचर के लिये पहले दस हजार रूपये थे लेकिन अब ये महंगाई बढ़ जाने की वजह से उसे तीन हजार रूपये करना चाहते है। अगर महंगाई बढ़ गई है तो गवर्नर साहब की तनखाह तो कम नही हो गई है। लेकिन फिर भी उसको आप तीन गुना बढ़ाने जा रहे है। अगर गवर्नर साहब को तीन गुना खर्चा दिया जा रहा है तो बेचारे क्लास तीन और चार के कर्मचारियो ने क्या जुलम कर दिया कि उनको तीन गुना महंगाई भत्ता क्यों नही दिया जाता। 90

हजार रूपये तो केवल उनके दफ्तर का खर्चा बढ़ गया है। मैं नही समझता कि गवर्नर साहब के स्टाफ को चांदी की दवाते दी जाती है या गवर्नर साहब को सोने की दवात दी जाती है इसलिये यह खर्चा बढ़ गया। मैं जानता हूं कि इस आइटम पर वोटिंग नही हो सकती लेकिन मैं फिर भी प्रोटैक्ट करता हूं कि गवर्नर हाउस के खर्चे पर सरकार बहुत गहराई से विचार करे। इसमे खर्च बढ़ने के तीन चार कारण दिये हैं एक कारण दिये हैं एक कारण तो यह है कि कर्मचारियों के महंगाई भते का खर्चा बढ़ गया है। मैंने अंदाजा लगाया है कि महंगाई भता बढ़ने से 21 हजार रूपया का खर्चा आता है। तीन लाख 84 हजार रूपये मे से 21 हजार निकाल लो बाकी का खर्च कहां हो गया ? इसके अलावा गवर्नर के पास तीन व्हीकल्ज होते है लेकिन आप देखें कि हरियाणा के गवर्नर के पास कितने है। मैं इस मामले मे पालिटिकस नही लाना चाहते बल्कि जो गवर्नर के इंस्टीच्यू ान का खर्चा है, उस पर अटैक कर रहा हूं। यहां पर ऐसे गवर्नर रहे है जो पहले कांग्रेसी थी और बाद मे गवर्नर बन गये लेकिन फिर गवर्नि ाप छोड़ कर फिर कांग्रेसी बन गये। तो यह क्या बढ़ा हुआ खर्चा उन बड़े कांग्रेसियों के लिये है ? हमारे लिये यह फिजूल खर्ची अच्छी नही है। डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब पर खर्चे के मामले मे मैं पर्सनली एजीटेटिड महसूस करता हूं और चाहता हूं कि इस खर्चे को कम किया जाये। इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ डिमांडज पर और कहना चाहता हूं। एक बात इसी डिमांड मे और रह गई कि वजीरों पर पहले 1977–78 मे 34.85 लाख रूपये खर्च होता था

और आज 66 लाख 58 हजार रूपया हो गया है यानी लगभग दोगुना खर्चा हो गया है। आप अंदाजा लगाएं कि हरियाणा स्टेट मे तीन साल के अंद वजीरों पर दोगुना खर्चा हो गया है। अगर आप खुद ही इतना खर्चा करोंगे तो आप कर्मचारियों को किस मुंह से कहंगे कि तुम कटौती करो, सेविंग करो, सेविंग करो और वेस्टफुल एक्सपैंडिचर न करो।

स्वामी आदस्विेा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डन हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि ये किस मांग पर बोल रहे है ?

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब मैने बोलते वक्त ही बता दिया था कि मैं डिमांड नं. 2 पर बोल रहा हू मैंबर साहब देख ले कि यह डिमांड पृश्ठ 4 पर है।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 9 के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं जोकि एजुके ान के बारे मे है। इस साल एजुके ान के लिये तकरीबन 54.46 करोड़ रूपया रखा गया था । अब यह सरकार एक करोड़ 20 लाख रूपया और मांग रही है और इस एक करोड़ 20 लाख रूपये के अलावा एक करोड़ 6 लाख रूपये की इस सरकार ने इस डिपार्टमैंट की सेविंग दिखाई है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने अपनी डिमांड मे जो एक करोड़ 6 लाख रूपये की बचत दिखाई है इसमे इन्होंने यह नही बताया कि यह किस मद मे से दिखाई है डिप्टी स्पीकर साहब, मैं, आपकी

मारफत फाईनैंस मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि यह तो एक करोड़ 6 लाख रूपये की सेविंग की गई है, यह किस मद मे से की गई है। एजुके ान और हैल्थ दोनो समाज की भलाई के लिये होती है इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्होंने एक करोड़ 6 लाख रूपये की सेविंग दिखाई है यह रा ि ा इन्होंने एक करोड़ 6 लाख रूपये की सेविंग दिखाई हे यह रा ि ा इन्होंने जिस भलाई के काम के लिये खर्च करनी थी, वहां नही की।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नंबर 13 के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं जो कि सो ाल वैल्फयर एंड रिहैबिलीटे ान के बारे मे है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो हरिजन कल्याण निगम है यह हरियाणा के हरिजन भाईयों को दस्तकारी के लिये और छोटे छोटे कारखानों वाले कामगरो को कर्जा देने के लिये है। यह कार्पोरे ान 1970–71 मे बनाई गई थी । जब यह कार्पोरे ान 1970–71 मे बनाई गई उस समय इसकी पूंजी 25 लाख रूपये थी। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि डिमांड से जाहिर होता है कि 1978–79 के बजट मे स्टेट ने इस कार्पोरे ान के लिये इनवैस्टमैंट भोयर कैपिटल के लिये 15 लाख रूपये का प्रोविजन किया था और इस तरीके से यह इनवैस्टमैंट बढ़ती चली गई। 31 मार्च, 1979 को हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का वर्किंग कैपिटल एक करोड़ 24 लाख 40 हजार रूपये था।

श्री उपाध्यक्षः जैन साहब, आपका समय हो गया है।

श्री मूल चंद जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सारी डिमांडज पर नही बोल रहा हूं। मैं तो जो जरूरी है उन्ही डिमांड पर बोल रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मार्च 1979 मे भारत सरकार का सुझाव आया कि गरीब कामगारो को जयादा मदद देने के लिये हम हरिजन कल्याणर निगम मे 19.51 की रे ाो मे भोयर देने के लिये तैयार है। इस हिसाब से हरियाणा को कुल 51 लाख रूपया लगाना पड़ेगा जिसमे 15 लाख रूपये तो इन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है और 36 लाख रूपया और मांग रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय की जनता सरकार मे जब मैं फाइनैंस मिनिस्टर था तो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने मार्च 1979 मे अपने 49 लाख रूपये के भोयर मे से 9.25 लाख रूपये की रा ि ा रीलीज की थी और जो बाकी का पैसा था वह कंरैट फाइनैन्ि ायल ईयर मे देना था लेकिन वह पैसा अभी तक नही आया है। तो यह 26 लाख रूपए और जो 9.25 लाख रूपये की भारत सरकार ने किस्त देनी थी, वह अभी तक नही दी जा सकी । इसलिये यह 45.25 लाख रूपये की डिमान्ड लाई गई है। मगर यह सारा काम उस समय की जनता सरकार का किया हुआ है और इसका क्रैडिट उस समय की देवी लाल सरकार को जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिमांड नंबर 12 के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं जो कि लेबर एण्ड एम्पलायमैंट के बारे मे है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत इनको जो अनाज मिला वह भारत सरकार की तरफ से मिला है और वह अनाज देकर इन्होंने लोगो से, गरीब मजदूरों से काम करवाया है। लेकिन

जो पैसा इन्होंने लोगों को रोजगार देने के लिये अपने बजट मे रखा थ जेसे फारेस्ट डिपार्टमैंट का है और पी.डब्ल्यू.डी. का है, वह पैसा इन्होंने खर्च नही किया । फारेस्ट और बी. एंड आर. के अपने बजट से जो रोजगार गरीब लोगो के मिलना था, वह न मिला। तो यह कोई तरीका नही है। बेरोजगारों की समस्या के साथ यह एक तरह से खिलवाड़ है। इस तरह से ये लोगों को भूल भुलैया मे डाल रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, फारेस्ट डिपार्टमैंट को इन्होंने 33 लाख 32 हजार रूपये का अनाज दिया और सरकार ने उस डिपार्टमैंट की सेविंग 29 लाख 66 हजार रूपये की दिखाई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये फाईनैंस मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि 29 लाख 66 हजार रूपये की सेविंग इन्होंने किस मद मे से दिखाई है। इसी तरह से पी.डब्ल्यू.डी. को 20 लाख 7 हजार रूपये की कीमत के बराबर का अनाज दिया गया और उनके हैड मे इन्होंने 17 लाख 45 हजार रूपये की सेविंग दिखा दीं डिप्टी स्पीकर साहब, इनको चाहिए तो यह था कि अनाज गवर्नमैंअ आफ इंडिया से आया हे वह तो वर्क चार्ज्ड लेबर को देते ही, उसके साथ साथ जो सेविंग दिखाई है वह रूपया भी उनको रोजगार देने के लिये खर्च किया जाना चाहिए था। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ से जो पैसा गरीबों को रोजगार देने के लिये रखा था, उसको तो यह सरकार बचा रही है और दूसरी तरफ यह क्लेम कर रही है कि हमने गरीबो की भलाई के लिये यह कर दिया, वह कर दिया।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात एग्रीक्लचर के बारे मे कहना चाहता हूं। फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच मे कहा कि सूखे की स्थिति के कारण सरकार द्वारा 1.79 करोड़ रूपया सर्टिफाइड सीडज, खाद तथा कीटना ाक दवाईयों के लिये किसानो को आर्थिक सहायता के लिये केवल 72 लाख 55 हजार रूपये मांग रहे है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके पास एक करोड़ 7 लाख रूपये की सेविंग एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट मे पहले से ही है। तो मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह सेविंग किस मद मे से की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत जो अनाज बांटा गया अगर उसके साथ साथ यह सेविंग का पेसा भी गरीबों पर खच्र कर दिया जाता तो सूखाग्रस्त ईलाकों मे और राहत मिलती।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, यह 1979–80 की अनुपूरक मांगों की पहली और अन्तिम कि त सदन मे रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस का हाउस मे प्रेजैंट किया जाना अपने आप मे बजट की प्लानिंग पर एक रिफलैक ान होता है लेकिन चूंकि सप्लीमैंअरी एस्टीमेटस केवल तभी प्रेजैंट किये जाते है, अगर वह खर्चा बजट मे न रखा गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, एक गृहिणी जब अपने घर का बजट बनाती है तो वह बजट बनाते वक्त छोटा मोटा ऊपर का खर्चा जैसे हारी बीमारी और मेहमानो का खर्च अगर उस

बजट मे भाामिल न करे और रोज अपने स्वामी से जा कर उसके लिये अलग से पैसा मांगे तो उसका स्वामी भी नाराज हो जाता है। वह भी कहताा है कि तुम मेरे से बार बार पैसा क्यों मांगती हो, यह तो नार्मल खर्चा है इसका आपने पहले ध्यान क्यों नही रखा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमैंटरी एस्टीमेअस को पढ़ा और मेरे दिल मे एकदम यह बात आई कि मैं सरकार को बधाई दूं कि उसने इस बार एक दफा ही सप्लीमैंटीर एस्टीमेटस पे ा किये है। (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए) जबकि पहले 3–3 बार किये जाते थे। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने देखा कि इन सप्लीमैंटरी के द्वारा 39 करोड़ 33 लाख रूपये की डिमांड की जा रही है तो मेरी, सरकार को बधाई देने की भावना, बदल गई। इन सप्पीमैंटरी एस्टीमेटस मे आधे से ज्यादा पैसा तो ऐसा है जो सरकार के खिलाफ कोर्टस मे डिग्रियां होने की वजह से सरकार को देना पड़ रहा है। सभापति महोदय, जैसे कि सरकार ने किसी की जमीन एक्वायर की और जमीन मालिक सन्तुश्ट न होने के कारण कोर्ट मे चला गया और कोट्र ने उसके हक मे फैसला दे दिया, इस वजह से सरकार को बाद मे यह पैसा देना पड़ा। इसलिये अगर सरकार पहले ही अच्छी तरह से जांच करके उसको मुआवजा दे तो यह रकम सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस मे लाने की आव यकता न पड़ती। जब सरकार को मालूम है कि लैंड एक्विजी ान के झगड़ों मे लोग कोर्टस मे जाते है और जमीन का मुआवजा बढ़ने की सम्भावना है तो मुआवजा अदा करने के लिये कुछ पैसा सरकार को बजट मे

रख लेना चाहिए ताकि यह अमाउंट सप्लीमैंटरी एस्टीमैंटस मे न आये। हर मद के नीचे एक एक डिक्रिटल अमाउंट की आईटम जोड़ दी गई है, कभी कोर्ट मे ि ाव कुमार चला गया कभी कोई चला गया जिसके कारण सरकार को सप्लीमैंटरी ग्रांटस मे डिक्रिटल अमाउंट मांगना पड़ा।

सभापति महोदय, मांन सं. 2 के बारे मे खास तौर पर कहना चाहती हूं। यह मांग गवर्नर साहब के खर्च के संबंध मे हे और यह जार्ज्ड आईटम है। समय के अभाव के कारण मैं इस पर जयादा नही कहना चाहती। बाबू मूल चंद जैन ने इस मद पर बड़ी खूबसूरती के साथा कहा। मैं बाबू जी की भावनाओं का समर्थन करते हुए यही कहना चाहती हूं कि गवर्नर के खर्चे मे कमी करने चाहिए और खर्चे मे सादगी बरतनी चाहिए। इसके ाबद सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के पेज नं. 4 पर मंत्रियों के लिये 802770 रूपये डिस्क्रि ानरी ग्रांट के लिये मांगे गययें है। ठीक है, जहां तक इस अमाउंट का संबंध है, यह मंत्रियों के अपने घर मे नही जाएगी, किसी की सेवा के लिये, सार्वजनिक लाभ के लिये यह ग्रांट खर्च होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिएं सत्तारूढ़ दल की संख्या 45 है जिन मे से 23 मंत्री पद पर आसीन है। इन 23 मंत्रियों की 23 कारें दौड़ रही है।

श्री सभापतिः आप चाहती क्या है ?

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं चाहती हूं कि कैबिनेअ को फौरन छोटा कर देना चाहिए। (व्यवधान) मुख्य मंत्री को यह नी देखना चाहिए कि सरकार टूट जायेगी या औरक ुछ हो जायेगा। सभापति महोदय, जब ये लोग दिल्ली से चलते हे तो दखने वालो को लुत्फ आ जाता है। कार नं. एच.वाई.ए. 15, 18, 43, 47 यानी सारी मिनिस्टरी कारो मे चण्डीगढ़ से दिल्ली भागी रहती है। 23 कारें चण्डीगढ़ से दिल्ली चलती है। क्या आपने इतनी बड़ी मिनिस्टरी कभी सुनी है। 45 मे से 23 मंत्री बने हुए है और उनकी कारों के आगे झंडियां लगी हुई है। क्या जरूरत है इतने मंत्री बनाने की ? लेकिन जरूरत रहती है और वह हे हालात की मजबूरी । जब इन साथियों पर एस्प र्ान कास्ट होता है जो मुख्य मंत्री महोदय ब्यान देते समय इस बात को भूल जाते है। क्योंकि अगर वे अपने साथियों की कारों पर झंडियां न लगाएं तो मिनिस्टरी टूट जाने का डर रहता है। इनकी मिनिस्टरी का करदार इतना ही है कि कारों पर झंडियां लगाओ और इनको रोके रखो। ये लोग कांग्रेस (इ) की नीतियों की वजह से नही रूके हुए इसलिये जब मुख्य मंत्री बयान देते है तो भूल जाते है कि उनके साथियों पर एक्सप र्ान कास्ट हो रहा है। (व्यवधान) हमारे वित्त मंत्री श्री तायल का बयान आया था, वे गांधीवादी विचारधारा के आदमी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब आप पहले मिनिस्टरी मे आये थे तो 8 मंत्री थे, जब इतनी बड़ी मिनिस्टरी है, इसके बारे मे आपको क्या कहना है ? इन्होंने कहा कि क्या करे, 'नीड आफ दी आवर' है। अगर ऐसा नही करेंगे तो सब कुछ

गडबड़ हो जायेगा। इस प्रकार वे इस चीज को मंजूर करते है कि अगर इनको कार और झंडियां नही देंगे तो मामला गड़बड़ हो जायेगा। सभापति महोदय, इतनी बड़ी मिनिस्टरी से पब्लिक एक्सचैकर पर बहुत बड़ा बोझ है। पब्लिक एक्सचैकर केसे बनता है ? हरियाणा की जनता अपने खून पसीने की कमाइ से टैक्स देती है जिससे पब्लिक एक्सचैकर बनता है। इस पैसे का 23 आदमियों की मिनिस्टरी बनारकर और हर एक को कोठियां और कारें देकर दुरूपयोग नही करना चाहिएं अगर मुख्य मंत्री महोदय अपनी मिनिस्टरी का आकार छोटा कर दे तो पब्लिक एक्सचैंकर पर बोझ कम हो जायेगा।

सभापति महोदय, पेज 4 पर 22 हजार रूपये के डिक्रिटल अमाउंट का खर्चा मांगा गया है। अगर अमाउंट के लिहाज से देखे तो यह रकम कोई ज्यादा नही है। यह चार्ज्ड आइटम है, इस पर बहस तो की जा सकती है लेकिन वोटिंग नही हो सकती। इस आइटम मे लिखा है कि एक वेन दिल्ली से चण्डीगढ़, प्रैस पार्टी को लेकर आ रही थी। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप चुनिए, बडी सनसनीखेज बात है। वैन प्रैस पार्टी को लेकर आ रही थी कि रास्ते मे एक ट्रक एक साईकल वाले को टक्कर मार गिरा कर चला गया। वैन के ड्राईवर को उस पर तरस आय गया और वह उस साईकल वाले को उठाकर हस्पताल ले गया। साईकल वाले के रि तेदारों ने वैन के ड्राईवर के खिलाफ

मुकदमा दायर कर दिया। सभापति महोदय, इन्होंने जो लिखा है वह मैं पढ़ कर सुनाती हूं। इसमे लिखा है–

"The relatives of the deceased filed a compensation suit for 30000 under section 110-A of Motor Vehicles Act, 1939, in the Court of Motor Accidental Claims Tribunal, Karnal and implicated. Jit Singh, the driver of the Publicity Van.

The Motor Accidental Claims Tribunal without placing any credience on the evidnece of Sh. Jit Singh, driver of the Van and also the Conductor of the Van, passed a decree of Rs. 22000 against the Govt."

सभापती महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस दे ा का कानून इतना अंधा है और हमारे प्रदे ा की सरकार इस अंधे कानून को स्वीकार करती है ? ठीक है, सरकार ने उसको पैसा देना था इसलिये उसको इस पैसे का दर्द नही है। जो देना था वह सरकारी खजाने से दे दिया लेकिन मैं पूछन चाहती हूं कि अगर आम आदमी के ऊपर इस तरह का झूठा क्लेम डाल दिया जाये तो वह 22000 रूपये की डिक्री कहां से देगा। एक निर्दोश आदमी, जिसने घायल आदमी की मदद की, और उसके खिलाफ डिक्री दे दी, यह कितनी अन्यायपूर्ण बात है। सभापति महोदय, मैं इस बात को आसानी से नही लेना चाहती, मैं वकील हूं, मैं अच्छीर तरह से जानती हूं कि पब्लिक एविडैंस अगर न हो तो कोई भी ट्रिब्यूनल इस तरह की डिक्री नही दे सकता। सभापति महोदय, मुझे तो इसमे से राजनैतिक बू आती है। कोई न कोई टैस्टिमनी

ट्रिब्यूनल के सामने जरूर आया होगा जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल ने 22000 रूपये का क्लेम दिया है। इसके अतिरिक्त, एक और राजनैतिक बू आती है। मरने वाला झंझाड़ी गांव का रहने वाला था जहां के हमारी माननीय मंत्री चौधरी ि ावराम वर्मा है। हो सकता है इस आदमी को क्लेम दिलवाने मे इनका हाथ हो।

श्री सभापतिः कोर्ट का फैसला हैं इसमे मंत्री जी के हाथ का क्या प्र न है ?

श्री मूल चंद जैनः चेयरमैन साहब, ठीक है कोर्ट का फैसला है लेकिन वैन मे जो प्रैस के आदमी सफर कर रहे थे, उनको कोर्ट ने विटनैस मे क्यों नही पे ा किया गया ? (विध्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः सभापति महोदय, यह चार्ज्ड आईटम है, वोटिंग के लिये नही है लेकिन इस पर बहस हो सकती है। मैंने इस आईटम पर जो सवाल उठाया है वह सदन के सामने है। अगर बिना रिकार्ड के, बिन किसी एविडैंस के, कोई ट्रिब्यूनल इस प्रकार का निर्णय दे दे तो मैं समझती हूं कि सारे इंसान अपनी इंसानियत से हट जायेंगे और एक सामन्य आदमी किसी घायल को देख कर उसे उठाने की हिम्मत नही करेगां ऐसे समय पर वह कहेगा कि मेरे पीछे सरकार नही, मैं कहां से क्लेम दूंगा। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ डिक्री करने की जुर्रत करता हे तो मैं समझती हूं कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नही क्योंकि सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का काम नही कर सकता ।

इसमे किसी वि ोश आदमी का हाथ हो सकता है, इसके बारे मे मंत्री महोदय अपनी मं ाा क्लियर करें।

अब मैं डिमांउ सं. 6 पर आती हूं जिसमे पेमैंट आफ इन्ट्रैस्ट आन जनरल प्रोविडैंट फण्ड का जिक्र किया गया है। इसमे 4369680 रूपयेी की मांग की गई है। सथापति महोदय, मैने भाुरू मे कहा था कि बजट की प्लानिंग करत`समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस मे कम से कम रूपये की मांग की जाये। सरकारी कर्मचारियो को प्रोविडैंट फण्ड इन्ट्रैक्ट देने के लिये सरकार ने बजट मे 57503000 रूपया मांगा था लेकिन अब सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस मे 4369680 रूपये की और मांग की है। 10 हजार, 20 हजार का फर्क हो सकता है लेकिन इतना फर्क नही हो सकता कि लोखो रूपये का फर्क पड़ जायें आप सोचिये कि ये लोग कैसे अजट की प्लानिंग करते हैं? ऐसा लगता है कि ए.जी. महोदय किसी विभाग के आंकड़े लेना ही भूल गये होंगे । तो मैं कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री महोदय जब बजट की प्लानिंग बनवाएं तो सही आंकड़े लेकर बनवाएं । इस तरह तो सरकार की इनऐफिसिएंसी का नतीजा हमारे सामने आता है।

सभापति महोदय, अब मैं पेज नं. 19, डिमांड नं. 7 पर आती हूं। इसमे 1936760 रूपये प्रिंटिंग एण्ड स्टे ानरी डिपार्टमैंट के लिये मांगे गये है। इसमे लिखा है कि–

"In view of the increase int he cost of stationery articles and paper, additional expenditure to the extent of Rs.

1936760 is required to fulfil the demand of the State Government Department during the current financial year."

कहते है कि चूंकि स्टे ानरी आर्टिकल्ज और पेपर आदि की कास्ट इंक्रीज हो गई है इसलिये इस पैसे की जरूरत पड़ी। मैं तो सभापति महोदय यह कहूंगी कि प्रिंटिंग और स्टे ानरी डिपार्टमैंट मे तो लूट मच रही है। सभापति महोदयत्र यह जो लिफाफा आप देख रहे है यह बाजार मे एक या दो नए पैसे का मिल जाता है लेकिन प्रिंटिंग एंड स्टे ानरी डिपार्टमैंट मे 17 पैसे का मिलता है। (विघ्न) पैड 3 रूपये 36 पेसे का मिलता है उसमे तो आठ आने, रूपये की गुंजाय ा है लेकिन यह लिफाफा 17 नए पेसे मे हमें मिलता है। क्या ये इसी बात के लिये हमारे से 1936790 रूपये मांगते है जबकि कास्ट बिल्कुल नही बढ़ी है। हां, डिफरैंस यह है कि इस पर ऐमब्लैम लगी हुई है और बाजार से अगर हम लेंगे तो प्लेन मिलेगा। क्या ऐमब्लैम की छपाई पर इतने पैसे खर्च आ गए ? मुझे समझ मे नही आती कि किस तरह यह डिपार्टमैंट लूट रहा है ? फिर सभापति महोदय, 104620 रूपये इनहे इसलिये चाहिए क्योकिं इन्होंने यू.टी. के प्रैस से ज्यादा से ज्यादा चीजे छपवाईं है। सरदार तारा सिंह जी यहां बैठे हुए है। यह महकमा इनके पास है। आज इस हरियाणा को बने 14 साल होने जा रहे है। क्या इन 14 वर्शो से ये अपने प्रैस को भ इतना सुदृढं नही कर सके, फैला नही सके के कम से कम अपना काम तो उसमे खुद छाप सके। यू.टी. प्रैस, चण्डीगढ़ एडमिनिस्ट्रे ान का प्रैस है। वह अपना काम भ करता है, हरियाणा का मैटीरियल

भी छापता है और पंजाब का मैंटीरियल भी छापता है। लेकिन हमाराप्रैस अपना काम करने योग्य भी नही है। बात तो ये बड़ी बड़ी करते है कि पंचकूला मे प्रैस लगा है, मधुबन मे लगा हुआ है लेकिन मेरी समझ मे नही आता कि वे करते क्या है जबकि यू.टी. एडमिनिस्ट्रे ान के प्रैस से इतना काम हमें करवाना पड़ता है ? मैं अपनी सरकार को सुझाव देती हूं क्योंकि सरदार तारा सिंह जी काफी सूझ बूझ वाले मंत्री है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने के लिये अधिक से अधिक काम अपने प्रैस से करवाएं और यू.टी. एडमिनिस्ट्रे ान को पैसा देने वाली बात पर गौर करें।

सभापति महोदय, अब मै आपका ध्यान पेज नं.35, डिमांड नं. 13 की ओर आकर्शित कराना चाहती हूं। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के बारे मे बाबू मूल चंद जैन जी ने चूंकि काफी कह दिया है इसलिये मैं इस संबंध मे ज्यादा नही कहना चाहूंगी लेकि एक बात सरकार के नोटिस मे जरूर लाना चाहती हूं सभापति जी, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की मैंब्र होने के नाते से इस निगम की वर्किंग को मैंने काफी तफसील से देखा है और मुझे यह कहते हुए संकोच नही है कि जरा भी संतोशजनक इस निगम की वर्किंग नही है। अगर सयम होता और हरिजन कल्याण निगम की रिपोर्ट पर बहस करनी होती तो ऐसी सनसनीखेज चीजे मैं हाउस के सामने रखती जिन्हे सुनकर आप हैरान हो जाते। यह निगम हरिजनो को कर्जा देती है। पी.यु.पी. के चेयरमैन श्री सुमेर चंद भट्ठ यहां नही बैठे है वरना वे मेरी बात को वाच करते।

सभापति जी ट्रैक्टरों के लिये कर्जा दिया गया लेकिन गारंटर के द्वारा हरिजनों से कहा जाता है कि आप गारंटर लाए। सभापति जी आप इनकी वर्किंग के बारे मे जानकर हैरान होंगे। हिसार मे कोई गुलाब सिंह जैन एंड कम्पनी ट्रैक्टर्ज का व्यापार करती है। बजाय इसके कि हरिजनों की तरफ से कर्जे के लिये ऐप्लीके ांज आएं वह गुलाब सिंह जैन एंड कम्पनी ऐप्लीके ान्ज देती है। कहते है कि इन हरिजनों को कर्जा दे दो। मीटिंग के ऐजेंडे मे गारंटर की ऐप्लीके ान्ज पहले कंसिडर हो रही है और जिन हरिजनों को कर्जा दिया जा रहा है उनकी ऐप्लीके ान्ज ही नही है। (विघ्न) ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि उनका पोलिटिकल पुल था। (विघ्न) उनको पैसा दे दिया गया क्योंकि वह सरकार का एक अच्छा फाईनैंसर है।

श्री सभापतिः कौन सी सरकार का ? (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः कांग्रेस सरकार का। (विघ्न)

श्री सभापतिः अब किसके साथ है? (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः कांग्रेस भी कई किस्म की हो गई है। कोई कांगेस (आई) है कोई कांग्रेस (यू) है कोई कांगेस (मैं) है और कोई कांग्रेस (तू) है इसलिये मैं इंदिरा गांधी की सरकार का कहती हूं। (ाोर)

तो सभापति महोदय, मैं यह कह रही थी कि गारंटर की ऐप्लीके ान पर सैटिसफाई हो करके हरिजनों को कर्जा दे

दिया गया। उनकी ऐप्लीके ान्ज बाद मे ली गई लेकिन आज ये हरिजनों के पीछे घूम रहे है। सारे के सारे हरिजन डिफाल्टर्ज बने हुए है। ये कहते है कि इन इन हरिजनों के नाम कर्जा है उसे वापिस लेकर आओ। डिप्टी कमि नर उनके पीछे रिकवरी आफिसर भेज देता है। (विघ्न) सभापमि जी समाज के पिछड़े हुए वर्ग की सेवा करने के लिये यह निगम बनायी थी। सोचा था कि यह उनकी सेवा करने के उनके झूठे अंगूठे लगाकर रिकवरी अफसर उनके पीछे लगा दिये। यह कितनी गलत बात है ? (विघ्न) तायल साहब तो स्वयं पी.यू.सी. के चेयरमेन रहे है। इनको चाहिए कि ये सारी कार्पोरे ान्ज के अधिकारियो को बुला करके उनसे अपनी काम को अच्छी तरह से करने के लिये कहे। मुझे अफसोस है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इस निगम मे धांधली हो रही है और उसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया गया है। (विघ्न) सभापति जी इसी पृश्ठ पर एक आइटम है– 'Grant-in-aid to poor distitute and handicapped persons.' इसके लिये टोकल डिमांड 10 रूपये की रखी गई है। मैं इसका विरोध नही करना चाहती। इसमे लिखा गया है कि कुछ डैस्टिच्यूटस और डिसएवल्ड लोगो को ग्रांट देने के लिये यह पैसा चाहिए । मुख्य मंत्री जी जब दौरा पर जाते है तो इस तरह के लोग मदद के लिये उनके पास आते है। पोसीजरल रिक्वायरमैंअस के मुताबिक ग्रांट देने मे चूंकि काफी समय लग जाता है इसलिये आन दि स्पौट ग्रांट देने के लिये यह एक लाख रूपया मांगा गया है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि कोई विरोध नही कर रही हूं। लेकिन एक बात

मुझे अखर रही है कि जिसके बारे मे जानना चाहती हूं। इस डिमांड के आइटम नंबर एक मे अंत की लाईन पर लिखा हुआ है– "Since savings are available within the grant, a token demand of Rs. 10 only is presented for the vote of Legislature." सभापति महोदय, अगर एक लाख रूपया अलग से मांगा जाता और सदन के सामने वोटिंग के लिये रखा जाता तो मैं खु ाी से वोट देती ओर दूसरे सदस्यो को भी कहती कि बड़ी अच्छी अनुपूरक मांग है इसे पास किया जाये। परंतु मेरी समझ मे यह बात नही आती कि कौन सी और कहां से सेविंग इस विभाग के पास अवेलेबल है जिससे यह एक लाख रूपया दे रहे है। सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट के पास तो ओल्ड ऐज पै ान की बेइंत्ताह एप्लीके ान पैंडिंग है फिर यह सेविंग कहां से हो गयी ? जब मैं इस विभाग की मिनिस्टरी थी उस समय पर वैलफेयर डिपार्टमैंट के सैक्रेटरी को कहती थी कि फलां आदमी को पैं ान दे दो तो वे कहा करते थे कि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा मे एप्लीके ान्ज पैंडिंग है इसलिये हम तो उसी हिसाब से पैं ान देते है जिसकी पहले एप्लीके ान आयी है उसको पहले दैंगे और जिसकी बाद मे आयी हैख उसको बाद मे देंगे। उनका जवाब यही होता था कि हमारे पास पैसा नही है।

सभापमि महोदय, पिछली बार बजट पर बोलते हुए मैंने सरकार से गुजारि ा की थी कि इस पैसे को बढ़ा दिया जाये। मुझे बड़ी खु ाी है कि कल वित्त मंत्री महोदय ने बजट पे ा करते हुए उस रा ि ा को बढ़ा दिया है। पिछले वर्श तक 8700

आदमियों को पैं ान दी जाती थी तब सन् 1980–81 मे और दस हजार व्यक्तियों को पैं ान दी जायेगी । मेरी समझ मे यह बात हनी आती कि इसमे सेविंग कैसे हुई, इसमे तो हमे ाा ग्रांट कम पड़ती थी। मैं यह कहूंगी कि महकमे का इतना पेसा बचे तो उसकी इन एफिसेन्सी है। यह भी मैं मान सकती कि उन के पास आर्गेनाइजे ान है। ओल्ड ऐज पें ान के केसिज भी इनके पास होंगे। मैं तो यह जानना चाहती हूं कि फिर यह ग्रांट कहां से बची हुई है। इस बारे मे सुझाव दूंगी की जितने भी ओल्ड ऐज पै ान के केसिज है पहले उनको निपटाया जातां यह तो दस रूपये की ओकन डिमांउ लाये है, उसकी बजाए एक लाख रूपये की अलग से डिमांड ले आते तो हम खु ाी से वोट करके पास कर देते। परन्तु हमारी जो आलरेडी एप्लीके ान्ज निपटायी जा सकती थी और इस एक लाख रूपये के लिये अलग डिमांड ले आते। मैं इतना कह कर खत्म करती हूं

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): सभापति जी, अभी बहिन सुशमा जी ने जितनी बातें रखी है उनके विशय मे मुझे कहना पड़ेगा कि ''कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुन्बा जोड़ा'' (विघ्न)

श्री सभापतिः हाउस बड़ा भाान्ति से चल रहा है। आप उनकी बात तो सुनें

श्रीमती सुशमा स्वराजः सभापति जी, जब मैं बोल रही थी तो आप बड़े ध्यान से मेरी बात तो सुन रहे थे लेकिन स्वामी जी कह रहे है कि ''कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुन्बा जोड़ा''

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति जी, मेरे से पूर्व बोलने वाले भाई यदि इन डिमांडज के प्रावकथन को पढ़ लेते तो एक एक बात का पता चल जाता । हमारी सरकार ने सारी अनुपूरक मांगे 39.33 करोड़ रूपये की रखी है। इसमे 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिये 21.36 करोड़ रूपये की मांग भी भाामिल है।

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। सभापति जी डिमांड पर बोलते हुए स्पैसीफायी करना पड़ता है कि कौन सी डिमांड पर बोलना है। स्वामी जी को तो यह पता ही नही है कि वे कौन सी डिमांड पर बोल रहे है ? (ाोर)

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।

डॉ. मंगल सैनः तायल साहब यह बात ठीक फरमा रहे है ताकि वे फ्री स्टाइल न हो सके ओर स्पैसिफिक डिमांड पर कंसंट्रेंट कर सकें।

श्री सभापतिः यह आप पूछेंगे या मैं पूछूंगा।

डॉ. मंगल सैनः आप ही पूछेंगे लेकिन डिमांड नंबर तो बताना चाहिए।

स्वामी आदित्यवे ाः मैं डिमांड नं. एक से लेकर 25 तक बोल रहा हूं। (ाोर)

श्री बलदेव तायलः सभापति जी, एक से लेकर 25 तक कहने से काम नही चलेगा। इनको डिमांड नंबर स्पैसीफायी करनी चाहिए कि किस पर बोलना चाहते है। (विघ्न)

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति जी, वित्त मंत्री महोदय ने बड़े स्पश्ट भाब्दों मे 21.36 करोड़ रूपये 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिये मांगा है। 39.33 करोड़ रूपये की कुल अतिरिक्त मांग, या तो प्रति समंजनों अथवा भारत सरकार, एन.सी.डी.सी. द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा ''समतुल्य अनुदान स्कीम'' के लिये जनता के योगदान से 25.31 करोड़ रूपये तक कम हो जाने की सम्भावना है और जो भोश 14.2 करोड़ रूपये है वह पिछला जो हमारा 227 करोड़ रूपये का प्लान था उसमे 196 करोड़ रूपया खर्च हुआ है, उसमे जो बचेगा वह इसको पूरा कर देगा। इसलिये इन अनुपूरक मांगों से हमारे खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नही पड़ेगा। हमारी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि तीन करोड़ रूपये से ज्यादा एमपलाइज को महगांई भत्ते आदि का दिया है और एक करोड़ रूपया हमारी पुलिस की वर्दी, अलाउंस तथा उनको एक माह का अतिरिक्त वेतन के लिये

दिया गया है। इसी प्रकार से ओलावृश्टि के कारण किसानो की जो फसल तबाह हुई थी, उसके लिये छः करोड़ पांच लाख रूपया दिया है और हरियाणा मे जो सूखा पड़ा है। उसका मुकाबिला करने के लिये 72 लाख रूपया दिया गया है। कम से कम अपोजी ान के भाईयो को अच्छी बात तो कह देनी चाहिए। सभापति महोदय, इस सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि समाज का जो आखिरी आदमी है जिसको कोई पूछता भी नही था उसके लिये साल लाख 27 हजार रूपया दे कर, पचास रूपये महीने के हिसाब से तन्खाह बढ़ायी है। हमारे वाल्मीकि भाईयों की पचास रूपये महीने के हिसाब से तन्खाह बढ़ा दी है जो आज तक किसी सरकार ने नही बढ़ायी थीं

श्री बलदेव तायलः चेयरमैन साहब अब तक ये किसी भी अनुपूरक मांग पर नही बोले है इसलिये मेरी गुजारि ा है कि ये पहले समाज के प्रचारक थे और अब से भजन प्रचारक है।

श्री सभापतिः आप पढ़े लिखे काबिल आदमी है, इनको भी बोलने दें।

डॉ. मंगल सैनः सभापति जी, गुस्ताखी माफ। आपने अभी फरमाया कि बलदेव तायल तो आप तो काबिल आदमी है तो क्या उनकी काबलियत पर आपको भाक है ?

श्री सभापतिः मुझे किसी की काबलियत पर भाक नही है।

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति जी, पता नही इन सब लोगों को किस बात का फोबिया हो गया हे, बोलने की नही देते है। हम इनकी सारी बाते सुनने के लिये तैयार है (ाोर) लेकिन ये हमारी कोई भी बात सुनने के लिये तैयार नही। (ाोर) बिना सोचे समझे ही बात कहना भाुरू कर देते है। अभी पहले कोई साथी कह रहे थे कि गवर्नर साहब के ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर रहे है। अगर वे इन डिमांडज को ध्यान से पढ़ लेते तो उनको पता लग जाता कि वह पैसा किस लिये मांगा जा रहा है। यह पैसा वहां के एम्पलाइज के लिये और वहां जो फोर्थ एम्पलाइज है, उनकी वर्दी के लिये मांगा जा रहा है।

जनता सरकार ने अपने टाईम पर कभी नही सोचा कि एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये किस तरह से बिल पे ा किये गये । (ाोर) ये उस बात की तरफ ध्यान नही देंगे और कोई न कोई अपनी ही बात कहने की कोि ा ा करेंगे। जब ये लोग दूसरों को आरोपित करते है तो उसका उत्तर सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए लेकिन इनकी ये हिम्मत नही है कि दूसरो की बात भी सुन ले। यहां पर हवाई गोले छोड़ कर चले जाते है। नैतिकता तो यह है कि अपने सवालों का भी इनको उत्तर सुनना चाहिए और सदन मे जो भी बात कही जाये वह भी जिम्मेदारी सेै कहनी चाहिए। (ाोर) सभापति जी, पिछली बार इसी सदन मे एक बिल आया था जो सदस्यो को पैं ान देने के बारे मे था। उसमे यह लिखा हुआ था कि जो भी भूतपूर्व विधायक है, उनको भी

पैं ान दी जायेगी। उससे स्टेट के खजाने पर लाखों रूपये का खर्चा बढ़ेगा। इस पैं ान बिल को इसलिये लाया गया था कि साहब राम जी जो चौधरी देवी लाल भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर के भाई है, उनको भी पिछली डेट से पैं ान मिल जायेगी। पिछली तारीख से लाने का उनका यही मकसद था। (ाोर) इन्होंने इस बात पर उस समय यहां हाउस मे कोई चर्चा नही की क्योंकि उन्होंने पैं ान लेनी थी।

चौधरी गंगा रामः सभापति जी * * * *

* * * * * * * * * * *

*

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

श्री सभापतिः जो कुछ चौधरी गंगाराम ने कहा है यह एक्सपंज कर दिया जायें

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक गांव मे जहा पर आबादी 2000 से ज्यादा होगी वहां पर कन्जयूमर्ज स्टोर खोले जायेंगे। 73 लाख 18 हजार रूपये की रा ि ा इस प्रकार के कंजयूमर्ज स्टोर खोलने के लिये खर्च की जा रही है। 214 गांवो मे इस प्रकार के भण्डार खोले जायेंगे।

पहले हरियाणा के भाहरों को ही ये सुविधाएं मिलती थी लेकिन अब ये सारी सुविधाएं मिलती थी लेकिन अब ये सारी सुविधाएं मिलती थी लेकिन अब ये सारी सुविधाएं गांवों तक भी पहुंचाने के लिये यह सरकार प्रयत्न ाील है। (ाोर) इनको कम से कम जो अच्छी बाते है उनकी तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये जो अच्छी बाते होती है उनमे वे अच्छे भाब्द निकाल कर बुरे भाब्दो को एलैबोरेअ करने की कोि ा ा करते है। (ाोर)

श्री सभापतिः आप लोगों को भी बोलने का समय मिलेगा, बीच मे न बोले।

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति जी, इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किये है, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार ने कल करोड़ो रूपये का बजट इस हाउस मे रखा लेकिन एक पैसे का भी टैक्स नही लगाया । यह हरियाणा की पहली ऐतिहासिक घटना है। इस सरकार ने किसी गरीब पर, किसान पर या मजदूर पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नही लगाया। कितने वर्क चाईड कर्मचारी थे उन को भी काफी लाभ हुआ है। (ाोर) सभापति जी, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो लोगों के मकान गिर गये थे, किसानो की फसले नश्ट हो गई थी तथा गांवो के अंदर बीमारी फैली हुई थी फिर भी उस समय चौधरी देवी लाल की सरकार ने उनके 93 लाख रूपया चंदे के रूप मे इकट्ठा किया और उन पर नाजायज बोझ डाला। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस साल दोनो फसले खराब हो गई है

लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नही लगाया। इसी प्रकार इस सरकार ने प्रत्येक वर्ग को हर प्रकार से सुविधा जुटाने की पूरी पूरी कोि ा ा की है। (ाोर) ये जो अनुपूरक मांगे सदन के सामने रखी गई है, इससे हमारे खजाने के ऊपर कोई बोझा नही पड़ता है। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इन अनुपूरक मांगो को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आप का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं सबसे पहले डिमांउ नं. 2 पर बोलना चाहता हूं। स्वामी जी ने बड़ी बड़ी बातें इस सरकार के बारे मे कही है। उन्होंने खुद सप्लीमैंटरी डिमांडज को नही पढ़ां इनमे अगर खुद मे कोई नैतिकता होती तो वे इतनी बड़ी बातें न करते। इनको यह भी नही पता कि ये कहां से आए है और कहां पर चले गये है। इनको यह भी पता नही कि असैम्बली की तरफ से एक किताब छपती है जिसमे प्रत्येक विधायक का परिचय होता है जिसको 'हूइज हूं' कहते है। (ाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्वामी जी जब से स्वामी बन कर आयें है जब से यही पर बैठे हुए है।

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है। चौधरी संत कंवर जी आप अपनी डिमांड पर बोलिये ताकि मंत्री महोदय जवाब दे सके।

चौधरी संत कंवरः सभापति जी, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। चेयरमैन साहब, इस असैम्बली मे एक कानून पास किया गया है कि मैंबरो को कारों और मकान के लिये लोन मिलेगा लेकिन मैं सदन को आप की मार्फत यह बताना चाहता हूं कि जो लोन उगाहने का तरीका है वह नही बताया गया है। (ाोर) हमारी यह बदकिस्मती है कि यहां हाउस मे ऐसे मैंबर भी बैठे है जिन्होंने न अपने बाप का नाम लिखा है, न अपनी मां का नाम लिखा और और न ही यह बताया कि वे कहां पर पैदा हुए है। उनका कोई अता पता नही है। मैं स्वामी आदित्यवे ा जी का नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने न अपने बाप का नाम किताब मे दिया है और न ही अपनी मां का नाम दिया और न ही यह बताया है के वे कहां पैदा हुए है (ाोर) तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो विधायकों को लोन दिया जा रहा है यह उनसे किस तरीके से वसूल करेंगें।

श्री सभापतिः यह सरकार का कार्य है। सरकार अपने आप वसूल करेगी।

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जब स्वामी जी बोल रहे थे तो कह रहे

थे कि स्वामी जी कि डिमांड पर बोल रहे है। तो मैं इसी विशय मे आपके द्वारा अपने साथी से पूछता हूं कि वे किस डिमांड पर बोल रहे है ? (ाोर)

चौधरी संत कंवरः चेयरमैंन साहब, मैं मंत्रियों और सदस्यों के भत्ते की डिमांड पर बोल रहा हूं। सभापति जी, जो लोग नैतिकता की बात करते है उनमे खुद मे कोई नैतिकता नही है। हमारे हिन्दु धम्र मे अग्नि के सामने बैठ कर पति पत्नी एक सूत्र मे बंधते है और वचन लेते है, लेकिन स्वामी जी, उस सूत्र को भी तोड़ा है, नैतिकता को तोड़ा है, असूलों को तोड़ा है। (ाोर) (इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य चौधरी राम कि ान, पदासीन हुए)

चेयरमैंन साहब, मैं अब एक बात डिमांड नं.2 के बारे मे कहना चाहता हूं । इस डिमांड मे 12½ लाख रूपये की रा ि ा रखी गई है यह सारे का सारा पैसा हमारी मंत्रि परिशद गलत ढंग से खर्च कर रही है। लाखों रूपया टी.ए/डी.ए. पर खर्च किया जा रहा है चेयरमैंन साहब जो मंत्री दौरा करते है उनकी पोजी ान यह है कि मैं उस मंत्री महोदया का नाम नही लेना चाहता। वह सोनीपत जिले के एक कौमी गांव मे गई थी। उस गांव के लोगो ने बैठकर यह फैसला किया कि जो मैंबर पार्टी बदल कर, भारत भ्रमण करके आएं है और जिन्होंने हरियाणा के नाम को कलंग लगाया है ऐसे आदमियों के हम द ान नही करेंगे। जब वे मंत्री महोदया गांव मे गई तो वहां पर पब्लिक रिले ान्ज डिपार्टमैंट के

आदमियो के सिवाए कोई भी आदमी नही था। (ाोर) तो गांव के आदमियों ने जब यह फैसला किया हो कि इनसे नही मिलना तो मंत्री महोदया ने यह सोचा कि गांव के 5–7 आदमियो को पौली मे बिठाकर बात की जाये। मंत्री जी उनसे मिले के लिये गांव मे नकली तो सामने से दो आदमी आ रहे थे। उन्होंने इनको नमस्ते भी नही की। लेकिन जब वे नजदीक आ गये और उन्होंने देखा कि भई यह तो मंत्रिमण्डल की एक यदस्या है, तो वे भाग कर घरों के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। गांवो मे ऐसा व्यवहार हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यो के साथहो रहा है जिनके ऊपर लाखो रूपया खर्च कर रहे है। चेयरमैन साहब, मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह दल बदलुओ की सरकार और यह अस्थायी सरकार हरियाणा की जनता के खूद पसीने की कमाई का पैसा खर्च कर रही है, उसके लिये हरियणा की आने वाली पीढ़ियां इनको कभी भी माफ नही करेगीं ये कहते है कि हमने तो जनता के मैनडेट को माना है जनता के कांग्रेस (आई) के हक मे फैसला दिया, इसलिये हम उधर चले गये। अभी कुछ दिनों मे नौ विधान सभाओं के लिये चुनाव होने जा रहे है। हरियाणा का भी साथ ही मे चुनाव हो जाता तो ठीक था। खैर, अब भी चुनाव हो कर रहेगा, यह मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चुनाव होने के बाद ये कांग्रेसी नही, यहां पर लोग दल और जनता पार्टी के ही सारे सदस्य मिलेंगे। (व्यवधान व भाोर) मैं तो यह कहता हूं कि 9 विधान सभाओं के

चुनाव हो जाने के बाद आप सब लोग कांग्रेस को छोड़कर वापिस इधन ही आओंगे।

श्री सभापतिः आपके 8 मिनट हो गये है, दो मिनट बाकी है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कंवरः चेयरमैंन साहब, डिमांड नं. 9 एजुके ान के बारे मे है। एजुके ान के बारे मे स्वामी जी ने बड़ी बड़ी बाते की । आज हालत यह है कि गांव के गरीब आदमी का बच्चा जिस स्कूल मे पढ़ने के लिये जाता है, वहां पर कमरे नही है। एक एक कमरे मे स्कूल खोल रखा है और एक ही वहां पर अध्यापक रखा हुआ है। एक नही, सारे प्राइमरी स्कूल ही ऐसे है। मैं एक बात को चीफ पार्लियामैंट्री साहिबा ने नोटिस मे लाना चाहता हूं कि अध्यापकों को आपसे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि आप भी उसी वर्ग से संबंध रखती रही है। (व्यवधान व भाोर) करोड़ो रूपये खर्च करके पब्लिक स्कूल खोले गये है जैसे राई मे स्कूल है, जहां पर अफसरों के और धनाढ़यों के बच्चे पढ़ते है। उनके मुकाबिले मे उन स्कूलों के लिये जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते है, कोई भी पैसा नही रखा गया है। अगर आप इस विभाग को ऊपर उठाना चाहती है तो सबसे पहली बात इस दि ाा मे करनी चाहिए कि गरीब आदमी के बच्चे मे इन्फीरीयरिटी कम्पलैक्स न आने पाये। एक ओर तो पब्लिक स्कूल्ज है जो इस दे ा मे आजादी के बाद से फ्रीली पनप रहे है और दूसरी ओर ऐसे स्कूल्ज है जो गरीब बच्चों के लिये है। इस दोहरी ि ाक्षा नीति के बारे मे

हरियाणा सरकार को तुरंत फैसला देना चाहिए कि प्रदे ा के अंदर से दोहरी ि ाक्षा नीति को समाप्त किया जाये ताकि चौधरी खुर ाीद अहमद का और एक गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े और बहिन भाांति राठी का और एक गांव के आदमी का बच्चा एक साथ पढ़े।

मैं डिमांड नं. 12 पर भी कुछ बोलना चाहता हूं। स्वामी जी ने 'फण्ड फार वर्क' प्रोग्राम का जिक्र किया। वे गांव के अंदर जाकर तो देखते नही है, वैसे ही बोल देते है। यह स्कीम तो बहुत बढ़िया है। आपके अफसर तो इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से लागू करना चाहते है लेकिन आपकी कांग्रेस (आई) पार्टी के कुछ कार्यकत्र अफसरों पर दबाव डालकर घपला करना चाहते है। मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बी.डी. ओज. पर नाजायज दबाव डाल कर इस 'फण्ड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत जो अनाज दिया जाता है, उस अनाज को बेच कर पैसे अपनी जेबो मे डालना चाहते है। इसलिये मैं खास तौर पर अपनी सरकार से जिसमे बड़े पुराने पुराने मैंबज साहेबान भाामिल है, तायल साहब जैसे लोग इसमे भाामिल है, निवेदन करूंगा कि वे इस बात की तरु ध्यान दे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस 'फण्ड फार वर्क' प्रोग्राम का मिसयूज करना चाहते है, बी.डी.ओज. पर प्रै ार डालकर अनाज बेचकर पैसे अपनी जेबो मे डाल रहे है, इस बात को रोके। इस तरह के हालात तो इस प्रदे ा के अंदर चल रहे है। चेयरमैन साहब, मै एक बात कहकर अपना स्थान लूंगा

। ये जो सारे 'भाई' कांग्रेस (आई) मै बैठे हुए है (विघ्न व भाोर) ये इस बात को खुद भी सोचते है कि जनता के सामेन कभी न कभी तो जाना पड़ेगा ही। अभी तायल साहब ने (व्यवसाय व भाोर) कल जो बजट पे ा किया, उससे यह साफ जाहिर है कि आप लोगो को 15 दिन के अंदर जनता के दरबार मे फिर जाना पड़ेगा। जनता आपको बख्भोगी नही । जनता आपको इस बात के लिये वाजिब सजा देगी, जो आपने इस प्रदे ा की जनता के साथ धोखा दिया है।

चौधरी रिजक राम (राई): चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नंबर 3, 4 और 17 के ऊपर बहुत थोड़े से भाब्दों मे अपने विचार रखता हूं। डिमांड नं. 3 मे चुनावों और पुलिस के बारे जिक्र है। इस डिमांड मे चुनावों के लिये हुए खर्च की मांग की गयी है। चेयरमैन साहब, ये जो चुनाव हुए, इसमे एक विचित्र और अजीब सी बात सामने आयी जो भाायद आज तक किसी भी चुनाव के सामने नही आयी। जनता पार्टी और लोक दल की ओर से, जातिवाद मे खूब प्रचार किया गया। भाायद इतना जातिवाद का प्रचार पहले कभी नही किया गया था। (व्यवधान व भाोर)

आवाजे: ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे है ?

चौधरी रिजक राम: मैं डिमांड नं.3 पर बोल रहा हूं। जनता पार्टी के बड़े ही जिम्मेवार नेताओ ने बाबू जगजीवन राम के नाम पर जात बिरादरी का जहर फैलाया और इस बात का प्रचार

किया कि आप हमें राय दो ताकि आपका एक हरिजन भाई प्रधान मंत्री बन सके। इसी तरह से लोक दल ने भी जातिवाद का प्रचार किया। (व्यवधान व भाोर) मैं यह बात बड़ी जिम्मेदार के साथ कह सकता हूं कि अगर ये पार्टियां लोक सभा इलैक ान मे कामयाब हो जाती तो इस दे ा मे जातिवाद की जड़े मजबूत हो जाती । ई वर ने यह अच्छा ही किया कि इन पार्टीज को चुनावों मे ि ाकस्त दी। इन पार्टीज के मुकाबिले मे यह जो इलैक ान हुए है, उन मे जातिवाद को दबाने के लिये इंदिरा गांधी ने बड़ा भारी योगदान इस दे ा के लिये दिया है। लेकिन मैं इस बात इस सिलसिले मे जरूर कहना चाहता हूं कि इस चुनाव मे आमतौर पर अफसरान का व्यवहार सराहनीय रहा है। किसी ने भी पक्षपात से काम नही लिया लेकिन इसके बावजूद भी कूछ बड़े अफसरान को परे ाान किया गया, उनको तबदील किया गया। चेयरमैंन सहाब, तैं आपके द्वारा यह अज्रग करना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान अफसरान का रवैया बड़ा अच्छा रहा है। वे किसी पक्षपात मे नही पड़े। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि नीचे स्तर के जो अफसर है अगर उनको जातिवाद के नाम पर परे ाान किया जाता हो, तंग किया जाता हो तो उसको दूर किया जाये। मेरा कहना यह है कि अगर अफसरान तक राजनीति चली गई और अफसरान ने किसी पार्टी से हमदर्दी रखते हुए अपने नीचे के लोगों की तरक्की करने या तबदील करने का सियार कायम किया तो राजनीति और प्र ाासन को बड़ा धक्का पहुंचेगा। इसलिये इस मामले मे मेरी प्रार्थना है कि सारा मंत्रिमण्डल सचेत

रहे है कि उनके मातहत कर्मचारी और खासतौर से पुलिस के कर्मचारी इस तरह का व्यवहार न करे। चेयरमैन साहब, पुलिस के कुछ ऊपर के दर्जे के अफिसर्ज इलैक ान्ज से पहले भी और इलैक ान्ज के बाद भी जातिवाद की बिनहा पर, जात बिरादरी की विनहा पर अपने नीचे के अफसरान की तबदीली और उनकी तरक्की मे ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे है। हालांकि वे रि तेदार भी है लेकिन रि तेदारी को भुलाकर एक बिरादरी के अफसरान को ज्यादा से ज्यादा तंग करने का बतीरा अख्तियार किया हुआ है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री के नोटिस मे यह बात न हो इसलिये मैं खास तौर पर यह बात उनके नोटिस मे लाना चाहता हूं कि अगर पुलिस जो ला एंड आर्डर की जिम्मेदार है, उसमे पार्टीबाजी हो और बिरादरी की बिनहा पर तबदीलियां और प्रोमो ान की जाये तो सारी स्टेट का इंतजाम खराब हो जायेगा। पुलिस का एक अफसर चाहे वह कितना ही बड़ा क्यो न हो अगर वह किसी एक खास बिरादरी के आदमी को, किसी खास जाति से संबंध रखने वाले आदमी को तबदील करता है, एक खास बिरादरी के आदमियों को अच्छी जगहों से निकालकर खराब जगहों पर भेज देता है तो यह खराब बात है। मैं आ ाा करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय, उस पुलिस के अफसर को, जिसने कई महीने से इस तरह का रवैया अख्तियार किया हुआ है कि जाति के बहाने से, चुनाव के बहाने से, बिरादरी के बहाने से कि फंला बिरादरी ने कांग्रेस को या जनता को वोट नही दिये और उस बिनहा पर छोटे अफसरों को सजा दी जाये अच्छी बात नही है, उस को समझाने

का प्रयत्न करेंगे जिससे कि पुलिस के निजाम मे कोई असंतोश न हो, कोई खराबी न हो।

चेयरमैन साहब, अब मैं लैंड रिफार्म के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, 1953 मे पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर एक्अ किया गया । इससे पहले से लैंड रिफार्म की चर्चा चली रही थी। 1952 मे पहले चुनाव हुए और उससे पहले जमींदारा सिस्टम को खत्म किया गया। 1972–73 मे इस एक्ट मे फिर तरमीम की गई। चेयरमैन साहब, इस अर्से मे इस कानून के बारे मे जितनी लिटिगे ान हुई उतनी किसी और कानून के बारे मे हनी हुई। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि जमीन के बारे मे इस ढंग से कानून बनाया गया कि उसको न वकील समझ सके, न जज समझ सके बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए वे भी एक दूसरे से मुतजाद थे। उस एक्ट की सैक ान के मायने क्याहै इसके बारे मे फैसला लेने के लिये लोगो के लाखो रूपये खच्र हो गये। चेयरमैन साहब, आज अंदाजा यह है कि दे ा मे पचास लाख एकड़ भूमि सरप्लस है। इसमे से 44.45 लाख एकड़ भूमि के बारे मे निर्णय दिया गया कि यह सरप्लस है और यह भी बतायाग या है कि पंद्रह सोलह लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर गुजारे बैठे हुए है। चेयरमैन साहब, 1953 से आज तक की पोजी ान यह है और आप देख सकते है कि इन 26–27 साल के अन्दर एक तिहाई जमीन पर मुजारे बिठाये जा सके है। चेयरमैन साहब, 1972 मे डिस्ट्रिक्ट रोहतक मे एक सर्वे किया गया और आप यह जानकर

हैरान होंगे, उस सर्वे कमेटी को यह रिपोर्ट है कि अगर किसी जगह सौ मुजारे बिठाए गये है तो उन सौ मुजारो मे से केवल बारह मुजारे ऐसे है जिनका जमीन पर कब्जा हुआ है बाकी का कब्जा नही हुआ है। जब उनको कब्जा नही मिलता तो वह जमीन सरप्लस नही रह पाती है और इस सरप्लस जमीन के कारण देहात मे बहुत खींचातानी है, बहुत ज्यादा भेदभाव देहात के अंदर पैदा हो गया है। हरिजन भाई यह कहते है कि उनको जमीन नही मिलती और किसान भाई यह कहते है कि उनकी जमीन ये हरिजन भाई ले लेंगे। पिछले तीस साल से यह चल रहा है, न किसी की जमीन छीनी गई और न किसी को जमीन दी गई है। चेयरमैन साहब, आप भी देहात के रहने वाले है और आपका देहात के साथ गहरा संबंध है। आपको पता हे कि पिछले तीस साल के अंदर यह निर्णय नही हो पाया है कि किससे कितनी जमीन लेनी है और किसको कितनी देनी है और अब भी यह फैसाल नही हो पा रहा है। चेयरमैन साहब इस प्र न की वजह से कि कितनी जमीन सरप्लस है, कितनी जमीन किसी को लेनी है, कितनी जमीन किसको देनी है, देहात मे बहुत तनाव है। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि लैंड रिफार्म के मसले को प्रायरिटी देकर जितनी जमीन लेनी है उसको लेकर जिनको देनी है उनमे तकसीम कर दे ताकि देहात मे कंफिलिक्ट पैदा नह हो और जो रोश देहात के लोगो मे फैला हुआ है वह खत्म हो जाये। चख्येरमैन साहब, आप देखे कि बिहार के अंदर नक्सलाइटस जमीन के मसले को लेकर हरिजनो तथा गैर हरिजनो को भड़काते फिर हरे है, वहां पर कई

जमीदारो का कत्ल भी हुआ है। अभी पिछले दिनो पंद्रह सोलह आदमियो का कत्ल कर दिया गया। यह सब इस चीज का परिणा महै इसके साथ ही साथ चेयरमैन साहब, मै यह बताना चाहता हूं कि आज जमीन की पोजी ान क्या है। 1961 मे 16 परसेंट किसान ऐसे थे जिनके पास पांच एकड़ जमीन थी और आज 73 परसैंट किसान ऐसे हे जिनके पास पांच एकड़ भूमि है या उससे कम है। एक एक एकड़ के बिस्वेदार 39 फीसदी थे जो आप पचास फीसदी हो गये हैं एग्रीक्लचरल मजदूरो की तादार अठारह उन्नीस लाख थी जो बढ़कर उन्ततीस लाख हो गई हैं मजदूरो की तादाद बढ़ती जा रही है। किसानो की तादाद, खेती करने वाले की तादाद घटती जा रही है। जो होल्डिंग्ज थीं वे घटती जा रही है। जहां 73 फीसदी आदमी ऐसे हो जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन हो, वहां पर किससे जमीन ली जाये और किसको दी जायें इस बारे मे जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिये।

चेयरमैंन साहब, अब मैं स्टाफ बिल्डिंग्ज के बारे मे कहना चाहता हूं क्योंकि इनके लिये रूपया मांगा गया है। सरकार ने अभी नइए डिस्ट्रिक्टस बनाए है जैसे फरीदाबाद, सिरसा लेकिन वहा पर आज तक सै ान जज की रिहाइ ा के लिये मकान नही है। भिवानी के अंदर भी अभी तक जजिज के लिये मकान नही है। जो वहां परी स्टाफ लगा हुआ है उसके लिये भी कोइ मकान हनी हैं इसका नतीजा यहा है कि वहां पर कोई भी अफसर जाना नही चाहता है। जब उन्हे धर नही मिलते तो वे अफसर वहां से अपनी

बदली करवाने की कोि ा ा करते है। आज सोनीपत और भिवानी जैसे ऐसे छोटे छोट जिले है, जहां पर अफसरो और मुलाजमों के रहने के लिये सरकारी मकान नही है। प्राईवेट मकानों का यह हाल है कि जिन मकानो का किराया पहले 50 रूपये था अब वे मकान 600, 700 रूपये महीना किराये पर भी नही मिले। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस तरफ खास तवज्जह देनी चाहिए और छोटे छोअ मुलाजमो के लिये व जो जजिज साहेबान है, उनके लिये सरकारी मकानो का प्रबंध करना चाहिए। दूसरे खर्चे तो अवायड किये जा सकते हे लेकिन इस तरह के जो जरूरी खर्च है उनको अवायड न किया जाये और मकान वगैरह बनाने की तरफ खास ध्यान दिया जाये। कई ऐसे डिवीजन है जहां पर अभी तक मकानात वगैरह नही बने है और इस तरफ मेरे विचार मे सरकार का अभी तक ध्यान भी नही गया है। इसलिये इस तरु जितना खर्चा सरकार ने रखा है, उससे ज्यादा खर्चे का प्रावधान किया जाये।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं हेल स्टोर्मज के बारे मे कुछ बतलाना चाहता हूं। अभी रोहतक और भिवानी जिलो मे इस वजह से किसानो की काफी फसले बरबाद हो गई है । मेरे विचार मे सरकार की इस तरफ कुछ तवज्जह होगी और कुछठ रूलज भी बने हुए है जिनके तहत सरकार किसानो को रियायते देती है माफी देती है। सरकार ने ऐसा कर रखा है अगर किसी का 25 फीसदी नुकसान हो गया तो उसको इतना मुआवजा दिया जायेगा,

जिसका 50 परसैंट नुकसान हुआ उसको इतना मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन मेरे विचार से वे रियायते उचित नही है। आप देखिये कि एक किसान के पास एक बीघा जमीन होती है तो वह उस पर पता नही कितने महंगे बीज, कितनी महंगी खाद का इस्तेमाल करता है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः चौधरी साहब, आप वाइंड अप करे।

चौधरी रिजक रामः चेयरमैन साहब, मै बता रहा था कि किसान का एक किले के ऊपर कितना कितना खर्चा आता है और अगर कहीं ई वर का प्रकोप से ओले पड़ जाते है तो उस बेचारे का कितना नुकसान हो जाता है। इस बात का ध्यान खस तौर पर सरकार को रखना चाहिए और पड़ताल करवानी चाहिये कि उसका कितना नुकसान हुआ है और उस किसान को उस के नुकसान के हिसाब से मुआवजा देना चाहिये न कि पिछले कायदे और कानून के हिसाब से उसको मुआवजा देना चाहियें चेयरमैन सहाब, मै आप को बताऊं कि आज हरियाणा के अंदर कोई ऐसाकिसान नही है जिसकी इतनी जयादा पेदावर हो कि वह अपने व अपने बच्चो का अच्छी तरह से गुजारा कर सकता हो। तकरीबन हरेक किसान बेचारा कर्जे के नीचे दबा रहता है और जब ऐसी कोई बात हो जाये तो वह बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और कर्जे वगैरह से डरता हुआ वह छुपता रहता है, कर्जा लेने वाले उसके पीछे पीछे रहते है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह उन पुराने कायदे कानूनो को पीछे हटा कर किसान को उसके नुकसान

का असली मुआवजा दे ताकि किसान को भी एक सुख का सांस मिले और वह दोगुनी मेहनत से अपना काम कर सके और ईमानदारी से अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री मूल चंद मंगला (पलवल): चेयरमैन साहब, आजादी मिलने से पहले हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी यह बात कहा करते थे कि आजारी आ जाये तो आप देंखेगे कि हमारे दे ा के नेता जो है, वे एक साधारण जीवन व्यतीत किया करेंगें एक सस्ते तरीके से रहैंगे ताकि जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है उनके दिलों मे किसी किस्म की भावना न आए कि हमारे नेता इतना ज्यादा खर्चा कर रहे है। अभी श्री मूलचंद जैन जी ने बोलते हुये कहा है कि उनका खर्चा इतना अधिक दिखाया गया है जिसको देखकर मन बहुत दुखी होता है । मैं उनकी बात की ताईद करता हूं । चेयरमैन साहब, इस मे साफ लिखा है कि राज्यपाल के स्टाफ की तनख्वाहों के लिये 102180 रूपये, राज्यपाल महोदय के घरेलू अमल `पर 8400 रूपये और राज्यपाल तथा उसके परिवार को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिये 11900 रूपये की रा ि ा नि ि चत की गयी है। इसी तरह से आगे यह लिखा गया है राज्यपाल महोदय के मनोरंजन के लिये 241200 रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है। राज्यपाल के संविदा भत्ते का खर्चा 241200 रूपये व राज्यपाल के दौरे का खर्चा 900 रूपये बताया गया है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि

यह जो राज्यपार महोदय के लिये इतना भारी खर्चा दिखाया गया है, वह नाजायज खर्चा है। अगर हम इस खर्चे को कम नही करेंगे तो हम अपनी गरीब जनता को यह कैसे कह सकेंगे कि हम आपके लिये यहां पर कुछ कर रहे है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को गरीब आदमियों की कोई फिकर नही है, केवल बड़े आदमियों का ही ध्यान है। मेरा सुझाव है कि इस मसले पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए।

इससे आगे एक और बात बताना चाहता हूं । डबवाली मे तहसील भवन के कार्यालय का सरकार 70 रूपये प्रति माह के हिसाब से किराया देती थी और उस मालिक मकान ने उचि किराया करवाने के लिये उप न्यायाधी ा एंव किराया नियंत्रक डबवाली के न्यायालय मे मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय ने यह किराया बढ़ाकर 521.25 रूपये कर दिया। आप ही देखिये कि अगर दोबारा असैस करवाया जाये तो मु कल से कहीं दोगुना किराया भी नही होगा पर इस केस मे तो कोई राजनीतिक चाल दिखाई देती है कि एक दम किराया 70 रूपये से बढ़कर 521.25 रूपये हो गया। (ाोर व व्यवधान)

चौधरी देस राजः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जो केस कोर्ट से संबंधिंत हो वह यहां पर डिस्कस नही होना चाहिये । यह जो 521.25 रूपये की रा ि ा बढ़ाई गई, यह कोर्ट का फैसला था, हमने कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह पमैंट कर दी।

श्री सभापतिः मंगला जी, आप कन्टीन्यू रखिये।

श्री मूल चंद मंगलाः चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह था कि इसमे कोई राजनीतिक बू आ रही है। यह जो मामला है, इसमे वजोहात नही हैं कोई न कोई चालाकी हुई है। अभी बहन सुशमा जी ने भी कहा कि एक साईकिल सवार को एक गाड़ी मार कर फेंक गई। जो आदमी उस आदमी को हस्पताल मे ले गया उसक खिलाफ कोर्ट ने डिक्री कर दी और उस आदमी के रि तेदारो को सरकार की तरफ से 22000 रूपया देना पड़ा। इस केस के भी ऐसा जाहिर होता है कि इसमे भी कोई न कोई चार सौ बीसी है। ऐसे केसिज मे अगर सरकार को पता हो कि डिक्री होनी है तो कोर्ट मे जाने का कोई मतलब ही नही होना चाहिए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, मैं भी एस्टीमेटस कमेटी का मैंबर हूं। जब यह डिमांड वहां पर पास की गई, उस वक्त सभी बातों को सोच समझ कर इसको किया गया। इसलिये इन्होंने जो बाते यहां पर कही है उसे कार्यवाही मे से निकाल दिया जाये।

श्री मूल चंद मंगलाः चेयरमैन साहब, इसी तरह से एक और केस है। एक अधिकारी की पदोन्नति होनी थी, उसको पदोन्नति नही दी गयी। वह आदमी कोर्ट मे चला गया, कोर्ट ने सरकार के विरूद्ध फैसला दे दिया और उस आदमी को पदान्नति दे दी गयीं जो उसका बकाया पैसा था, वह भी दे दिया गया।

अगर सरकार पहले ही सोच समझ कर सारा काम करे तो क्यो इतना नुक्सान उठाना पड़े। उस आदमी का भी अदालत मे काफी खर्चा हुआ और इधर सरकार को भी उस मुकदमे पर काफी पैसा लगाना पड़ा। इसलिये मेरी सरकार से रिक्वैस्अ है कि इस तरह के केसिज को पहले ही अपने लैवन पर अच्छी तरह से परसू कर लेना चाहिये ताकि उसे इस तरह का नुकसान न उठाना पड़े। इससे सरकार की नीतियों की भी बदनामी होती है और इस तरह से जो फालतु पैसा अदालतों मे चला जाता है, वही पैसा अगर किसी गरीब मजदूर, गरीब किसान और दूसरी गरीब जनता के लिये खर्च किया जाये तो मेरे ख्याल मे यह ज्यादा हितकारी सिद्ध होगा। इससे लोगो को भी फायदा होगा और सरकार भी ऐसे गल्त कामों से बच जायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही नही होनी चाहिए। किसी गरीब आदमी को अपने हक मे लिये बिना वजह हाई कोर्ट मे जाना पड़े, यह बात ठीक नही है। सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह उसकी जायज मांग पर पहले ही ठीक प्रकार से सोच विचार करे।

इसके बाद मैं मांग नं. 6 पर आता हूं। इस मांग मे काफी रूपया एकसैस मांगा गया है। मैं समझता हूं यह भी पहली मांग की तरह ही दिखाई देता है। यह पैसा मांग कर एम.एल.एज. को खु ा करने की कोि ा ा की जा रही है। जैसे मैंने भाुरू मे कहा कि इस दे ा की जनता गरीब है इसलिये हमे वेस्टफुल एक्सपैंडीचर नही करना चाहिए।

सरदार सुखदेव सिंहः चेयरमैंन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर है। चेयरमैन साहब, सामने खम्भे पर जो बात लिखी है कि यहां पर वही बात कही जाये जो सच है। तो क्या मेरे साथी इस बात पर अमल करेंगे कि वे बढ़ा हुआ भत्ता नही लेंगे ? (ाोर)

श्री मूल चंद मंगलाः हां मै वायदा करता हूं और मैं लिख कर भी दे दूंगा। यह काम तो एम.एल.एज. का खुरूा करने के लिये किया जा रहा है। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं मैंबर साहेबाद को आपके द्वारा रिक्वैस्ट करूंगा कि जो पैं ान या और भतों को गलत समझते है। वे लिख कर दे दे कि हम सह सहूलियत नही लेना चाहते। सरकार एक्ट मे तरमीम कर देगी और इससे स्टेट को भी फायदा होगा। (ाोर)

श्री मूल चंद मंगलाः चेयरमैन साहब, मैं तो इस बात की पहले भी मुखलाफित करता था और अब भी करता हूं । इसके बाद मैं मांग नं. 14 पर आता हूं। इसमे 18929000 रूपये गनी बैगज की खरीद के लिये मांगे गये है। इस मामले मे भी बड़ी गड़बड़ होती है। मैं चाहता हूं कि जो बोरियां खरीदी जायें उनकी तसदीक कारवाई जाये कि वह वाकई नई है। मंडियों मे नई बोरियों की बजाये पुरानी बोरियों मे अनाज भर दिया जाता है।

इसलिये इस घोटाले की जरूर छान बीन की जाये। पिछली बार हमे पता चला था कि नई बोरियों की बजाये पुरानी

बोरियां मिली थी। जिस काम के लिये यह रूपया मांगा गया है वह घपले की बजाये और कुद नही है क्योंकि कोटे ान देने वाला असली तो एक ही आदमी होता है दूसरी कोटे ाने वह खूद ही बना कर दे देता है। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले मे खास ध्यान रखे। अभी मंत्री जी कैरोसीन के बारे मे बता रहे थे। मैंने पिछले इतवार को देखा कि एक आदमी रिक ाा पर दो सौ लिटर तेल ले जा रहा था । मैं उसी वक्त डीलर के पास गया और पूछा कि इसको इतना तेल कैसे दे दिया ? तो उसने मुझे 50–50 लिटर के चार परमिट दिखाये। वे परमिट अलग अलग नाम से थे लेकिन आदमी एक ही ले रहा था। चेयरमैन साहब, आज इस प्रकार की धांधलेबाजी हो रही है। गरीब आदमी को तो एक बोतल भी तेल की नही मिलती लेकिन बड़े आदमी दो दो सौ लिटर तेल ले रहे है। मैं इस विशय मे और भी बातें कहना चाहता था लेकिन आप मुझे वाईउअप करने के लिये कह रहे है। इसलिये मैं बाकी बाते बजट पर बहस के वक्त कहूंगा।

चौधरी गंगा राम (गोहाना): चेयरमैन साहब, मैं सब से पहले डिमांड नं. 4 पर बोलना चाहूंगा। आज सरकार ने यह माना है कि ओला वृश्टि से किसानो को 25 करोड़ रूपये की हानि हुई है। मुख्य मंत्री जी पिछली सरकार मे भी मंत्री थे। उस समय किसानो का जो ओलावृश्टि से नुक्सान हुआ था तो चौधरी देवी लाल की सरकार ने तीन सौ रूपये फी एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था। मैं आज की सरकार से भी दर्खास्त करता हूं

कि किसान सूखे से भी मरा, पाले से भी मरा, ओले से भी मरा, उसे डीजन भी नही मिला और पानी भी नही मिला। इसके अलावा जितने किसान के इम्पलीमैंटस है उनकी भी कीमते बहुत बढ़ गई है। जो बीज किसान ने डाला था उसकी कीमत भी पूरी नही मिली। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अच्छाई मे मुकाबिला होना चाहिए। अच्छा यही है कि अगर चौधरी देवी लाल ने तीन सौ रूपये फी एकड़ मुआवजा दिया था तो आपको पांच सौ रूपये फी एकड़ देना चाहिए। मैं सरकार से वही सिफारि ा करूंगा जिससे इस प्रदे ा का भला हो सके। इसके अलावा जो आखिर मे डिमांड नं. 25 है मे उसके बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने खुद माना हे कि आज भी हमारे प्रदे ा के जो भूगर मिल है उनके पास किसानो का तीन करोड़ रूपया बकाया पड़ा है। बड़ी भार्म की बात है कि हर साल हमारे प्रदे ा के किसानो का करोड़ों रूपया बकाया भूगर मिलों के पास पड़ा रहता है और दो दो साल तक नही दिया जाता है। एक तरफ तो हमारी सरकार जो भूगर मिलो को लोन देती है उस पर ब्याज लेती है लेकिन दूसरी तरफ किसानों का चार करोड़ रूपया हर साल बकाया पड़ा रहता है, उस पर कोई ब्याज नही दिया जाता। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि किसान का जो पैसा कई साल तक ब्लाक रहाता है, उस पर ब्याज दिया जायें हमारी सरकार ने सैंटर से दस करोड़ रूपया लिया और इस साल मे उस पर 50 लाख रूपया ब्याज दे रही है। इसी तरह से किसान का

4–5 करोड़ रूपया ब्लाक पड़ा रहता है लेकिन उसको ब्याज नही दिया जातां

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जो फिग्गर्ज मेरे दोस्त गंगा राम जी दे रहे है, ये सारी गल्त है। किसानो का पिछला सारा पैसा क्लियर किया जा चुका है। तीन मिलो मे कुछ बाकी है बाकी सारी पेमैंअ क्लियर करवाई जा चुकी है। इस साल भी केस पेमैंअ करवाई है।

चौधरी गंगा रामः चेयरमैन साहब, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि किसान का जितना पैसा ब्लाक रहता है, उस पर किसान को ब्याज मिलना चाहिए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं मांग नं. 3 पर भी बोलना चाहता हूं। इसके अंदर पुलिस विभाग के लिये 14258875 रूपये मांगे गये है। यह तो हम भी मानते है कि पुलिस विभाग मे कुछ तरक्की होना चाहिए ओर उनका फायदा होना चाहिए । लेकिन बड़ी भार्म की बात है कि आज हरियाणा के अंदर ला एंड आर्डर के नाम की कोई चीज ही नही है। आज हरियाणा के अंदर हर जगह पुलिस इनोसैंट आदमियों को पीट रही हैं आज मै अखबार पढ रहा था। गुड़गांव मे एन.के. सिंह को बुलाया गयां उसकी इंटैरोगे ान डेढ़ घंटे तक चली। वह जब पुलिस थाने से बाहर आया तो वहां पर प्रैस रिपोर्टर खड़े थे। प्रैस रिपोर्टरो ने उनसे कुछ पूछना चाहा तो थाने दार भी बाहर आया। चेयरमैन साहब बड़ी भार्म की बात है कि थानेदार ने अखबार वालो

को, प्रैस रिपोर्टरों को यह का तुम थाने मे कैसे आए, तुम्हारी कैसे हिम्मत पड़ी, तुम बाहर निकल जाओं। यहां तुम एन.के. सिंह से कोई पूछ ताछ नही कर सकते।

*चेयर के आदे ाानुसार कार्य वाही से निकाल दिये गये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): सभापति महोदय माननीय सदस्य जो बात हाउस मे कह रहे हे वह इनको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए। किसी भी प्रैस रिपोर्टर को नही कहा गया है। यह बिल्कुल निराधार और गलत बात है। इसलिये यह हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री सभापतिः चौधरी गंगा राम जी ने जो प्रैस रिपोर्टरों के बारे मे बात कही वह एक्सपंच की जाये। चौधरी गंगा राम जी आप डिमांड पर बोलिये।

चौधरी गंगा रामः सभापति महोदय, यह खबर अखबार मे आई है सभापति महोदय दूसरी बात है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज हरियाणा के अंदर ग्रामों के सुधार की और देहातो के सुधार की बात करती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने, जिसमे चौधरी साहब मंत्री थे, 80 लड़कों को सैंट्रल कोआप्रटिव बैंक सोनीपत मे नौकरी दी थी और इस सरकार ने आते ही उन 80 लड़को को नौकरी से निकाल दिया (ाोर एंव विघ्न) सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता

हूं कि हरियाणा एग्रीकचरल मार्किटिंग बोर्ड मे देहात के 150–200 लड़कों को नौकरी दी गई थी इस सरकार ने आते ही उनको वहां से निकाल दिया।

श्री सभापतिः चौधरी गंगा राम जी आज डिमांड पर बोलिये।

चौधरी गंगा रामः सभापति महोदय, मैं डिमांउ पर ही बोल रहा हूं आज यह सरकार कहती है कि हम खर्चे कम कर रहे है और यह भी कहती है कि बजट मे हम कोई नया टैक्स नही लगाना चाहते है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैम्बरों को खु ा करने के लिये किस तरीके से हरियाणा के गरीब किसानो की कमर तोड़ी जा रही है। सभापति महोदय, इस सरकारने हरियाणा मे नई तहसीले बनाई है, नई सब तहसीले बनाई है और सब डिवीजन भी बनाए गए है जिनमे हजारो आफिसर्ज जा कर काम करेंगे। सभापति महोदय, यह एक छोटा प्रांत है और इसके अंदर 10–11 छोटे छोटे जिले है। इनमे 25–30 नई तहसीले बना दी है और सब तहसीलों की तो कोई गिनती ही नही है। लेकिन किसान बरबाद हो रहा है उसका इस सरकार का कोई ख्याल ही नही है। चेयरमैन साहब, अगर कोई आदमी चौधरी भजन लाल जी को कहता हे कि यह तो आप मेरे गांव को तहसील बना दे नही तो मैं आपकी पार्टी छोड़ कर जाता हूं इस तरह से वे दबाव डाल कर अपनी मांगे पूरी करवा लेते है । सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चहूंगा कि आप

इस दबाव मे डरो मत। हम आपके साथ है, आपकी सरकार टूटती हनी है। मैं मुख्य मंत्री जी को यह बताना चहता हूं कि यदि आपको इस तरह से ब्लैक किया जाता रहा तो आप प्रवे ा का सुधार नही कर सकेंगे।

चौधरी देस राजः चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा चौधरी गंगा राम जी को कहना चाहता हूं कि वे दिन भूल गये जब इनको चेयरमैनि ाप से हटाया गया था तो इन्होने मुख्य मंत्री महोदय के पास जाकर माफी मांगी थी।

चौधरी गंगा रामः सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को चैलेंज करता हूं जो कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। मैंने कभी भी जन्म से लेकर आज तक किसी से माफी नही मांगी है। माननीय सदस्य और मुख्य मंत्री की तो ही क्या है कि वे मेरे से माफी मंगवा ले। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, हजारो सरकारे आई और चली गई मैंने कभी भी किसी से माफी नही मांगीं

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी अब आप खत्म कीजिये।

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा के ऊपर बड़ा भारी खर्चा डाला जा रहा है और इसके साथ ही यह सरकार कहती है कि ि ाक्षा का स्तर और ढांचा सुधर रहा है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बताना

चाहता हूं कि पिछली सरकार के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने गांवो मे लड़कें लड़कियों को ि ाक्षा देने के लिये 14–15 स्कूल खोले थे लेकिन इस सरकार के लिये यह भार्म की बात हे कि पालिटिकल भावना से, बदले की भावना से उन स्कूलो को डाउन ग्रेड कर दिया है।

श्री लहरी सिंह मेहराः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस हाउस मे गलत बात कह रहे है। किसी भी हल्के मे 2 या 4 हल्को को छोड़ कर 15–15 स्कूल अपग्रेड नही किये गयें दो चार हल्को के अलावा कोई भी हल्का ऐसा नही है जिसमे दो से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किये गये हो।

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो स्कूल अपग्रेड किये थे उनको इस सरकार ने आते ही डाउन ग्रेड कर दिया। इस सरकार ने देहाता के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। (ाोर एंव विघ्न) इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस मे काम के बदले अनाज की स्कीम आज हरियाणा के बारे मे जिक्र किया गया है। इसके बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी तहसील गोहाना के अंदर 15 डिपो होल्डर्ज मे 9 हजार बोरियों के डिस्ट्रब्यू ान हुई और अकेले डिपो होल्डर जिसका नाम श्री जोगी राम है, चौधरी भजन लाल जी उसको अच्छी तरह से जानते है, उसने अकेले 8 हजार बोरियों की डिस्ट्रीब्यू ान की है। एक डिपो हाल्डर को बोरियों की डिस्ट्रीब्यू ान मे एक बोरी के पीछे 8 रूपये

बचते है। इस तरह से किसानो को बरबार किया जा रहा और उनके साथ अन्याय किया ता रहा है। जो सरकार के मुहं लगते आदमी है, उनको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी आप ये सारी बातें गवर्नर साहब के ऐड्रस पर कह चुक है। आत आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सरकार ने बजट के अंदर तो कोई नया टैक्स नही लगाया है लेकिन इन्होंने 31 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया है। इसके अलावा 15 करोड़ रूपये सरकार कर्मचारियों पर भी खर्चा आना है और 13 करोड़ रूपया इन्होंने सैंटर को देना है। इस तरह से कुल मिला कर इनका घाटा लगभग 60 करोड़ रूपये हो जायेगा। इसको ये बाद मे आर्डिनैंस के जरिये टैक्स लगा कर पूरा करेंगे। इसलिये यह किसानो के साथ सरासर धोखेबाजी है। इसी तरह से जो सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस रखे जाते है उनमे हर बार गवर्नर साहब और मिनिस्टरो के लिये काफी खर्चा मांगा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी भार्म की बात है कि लाखो रूपया गवर्नर साहब पर खर्च होता है और करोड़ो रूपया मिनिस्टरों की कारो और कोटियों पर खर्च होता है। 90 सदस्यो के हाउस मे 40 मिनिस्टर है और 50 मैंबर है। उन 40 मिनिस्टरों के पास 40 सरकारी कोठियां है इसके अलावा स्वामी आदित्यवे ा जी को विदे ाो के अन्दर भेजा जा रहा है (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी आप बैठिये। मैं आपसे कई बार रिस्वेस्ट कर चुका हूं।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मांग नंबर 9 पर अपने विचार रखूगां। डिप्टी स्पीकर साहब, यह मांग ि ाक्षा के बारे मे हे। हमारे सरकार ने ि ाक्षा के ऊपर बड़ी धन रा ि ा खर्च करने की को ि ा ा की है उसके बावजूद भी महंगाई की वजह से और कर्मचारियो को महंगाई भते देने की वजह से तकरीबन 14 लाख 45 हजार रूपये की जरूरत पड़ी । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कल हमारा बजट पेश हुआ है उससे यह पता लगता है कि हमारी सरकार यह चाहती है कि ि ाक्षा के क्षेत्र मे हर आदमी को ज्यादा से ज्यादा सहूलियते दी जायें ताकि भिाक्षा को बढ़ावा मिले।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ सरकार ने यह रिकार्ड कायम किया है कि किसी प्रकार का टैक्स नही लगाया । इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को और वित मंत्री महोदय को बधाई देता हूं लेकिन इसमे एक बात विचारणीय हैै कि अगर हमारे खर्चे इसी प्रकार बढ़ते रहे और फिजुल खर्चो मे कमी नही करेंगे तो हम टैक्स लगाने के लिये मजबूर हो जायेगे। खर्चे मे कमी करने के लिये मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि सरकार को आने वाले समय मे टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े और न ही बजट पर नाजायज बोझ बढ़े। डिप्टी स्पीकर साहब, ि ाक्षा की उन्नति के लिये सरकार ग्रांट देती है। फाईनै ि ायल

ईयर के आखिरी महीने मे दो करोड़ रूपये की ग्रांट पैंडिंग है जिसको अभी तक डिस्ट्रिब्यूट नही किया गया। डिपार्टमैंट ने अब और ग्रांट मांगी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो महीने फाइनैि ायल ईयर के बाकी रहा गये है इसके लिये और ग्रांट लेने की ज्यरत नही है। जब पहल ग्रांट बांटी ही नही गई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जरूरत ही नही थी, अगर जरूरत होती तो इस ग्रांट का डिस्ट्रीब्यू ान हो जाता । अगले बजट के लिये इस ग्रांट को रोक रखे और अगले साल इसी की डिस्ट्रीब्यू ान करें, यही पैसा काम आ सकता है और डिपार्टमैंट को दो करोड़ रूपये की बचत हो सकती है। मैं समझता हूं कि ि ाक्षा विभाग मे ही नही, दूसरे विभाग मे ही नही, दूसरे विभागों से भी, कम से कम दस करोड़ रूपये की ग्रांटस की रा ि ा मिल सकती है, सिजको आप अगले साल मे इस्तेमाल कर सकते है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्म की ग्रांटस जो मिसयूज होती है, उनको चैक करे ओर फाइनैि ायल ईयर के लास्ट मे आकर ये डिस्ट्रीब्यूट नही होनी चाहिए, बल्कि अगले साल होनी चाहिए। इससे सरकार को काफी फायदा होगा और सप्लीमैंटरी एस्टीमैटस लोने की जरूरत भी नही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान स्कूल कम्पलैक्स स्कीम की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस स्कीम पर सरकार की तरफ से तकरीबन 3 लाख रूपया सालाना खर्च होता है। स्कीम यह है कि हाई स्कूल के हैडमास्टर के पास, पांच साल प्राईमरी या मिडल स्कूल के मास्टरों को सिर्फ हाजिरी देनी पड़ती है, कोई काम नही करना

पड़ता और प्रत्येक मास्टर को 75 पैसे पर डे रिफ्रै ामैंट तथा आने जाने का टी.ए. देना पड़ता है। मास्टर अक्सयर हाजिरी लगाकर चले जाते है और रिफ्रै ामैंट के पैसे हैडमास्टर की जेब मे चले जाते है। असल मे यह स्कीम बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसका कोई फायदा नही है सिवाये इसके कि हैड मास्टर को पैसे निकाल कर खाने का मौका मिल जाता है और मास्टरों को हाजिरी लगाने का मौका मिल जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्कीम को खत्म किया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बात आपके ध्यान मे लाना चाहता हं। सरकार होम साईंस टीचर्ज की ट्रेनिंग के लिये ग्रांट देती है लेकिन आप हैरान होंगे कि भाायद ही हमारी स्टेट का कोई लड़का होम साईंस की ट्रेनिंग ले रहा होगां सरकारने ऐसे ही होम साईंस के नाम पर कई प्राईवेट स्कूलों को ग्रांट दे रखी है। इन स्कूलों मे पंजाब और हिमाचल प्रदे ा के लड़के ट्रेनिंग लेते है, हरियाणा का कोई लड़का ट्रेनिंग नही लेता और ऐसा लगता है। कि ये स्कूल हरियाणा के लिये बने ही नही। हरियाणा सरकार अपना पैसा खर्च करके इन प्राईवेट स्कूलों को चला रही है जिससे कोई फायदा नही है।

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम हो गया है, आप एक मिनट मे खत्म करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब हमे इन स्कूलों से कोई फायदा ही नही है, हमारे लड़के इनमे ट्रेनिंग ही नही लेते तो इन प्राईवेट स्कूलो को

ग्रांट को बंद करना चाहिए ताकि इनका बजट पर कोई असर न पड़े। लोगो ने ग्रांअ स्कूल चलाने का जो प्रोफै ान बना रखा है सरकार इसको चैक अप करे और ग्रांट बंद करे।

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल): डिप्टी स्पीकर साहब, सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के जरिये मैंने 39 करोड़ 33 लाख रूपये की डिमांडज हाउस के सामने पे ा की है। मेरे साथी बाबू मूलचंद जैन अपोजी ान पार्टी के लीडर है। वे मेरे साथी है क्योंकि हम दोनो इकट्ठे ही राजनैतिक जीवन मे आये थे ओर अमरजैंसी मे इकट्ठे ही जेल मे रहे थे, इसलिये वे मेरे दु मन तो नही है, मित्र है। बाबू जी को 12–13– साल के बाद समझ आती है, (हंसी) मैंने जो कदम उठाये है, भाायद वे उनको माल जाये। इन्होंने अपनी तकरीर मे काफी बातो का जिक्र किया है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब वे यहां से एज फिनांस मिनिस्टर गये तो हमारे लिये 37 करोड़ रूपये का घाटा देकर गये थे। जब नई सरकार आई तो इस घाटे को देखते हुए सरकार ने खर्चे पर कट लगा दी और इस घाटे को परा करने की कोि ा ा की। जैन साहब ने हाउस मे कई बाते की, यह भी कहा कि गवर्नर के खर्चे पर और दूसरे खर्चो पर आम तौर पर डिस्क ान नही होती लेकिन चूंकि जैन साहब ने जिक्र किया है। इसलिये मेरे लिये जवाब देना जरूरी है। मै उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नर के खर्चे के लिये जो रूपया बढ़ाया गया है, वह जरूरी था। अगर यह रा ि ा न बढ़ाते तो वह इंस्टीच्यू ान जो सरकार का प्रतीक

है, ठीक तरह से न चल पाता और उसके साथ हम इंसाफ न करते। डिप्टी स्पीकर साहब, जैन साहब ने यह भी कहा कि मंत्रिमण्डल बहुत बढ़ाया गया है। अगर वे अपने समय के खर्चे को देखे तो मालूम होगा कि जितना रूपया उन्होंने एडवाइजरो पर खर्च किया था, वह इन मंत्रियों के खर्चे से कहीं बहुत ज्यादा था। यह रूपया उन लोगो पर खर्च किया गया था जिनका कोई पालिटिकल स्टेटस नही था। केवल एक आदमी को कुछ बाते याद दिलाने के लिये एडवाइजर लगाए गए थे। अगर उन एडवाइजरो के खर्चे का हिसाब लगाएं तो भाायद हमारे मंत्रिमण्डल के खेर्ं से कहीं ज्यादा बैठता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा ख्याल था कि अनुपूरक अनुमानो को पढ़ कर और यह देख कर कि किस तरह से इकोनोमी को कंट्रोल किया है, भाायद लीडर आफ दि अपोजी ान एप्रिसिए ान करते लेकिन इन्होंने एप्रिसिए ान करने की बजाये क्रिटिसीजम करना भाुरू कर दिया। ठीक है, अपोजी ान के लीडर का चर्चा करना फर्ज होता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसीजन होना चाहिए। इसके बीच मे कुछ ऐसे आदमी बैठे है। जो कंस्ट्रक्टिव बात इसके दिमाग मे बैठने ही नही देते। ऐसी बात नही है कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात इनके दिमाग मे आ ही नही सकती, आती है लेकिन जो लोग बीच मे बैठे है वे कंस्ट्रक्टिव बात आने नही देते।

श्री मूल चंद जैन: जो बाते मैंने कही है उनका जवाब दों पोलिटिकल मामलो मे क्यों उलझ रहे है ? (व्यवधान)

लाला बलवंत राय तायलः जैन साहब का ब्रेन तो कंस्ट्रक्टिव है लेकिन वे ऐसी सोबत मे आ गये है जिसके कारण अन हैल्दी क्रिटिसीजन करने के लिये मजबूर है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा की इकौनोमी इनसे छपी हुई नही है। जिस तरह के टैक्स इन्होंने हरियाणा की जनता पर लगाए थे, नई सरकार आने के बाद हम ने उन टैक्सों को वापिस ले लिया है। हमने लोगों के अंदर वि वास पैदा किया है कि हरियाणा मे आलरेडी जो टैक्स लगे हुए है, इन्ही को ठीक तरीके से इक्ट्ठा किया जाये तो हरियाणा मे तरक्की के काम हो सकते है। बिन टैक्स लगाये, लोगो को तकलीफ दिये बगैर हम अपना काम नही चला सकते है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे दोस्तों को इलैक ान के बारे मे कुछ वहम हो गया है । इन्होंने सोचा कि विदाउट टैक्स बजट पे ा हुआ है, भाायद हरियाणा मे इलैक ान न हो जाये। (व्यवधान) तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इनका यह ख्याल बिल्कुल गलत साबित हो गा और हरियाणा की असैम्बली पूरे समय तक चलेगी। (विघ्न) अैक्स न लगाने का ये मतलब न लगाए कि इलैक ान जल्दी होगा। लोगो का वोट देने का पैट्रन तो अलग ही है। वे काम को नही देखते। वे अपने तरीके से वोट देते है। इन्होंने यह पिछले इलैक ान मे देखा भी होगा। कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिये गये थे कि लोग आजादी से अपना वोट भी नही दे सके लेकिन आप मेरे साथी चौधरी गंगा राम जी ला एंड आर्डर की बात करते है, और जिक्र करते है किसी अखबार कां अगर कहीं किसी आधिकारी को बुलाकर कोई बात पूछी जाये तो इसमे ला एंड

आर्डर की खराबी कहां से आ गई ? सप्लीमैंटरी बजट पर बात करते हुए इन्हे काई कंस्ट्रक्टिव बाते करनी चाहिए थी ताकि स्टेट की इकौनोमी पर उसका कुछ असर पड़ता और हमारी स्टेट के जो लोग यहां हमारे पास पास बैठे है वे इस बात को सोचते है कि वधान सभा के सदस्य अपने काम काज को बड़ी अकलमंदी और सूझबूझ से करते है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, बहन सुशमा जी जो हमारे हाउस की आनरेबल मैंबर है और जो पहली मिनिस्ट्री के अंदर कुछ अर्से तक मिनिस्टर भी हरी है, ने भी कुछ बातों का जिक्र किया। हरिजन कल्याण निगम का उन्होंने बहुत जिक्र किया। एक व्यक्ति वि ाैश के बारे मे उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव सुजै ान देने की वजाय एक भावुकता भरी तकरीर उन्होंने यहां कर दी। उन्होंने यहां कर दी। उन्होंने स्टे ानरी और प्रिंटिंग डिपार्टमैंट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 17 पैसे का लिफाफा मिलता है जबकि मेरे पास अढ़ाई पैसे की रिपोर्ट है मुझे पता नही कि ये 17 पैसे का लिफाफा कहां से ले आई ? इनसे मैं कहूंगा कि जो भी बात ये यहां कहे, कंफर्म करके और अथौरिटी के साथ कहे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज।

लाला बलवंत राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो 39 करोड़ 33 लाख रूपये के अनुपूरक अनुमान पे ा किये है,

इनमे से आपने देखा होगा कि 21.36 करोड़ रूपया तो वह है जो हमने काम के बदले अनाज प्रोग्राम पर खर्च किया है। इसी तरह से 1 करोड़ 36 लाख रूपये हमने पुलिस डिपार्टमैंट को सुचारू रूप से चलाने के लिये पुलिस कर्मचारियों को महंगाई भता और एक महीने की ऐक्स्ट्रा सैलरी आदि देने के लिये खर्च किया है। यह खर्च बहुत जरूरी था। जो लोग स्टेट मे ला एंड आर्डर कायम कायम रखते है, जो अच्छा काम करने का, एक आद र्ा पे ा करते है, अगर हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल नही करेंगे तो अच्छी बात नही होगी और यह सरकार अपना फर्ज पूरा नही करेगी।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहब, 16289405 रूपया हमने पैं ान और दूसरे रिटायरमैंट बैनिफिटस देने के लिये मांगा है। इसमे परिवहन विभाग के कर्मचारियों के प्रोविडैंट फण्ड मे दिया जाने वाला पैसा और भूतपूर्व विधायको को दी जाने वाली पै ांन आदि का खर्च भी भाामिल है। यह खर्च भी बहुत जरूरी था। यहां कहा गया कि इसकी पहले अनुमान क्यों नही लगया गया ? डिप्टी स्पीकर साहब, 227 करोड़ रूपये के बजट मे अगर पांच परसैंट हिसाब से थोड़े से रूपये का सप्लीमैंटरी बजट बाद मे आ भी गया तो कोई खराबी नही। (विघ्न) बहिन सुशमा जी ने बनाया नही, सारी सरकार के बजट के ऊपर वे अगर इस तरह की बात कहे ओर बजट को क्रिटीसाइज करे तो बात कुछ जंचती नही । (विघ्न)

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 94 लाख रूपये हमने ब्याज की अदायगी पर खर्च किये है। 71 लाख 27 हजार रूपये भाहरो की तरक्की के लिये खर्च किये है। सरकारने भाहरो मे कुछ जायदाद खरीदी थी। किसको मालूम था कि सै ान कोर्ट ओर हाई कोर्ट मे जाकर के उसकी ज्यादा कीमत पड़ जायेगी। जब कोर्ट ने पैसा बढ़ा दिया तो वह देना जरूरी था। इसमे तीन चार मंडियां भी भाामिल है। इन बातो को देखते हुए कोई अगर यह कहे कि अनुपूरक अनुमान ठीक नही है और सोच विचार के बाद मे बनाए गए है तो ठीक बात नही है। (विघ्न) एक करोड़ सत्तर लाख रूपये हमने गन्नी बैंगज बगैरह के दिये । हमने कुरूक्षेत्र मे, जो हमारे प्रांत का एक तीर्थ स्थान है और सारे हिन्दुस्तान मे हरियाणा का नाम रो ान करता है, भी 48 लाख रूपया खर्च किया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, श्री संत कंवर जी मेरे दोस्त है, साभ है, अजीज है और बड़े जोि ाले भी है। ये बात करते है कि पहले यह सरकार जनता पार्टी की थी लेकिन अब कांग्रेस (आई) की बन गई लेकिन मुझे एक बात याद आती है। अगर संत कंवर जी यह बात कहें तो सोचना पड़ता है कि जो आदमी कुछ रोज पहले अपने आप दल बदल गया हो वह हमे क्या कहता है ? फिर इन्होंने हमारे एक साथी एम.एल.ए. के बारे मे यह आलोचना की कि इनके मां बाप कहां है, कहां से वे आए है, कहां से इनका पता

मिलेगा, कुछ पता नही। ऐसी बातें किसी दूसरे साथी एम.एल.ए. के बारे मे इन्हे नही कहनी चाहिए थी। (विघ्न)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आपने जो एम.एल.एज. के बारे मे किताब छापी है उसमे यह सब कुछ लिखा हुआ है। (विघ्न) उसमे इन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे मां बाप कौन है, मैं कहां पैदा हुआ, मुझे कुछ पता नही। (ाोर)

लाला बलवंत राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, जो लोग सन्यास ले लेते है वे अपने पिछले परिवार को छोड़ देते है। हिन्दुस्तानी समाज मे यह एक रीजि है कि ऐसे लोग पिछले परिवार को छोड़ कर जिसको गुरू धारण करते है उसका ही नाम देते है ताकि वहां से उसका पता चल सके। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी गंगा राम ने भी जब संन्यास लिया था तो यह भी अपने मां बाप को भूल गया था। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही।

लाला बलवंत राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि श्री संत कंवर जी का नाम तो पुलिस रजिस्टर मे मिल जायेगा और स्वामी जी का नाम अपने गुरू के आश्रम मे मिल जायेगा। (ाोर)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः अभी नही। इनके बोलने के बाद दे लेना।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बात के खिलाफ प्रिवलेज मो ान दूंगा या तो ये अनी बात को वापिस ले या साबित करे। अगर साबित न हो तो ये इस्तीफा दे वरना मैं इस्तीफा दूंगा। (विघ्न) तायल साहब के रि तेदार जो लगत ढंग से कारें चलाते है उसका तो ये जिक्र नही करते लेकिन मेरे बारे मे इस तरह की गलत बात करते है। (ाोर) कल भी अखबार मे एक खबर थी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः संत कंवर जी आप बैठ जाइये।

लाला बलवंत राय तायलः संत कंवर जी पुलिस मे नाम मेरा भी है। मैं भी पोलिटिकल आदमी रहा हूं। मेरी हर चीज का उन्हे पता है। इसलिये आप नाराज क्यों होते हो ? हर पालिटिकल आदमी का नाम वहां दर्ज होता है। डिप्टी स्पीकर साहब श्री मूल चंद मंगला हमारे बुजुर्ग मैंबर है। वे पलवल के रहने वाले है। उन्होंने कुछ बातें कही है लेकिन उन्होंने गांधी जी का नाम भी लिया। तो उनके बारे मे मुझे एक बात याद आ गयी। हमारे यहां अकबर अलाहाबादी भाायद हुए है वे ने ानल भाायर थे। उनका एक भोर है–

रपट लिखवाई है हरीफो ने जा के थाने मे

कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने मे।

इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मंगला साहब जब गांधी जी का नामे लेते है तो मुझे यह बात याद आ जाती है। इसी प्रकार से जब हमारे साथी चौधरी गंगा राम जी बोल रहे थे तो उन्होंने यहां जिक्र किया कि सोनीपत बैंक मे एम्पलाइज जो उन्होंने रखे थे वे निकाल दिये। मैं यह तो नही कहता कि उन्होंने कैसे रखे थे और क्यो उनको हटा दिया गया। मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर सर्विस मे इस तरह से आदमी रखे जाये जिस तरह से इन्होंने रखे थे, तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जायें जो भी काबिल आदमी हो उनको रखा जाना चाहिए न कि ऐसे ही रख लिये जाये। इसलिये उनको हटाना जरूरी था ताकि लोगो मे वि वास हो कि यह सरकार गलत काम को बरदा त नही कर सकती। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्षः आप बाद मे प्वायंट आफ आर्डर उठा लेना।

लाला बलवंत राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि यह जो अनूपूरक मांगे 39.33 करोड़ की हाउस के सामने रखी है, इनको पास करे क्योंकि इन अनुपूरक मांगों को लाये बगैर सरकार अपना

काम नही चला सकती थी। इसलिये इन मांगों को पास किया जाये।

Mr. Deputy Speaker: I will now apply guillotine and put the various demands to the vote of the House.

Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.263000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs.802770 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.2-Genral Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs.14258875 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.3-Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs.54630680 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.4-Revenue.

The motion was carred

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.16289405 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.6-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs.4518060 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.7-Other Administrative Service.

That a supplementary sum not exceeding Rs.893790 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs.1444390 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.9-Education.

The motion was carred

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.7127220 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.110972835 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs.20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs.18929000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.14-Food and Supplies.

The motion was carred

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.7255360 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.17-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs.365700 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs.125658545 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs.10003000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.22-Cooperation.

The motion was carred

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.445440 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs.20 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1980 in respect of Demand No.25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carred

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

चौधरी गंगा राम द्वारा

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लने ान सर। सभापति जी, अगर इस सरकार को अपने मुलाजमो पर वि वास न हो तो इसको रहने का कोई हक नही है। अभी तायल साहब ने कहा कि जिस ढंग से मैंने लड़को को नौकरी दी थी उस ढंग से डेमोक्रेसी का खात्मा हो जायेगा तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि उस सिलैक ान कमेटी मे रजिस्ट्रार एम.डी. तथा मैनेजर थे। सिलैक ान कमेटी मे छः गजटिड आफिसर हरियाणा के थे। अगर मिनिस्टर साहब गजटिड आफिसर पर इल्जाम लगाये तो बड़ी गलत बात है। यह बड़ा न्यायपूर्ण ढंग से सिलैक ान हुआ था। मैं आपके जरिये निवेदन कंरूगा कि मिनिस्टर साहब अपने भाब्द वापिस ले ओर उनको गजटिड आफिसर्ज के बारे मे ऐसे भाब्द नही कहने चाहिए। मेरे बारे मे कहना चाहते है तो कहे। (ाोर)

वर्श 1974–75 के एक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोपिए ांज पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker: The following Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1974-75 willbe deemed to have been read and moved:-

That a grant of a sum not exceeding Rs.365401 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 2-General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs.223770 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 5-Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 579274 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 6-Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 232861985 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 8 Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3716710 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 9 Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 54 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 13 Social Welfare and Rehabilitation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 137043134 be made to regularise the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 15-Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10445 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 18-Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 228997 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 20-Forest.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 998753 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 21-Community Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 68035 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 23-Civel Aviation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 31528790 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 25- Loans and Advances by the State Government.

(No mrmbrt rose to speak)

Mr. Deputy Speaker: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.365401 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 2-General Administration.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs.223770 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 5-Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 579274 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 6-Finance.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 232861985 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 8 Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3716710 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 9 Education.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 54 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 13 Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 137043134 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10445 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 228997 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 20-Forest.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 998753 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 21-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 68035 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 23-Civel Aviation.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 31528790 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1974-75 in respect of 25- Loans and Advances by the State Government.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Tht House stands adjourned till 9.00 a.m. on Wedensday, the 12th March, 1980.

(The Sabha then *adjourned till 9.00 hours on Wedensday, the 12th March, 1980)

Annexure

[See foot not at page (7) 30]

***1577 Sh. Gullzar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district wise number of villages there Rabi crops of 1979 were damaged due to hailstorms in the State;

(b) whether compensation to all the hailstorm affected farmers in all the villages referred to in part (a) above has been paid; if so, the amount of compensation so paid in each such village; and

(c) if reply to part (b) be in the negative the district wise names of villages where compensation to the hailstorm affected farmers has not so far been paid together with the reasons therefor?

Revenue Minister (Ch. Sher Singh):

(a) A statement showing the district wise number of villages is annexed at statement 'A'.

(b) The compensation has been paid to all the eligible farmers in the hailstorm affected areas except in a few case where the claimants as per Revenue record were either not available or there the claims are yet to the decided having dispute of ownership/cultivation or there the damage to the standing crops was less then 25 %. A

list showing the compensation paid in the villages of all the districts is at statement 'B'.

(c) Question does not arise.

STATEMENT 'A'

Statement showing the No. of Villages where Rabi Crops of 1979 were damaged

Sr. No.	Name of District	No. of Villages
1	Kurukshetra	72
2	Sonepat	44
3	Rohtak	87
4	Jind	41
5	Karnal	145
6	Faridabad/Gurgaon	11
7	Hisar	18
8	Mahendergarh	102
9	Sirsa	40
10	Bhiwani	57
11	Ambala	28
		645

STATEMENT 'B'

List showing the distribution of Gratious relief in the Hailstorm affected areas

DISTRICT KURUKSHETRA

Sr. No.	Name of Villages	Amount given
1	Amargah Majahra	11405
2	Salaarpur	2550
3	Khari Markanda	5145
4	Alaampur	5825
5	Kheri Brrahmanan	7025
6	Sanwala	15400
7	Ramgarah	3625
8	Bajidpur	96025
9	Bohil	194450
10	Partangah	6875
11	Murthla	69715
12	Dudla	10840
13	Khrindwa	22360
14	Naraingah	13950

15	Kahangarh	10649
16	Haldaheri	12384
17	Samalkhi	1965
18	Sayadpur Barwalian	561
19	Yara	55921
20	Birthala	191546
21	Birthali	76880
22	Bohavi	153953
23	Bohavi	89585
24	Lakhmari	122665
25	Mangoli Rangam	1215
26	Dhanani	2000
27	Sunarian	350
28	Kalwa	93526
29	Bir Kalw	80120
30	Suraja	52715
31	Bir Sujra	71815
32	Kanoni	8929
33	Ishar hari	196530

34	Bir Sonti	1739
35	Baraich Pur	25065
36	Halalpur	2028/55
37	Ducha	36130/90
38	Gobindgarh	5806/75
39	Gharaula	8843/10
40	Zainpur	34831/50
41	Harhaan	121644/95
42	Salimpur	27667/50
43	Baraut	66423/65
44	Newarai	135570/90
45	Darra Kalan	22667/90
46	Ishargarh	105629
47	Mukkarpur	53160
48	Moosapur	30795
49	Kaula Pur	32214
50	Untssj	52895
51	Sujri	40105
52	Mundhkhera	23665

53	Ram Nagar	15626
54	Kashithal	9325
55	Bhagwanpur	15625
56	Rampura	9325
57	Kalal Majra	15625
58	Kal Kheri	23665
59	Umri	4900
60	Pupli	43141
61	Devidaspura	69645
62	Bir Pipli	49902
63	Ratgal	29965
64	Palwal	19490
65	Kheri Ram Nagar	1925
66	Sangal	66610
67	Pai	24875
68	Saaran	117200
69	Siala Sismer	150970
70	Harsaula	6550
71	Kheri Sheru	3134525

72	Degan	311520
	Grand Total	283815/25
DISTRICT SONEPAT		
1	Poghala	358389.00
2	Sardhana	157665.00
3	Bali Quatabpur	349149.00
4	Bajana Khurd	258400.00
5	Bohaja	135964.75
6	Salarpur Majra	60062.30
7	Pinana	475663.00
8	Bajana Kalan	349018.00
9	Gorar	610744.00
10	Maujam Nagar	269611.00
11	Farmana	240594.00
12	Nizampur Majra	245033.42
13	Majri	17066.26
14	Moi	84004.22
15	Mohamadpur Majra	51074.12
16	Doeta	197002.80

17	Khubru	4303.83
18	Ahulana	35005.36
19	Tewari	189186.41
20	Ridau	-
21	Mohana	-
22	Bibilan	155945
23	Anwali	132395
24	Jasrana	371460
25	Giwana	132280
26	Sargthal	358855
27	Sakana Bahdari	19990
28	Kasaudi	342990
29	Kasauda	234780
30	Samdi Sisan	171810
31	Samadi Lochab Baran	173740
32	Guhna	566785
33	Tihad	217530
34	Khanpur Kalan	60186
35	Bhawad	5395

36	Nizampur	235103
37	Rolad Latiphur	59115
38	Bhadi	12560
39	Dodwa	161518
40	Jolli	164293
41	Bighal	250320
42	Bhanswal Kalan Mithan	293015
43	Bhanswal Kalan Bawla	349305
44	Smadi Buran	67780
	Total	8755088.92
DISTRICT AMBALA		
1	Barara	1477.74
2	Chahal Majra	53039.08
3	Datupur	40743.39
4	Hema Majra	88198.39
5	Tolanwali	64491.72
6	Adhoi	83384.09
7	Adhya Hinduwan	52328.97
8	Papotha	21653.76

9	Mullana	606.19
10	Tandwali	2832.49
11	Shahpur	99371.34
12	Patti Bhagaru	35227.34
13	Bhudian	12107.36
14	Hamidpur	16008.35
15	Mojgarh	75724.71
16	Kambas	84557.53
17	Talheri Ranghran	32007.90
18	Tandwal	39293.23
19	Sajjan Majri	103469.19
20	Soobhri	150523.93
21	Ghailri	17744.61
22	Uggala	123839.93
23	Sohana	324859.53
24	Rajoli	208266.77
25	Raju Kheri	175747.45
26	Kambasi	25170.45
27	Adoya Musalmanan	4433.86

28	Daya Majri	1497.67
	Total	2181141.17
DISTRICT ROHTAK		
1	Gandhra	310496.96
2	Kohrawar	115466.12
3	Asan	350640.73
4	Pakasma	607861.92
5	Kasranthi	33852.59
6	Chulina	204776.29
7	Rurki	452640.44
8	Bhalaut	317991.65
9	Mungan	205560.69
10	Polangi	82942.83
11	Hassangarh	15287.47
12	Kilai Dopana	4198.47
13	Ritauli	41157.92
14	Kabur Pur	237820.63
15	Atali	110186.43
16	Nonand	198680.90

17	Samchana	106391.26
18	Ismaila 9 Biswa	168866.37
19	Ismalia 11 Biswa	56518.85
20	Gijji	4850.35
21	Kansala	10503.25
22	Bakhata	30057.46
23	Majra	132203.3
24	Bagpur	15275.40
25	Milkpur	10346.53
26	Safipur	75.3.48
27	Dubaldhan Ghikian	11693.49
28	Dubaldhan Kirman	209989.76
29	Dubaldhan Bidhan	354576.93
30	Raipur	58677.01
31	Dhandlan	248846.05
32	Diwana	159470.12
33	Mamyan	226005.95
34	Ganotan	182.492.60
35	Barhana	434243.01

36	Dighal	520640.07
37	Bishan	279833.65
38	Kakria	220629.91
39	Gochhi	169452.68
40	Bhtian	37620.31
41	Beri khas	420479.68
42	Dujana	208028.68
43	Madana Kalan	317831.39
44	Madana Khurd	71470.13
45	Chaiman Pura	8240.65
46	Chhochhi	37349.24
47	Bakra	109795.46
48	Soria	350991.94
49	Beri Dopana	206791.84
50	Kasar	265100.00
51	Dohoda Kalan	60000.00
52	Mehandi Pur	63350.00
53	Tanda heri	4950.00
54	Kherka Musalmanan	73100.00

55	Sarai Aurangabad	141350.00
56	Barahi	145500.00
57	Khair Pur	36000.00
58	Mukand Pur	2950.00
59	Kanoda	167450.00
60	Ladrawan	223950.00
61	Jasaur Kheri	181050.00
62	Kheri Jasaur	124200.00
63	Kalasi	164100.00
64	Bahmanauli	233250.00
65	BhaisruKhurd	10200.00
66	Sankhol	36850.00
67	Luksar	164550.00
68	Said pur	109350.00
69	Bhadurgarh	231950.00
70	Gubhana	135700.00
71	Badli	14250.00
72	Majri	59650.00
73	Sulda	74000.00

74	Daboda Khurd	98250.00
75	Zardak pur	5700.00
76	Ganarwa	5000.00
77	Silothi	12200.00
78	Muna Majra	119866.00
79	Shiddi pur	104075.00
80	Kharman	54251.00
81	Kultana	7000.00
82	Kharhar	327800.00
83	Dulehra	227000.00
84	Barkatabad	8310.00
85	Rohad	153700.00
86	Darya Pur	79360.00
87	Lagar Pur	19575.00
	Total	12969253.29
District Jind		
1	Sarsa Kheri	32277.00
2	Bharon Khera	4226.00
3	Nand Garh	32.997.00

4	Samdo	38526.00
5	Badhana	271025.00
6	Deola	12571.00
7	Hasanpur	911.00
8	Ardana	15862.00
9	Kaul	281.00
10	Gangatheri	9301.00
11	Chuharpur	129751.00
12	Kheri Naguran	160815.00
13	Alewa	254222.00
14	Naguran	609768.00
15	Wagir Nagar	56949.00
16	Chausala	10042.00
17	Kelram	218257.00
18	Kalta	159100.00
19	Bhanala	90768.00
20	Mohangarh	7200.00
21	Dhan Kheri	91850.00
22	Kasun	53000.00

23	Ujhana	32100.00
24	Koil	51590.00
25	Gograin	19850.00
26	Ludhana	39452.00
27	Bhag Khera	56300.00
28	Aftaligarh	49381.00
29	Danoli	129662.00
30	Singhana	75253.00
31	Ram Nagar	46800.00
32	Hadwa	36446.00
33	Ram Pura	55006.00
34	Dharam Garh	81533.00
35	Shanpur	46678.00
36	Rodh	51350.00
37	Khera Khemavati	80822.00
38	Malakpur	87558.00
39	Paju Kalan	58559.00
40	Tha Malakpur	46298.00
41	Paju Khurd	486.0

	Total	3740230.00
DISTRICT KARNAL		
1	Dha	81588.50
2	Gumton	77295.55
3	Ram Garh	53752.50
4	Kamal Pur Gadian	76468.24
5	Panjokhra	172987.47
6	Manak Manjra	80735.60
7	Bijna	201931.42
8	Samalkha	106971.74
9	Bhunsli	138217.07
10	Bazide Jattan	162437.00
11	Gudha	336114.00
12	Bibipur Jattan	164840.66
13	Malik Pur	255281.86
14	Jhanjhari	41962.00
15	Dhamanaheri	31662.50
16	Barota	95325.00
17	Gorgah	107901.89

18	Begampur	176842.09
19	Gogripur	249162.50
20	Sandhir	117568.75
21	Dhumra	53312.50
22	Kurali	188187.00
23	Zarifa Viran	18800.00
24	Said Pura	12462.50
25	Karnal	60971.00
26	Karnal Depot	5437.50
27	Panudi	45187.00
28	Pingli	46187.50
29	Qadrabad	82989.50
30	Ram Pura	68387.50
31	Kharkali	42637.97
32	Kheri Man Singh	208831.25
33	Kheri Naru	3562.50
34	Janesron	145087.45
35	Jhinwarheri	50800.00
36	Butan Kheri	93800.00

37	Baldhi	17762.50
38	Khora Khera	56625.00
39	Hassan Pur	60337.50
40	Habat Pur	86450.00
41	Tikri	123087.50
42	Sheikhpura (Gharanuda)	205850.00
43	Ramba	544512.00
44	Kailash	86525.00
45	Upli	74337.50
46	Ghurni	234862.00
47	Darar	481186.50
48	Sanghoha	251662.50
49	Garhi Khazur	19612.50
50	Salaru	159687.24
51	Sheikhpura (Indri)	65393.70
52	Budhan Pur	60977.81
53	Dchana	387097.99
54	Sikri	308737.08
55	Garhi Multan	23387.50

56	Behol Pur	67372.48
57	Phurlak	298813.16
58	Barsalu	62977.44
59	Barsat	324037.15
60	Dadupur Roran	80300.00
61	Kamalpur Roran	16562.50
62	Mundrigarhi	38625.00
63	Bhadson	35924.50
64	Badsahpur	36764.97
65	Taphrana	59124.00
66	Raithakana	52974.50
67	Sarvan Majra	40200.00
68	Amargarh	93137.50
69	Amin	3262.50
70	Belehra	14062.50
71	Bir Rai Thakana	43037.50
72	Padhana	31962.50
73	Samora	79387.50
74	Sahmgarh	1950.00

75	Garhi Jattan	48687.50
76	Gangar	3462.50
77	Dadlana	30150.00
78	Kutail	3062.60
79	Kohand	63287.50
80	Srai Kohand	350.00
81	Babarpur	38562.50
82	Ganjbarh	437.50
83	Charaudi	9425.00
84	Rasin	83262.50
85	Baroli	9412.50
86	Rai Pur Jattan	38375.00
87	Kaimla	4600.00
88	Norta	45712.50
89	Dingar Majra	10175.00
90	Jamal Pur	51362.50
91	Gudha (Indri)	11900.00
92	Indri	50700.00
93	Sher Pur Viran	19812.50

94	Garhi Sadhan	92448.44
95	Phusgarh	6737.50
96	Badheri	20587.50
97	Faridpur	16787.50
98	Garhi Gujran	62037.50
99	Ghisarpuri	7587.50
100	Kalheri	78175.00
101	Raj Pur	212407.91
102	Jattol	173987.21
103	Sidhana	259161.23
104	Kachroli	150823.50
105	Baholi	9031.25
106	assan Kalan	141650.77
107	Sutana	174438.13
108	Israna	136681.00
109	Brahman Majra	142600.00
110	Ghmrara	254340.00
111	Bandh	389530.00
112	Puthar	214516.00

113	Mandi	491495.00
114	Burana Lakhu	415657.00
115	Didwari	113298.00
116	Palri	154883.00
117	Ratti Pur	109115.00
118	Urlana	157130.00
119	Nohra	204288.00
120	Bhandar	264438.00
121	Kabri	112052.00
122	Sikandarpur	132484.00
123	Sodan Pur	76724.00
124	Taraf Raj Putan	37626.00
125	Mohamad Pur	138144.00
126	Faridpur	27730.00
127	Taraf Ansar	165178.00
128	Siwah	59091.00
129	Nizam Pur	2897.50
130	Dhandhar	13651.87
131	Mamounda	42330.85

132	Jondhan Khurd	157235.14
133	Kakoda	263808.14
134	Wazir Pur Patiana	42722.88
135	Naultha	445646.74
136	Pehladpur Khalila	10443.76
137	Jandhana Kalan	90250.53
138	Kalkha	33978.47
139	Diwana	86120.73
140	Bajwa	16300.61
141	Naraoma	125187.64
142	Hartari	9611.94
143	Balana	351365.23
144	Busham	114817.99
145	Gawalra	226229.98
	Total	16656000.60
DISTRICT FARIDABAD		
1	Mobiapur	23395.00
2	Hirapur	94454.00

3	Sahupur	8830.00
4	Chhinsa	53725.00
5	Naryala	20975.00
6	Narhauli	59740.300
7	Mothuka	74680.00
8	Atali	60345.00
9	Arwa	18730.00
10	Majpur	32585.00
11	Korali	17535.00
	Total	379985.00
DISTRICT HISSAR		
1	Sman	338727.10
2	Nangli	360501.85
3	Nangla	63697.50
4	Gajuwala	277130.00
5	Chittan	54249.25
6	Pirthala	138431.45
7	Parta	114966.80
8	Bhekhpura	15158.05

9	Narnaund	329246.40
10	Pattan	9725.00
11	Tokas	3964.00
12	Pinhar Chak	11966.47
13	Bhariyan	6630.00
14	Bhiwnai Rohillan	12126.00
15	Chaudhriwas	68587.71
16	Dabra	28171.95
17	Mirkan	34238.69
18	Sarsana	21385.00
	Total	1891903.32
DISTRICT MOHINDERGARH		
1	Nangal Nunia	10312.33
2	Udepur kataria	3914.59
3	Budhwal	90355.81
4	Banihari	63164.88
5	Amarpura	52252.34
6	Thanwas	35587.35

7	Bhojawas	2602.09
8	Nangal pipa	16579.90
9	Chapra Bibipur	10680.13
10	hassanpur	104347.66
11	Dhani Bhathotha	44532.42
12	Kanwi	52071.06
13	Rambass	281899.44
14	Biharipur	12186.37
15	Jainpur	17840.01
16	Kamania	37459.71
17	Meghot Halla	27080.72
18	Meghot Binja	33843.89
19	Sheoramanathapura	41665.83
20	Tataheri	111023.47
21	Tanwas	26568.52
22	Udaipur Katiaria	4397.73
23	Banhari	50.00
24	Budhwal	91.72
25	Amarpur	3114.11

26	Nangal Lunia	10172.54
27	Rambass	224.75
28	Rasulpur	13809.63
29	Dhani Bhathotha	2008.12
30	Patikara	4086.87
31	Bargaon	37566.01
32	Koriyawas	99800.73
33	Nangal pipa	108.43
34	Kamania	134.60
35	Jainpur	2077.84
36	Tothiheri	2152.49
37	Bassai	80122.92
38	Rajawas	185167
39	Balana	1694.00
40	Ushampur	807.98
41	Zerpur	1680.68
42	Mandola	1306.00
43	Dholi	142.00
44	Pali	4111.74

45	bawana	4314.00
46	Sehlang	10182.00
47	Siana	4305.00
48	Notana	22818.95
49	Dulhera Khurd	71806.81
50	Nagal Sahabajpur	21470.00
51	Nagal Parshopr	30552.00
52	Dharchana	31000.00
53	Patuhera	14450.00
54	Nangal Ugra	24445.00
55	Nangal Teju	23640.00
56	Dulhera Kalan	76915.00
57	Khera murar	25925.00
58	Shaidpur Jaitpur	10279.00
59	Bishanpur	11545.00
60	Raipur	12510.00
61	Sahpur	29275.00
62	Sheri Dalusingh	9655.00
63	Raghuna Thpur	7615.00

64	Sekhpur	17025.00
65	Tihara	59596.00
66	Bawal	88382.00
67	Banipur	21514.00
68	Gujar Majri	1825.00
69	Manglashar	7520.00
70	Bethta	16955.00
71	Kamalpur	5280.00
72	Ibarahimpur	10345.00
73	Kheri Dharchanana	9080.00
74	Bhagwanpur	2790.00
	Total	641395.81
DISTRICT SIRSA		
1	Ellenabad	545517.00
2	Dani Jatan	606404.00
3	Thobri	410152.00
4	Talwara Khuri	339460.00
5	Fatehpur Hiamat Khan	27532.00
6	Joharanali	19929.00

7	Khari Surera	312340.00
8	Keram Sana	456635.00
9	Barwala Khurd	29220.00
10	Amitsar	104119.50
11	Mithi Surera	44325.00
12	Jiwan Nagar	80570.00
13	Harni Khurd	339140.00
14	Sia Paul	293035.00
15	Bani	2112970.00
16	Kariwala	492840.00
17	Darawala	19614.00
18	Dhrolawali	83229.00
19	Balasar	8051.85
20	Mamran	150910.00
21	Mithan Pur	802350.00
22	Dhoulparia	560.00
23	Jutanwali	169800.00
24	Lohgarh	451565.00
25	Abubsher	519200.00

26	Jandwala Jattan	56750.00
27	Nuian Wali	196825.00
28	Chukawali	53425.00
29	Jubgra	92025.00
30	Mithri	68535.00
31	Coutala	2440140.00
32	Taja Khera	474425.00
33	Sukhera Khera	65900.00
34	Jandwala Bishnoian	55350.00
35	Bharu Khera	229650.00
36	Asa Khera	427925.00
37	Nather	950190.00
38	Bachar	528515.00
39	Kaluana	601770.00
DISTRICT BHIWANI		
1	Satnali	8880.00
2	Surati Jakhad	83961.00
3	Dhana	15633.00
4	Sureti Mandian	1240.00

5	Dhani Lakshman	110375.00
6	Digawana Samiyana	50160.00
7	Sureti Pilaniyan	48625.00
8	Sahar	5717.00
9	Singhani	16435.00
10	Diganwan Jattan	122570.00
11	Amirwas	5014.00
12	Mohmad Nagar	12230.00
13	Dhana Jangi	23235.00
14	Pahadi	336070.00
15	Kundal	368475.00
16	Kharkadi	271830.00
17	Budhadi	1530.00
18	Bahalu	7127.00
19	Alaudinpur	74700.00 1575000.00
20	San	3405.62
21	Rewadi	20181.83
22	Phulpura	23401.48

23	Ajitpura	27516.43
24	Titani	15400.00
25	Hatampura	71699.94
26	Bhangarh	77249.61
27	Lohani	177009.43
28	Sarsa	5166.00
29	Katlan	44556.50
30	Jui Khurd	65168.75
31	Dhani Brahaman	29520.00
32	Golagarh	24239.50
33	Davsar	16623.73
34	Bhakhda	42482.00
35	Rajgarh	3331.93
36	Ghirana	8205.09
37	Mitathal	29466.10
38	Dhardu	86216.98
39	Dinod	3098.71
40	Pokarwas	34275.65
41	Lalawas	20775.50

42	Juidalan	56597.59
43	Kohad	8796.66
44	Bijna	1946.20
45	Maneharu	90169.15 986499.87
46	Pur	142244.00
47	Ghnana	14048.00
48	Talu	7946.00
49	Siwada	7006.00 171244.00
	Grand Total	2732733.87
50	Barsana	17856.28
51	Kanheri	148760.82
52	Sarupgarh	7875.00
53	Kedara	99132.50
54	Mirwala	200773.75
55	Bhagwi	96467.50
56	Jinlota	238685.38
57	Bigwa	705448.77

	Grand Total 3647733.87	915000.00